

समाचार



ई-कॉपी
के लिए
QR स्कैन
करें

विकसित भारत की ओर निर्णायक कदम

रिफॉर्म एक्सप्रेस पर सवार भारत को आम बजट
2026-27 से मिली और अधिक नई ऊर्जा, नई गति...



जन-भागीदारी और सामूहिकता की भावना देश की सबसे बड़ी ताकत

आजमगढ़ हो या अनंतपुर या फिर देश में कोई और जगह, लोग एकजुट होकर कर्तव्य भाव से बड़े संकल्प सिद्ध कर रहे हैं। जन-भागीदारी और सामूहिकता की यही भावना देश की सबसे बड़ी ताकत है। वर्ष 2026 के अपने पहले 'मन की बात' कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकतंत्र में मतदान के महत्व, एआई, मिलेट्स, भारत के त्योहार संस्कृति और स्टार्टअप सहित कई विषयों पर की चर्चा। प्रस्तुत है प्रमुख अंश...

- **मतदाता बनें युवा :** मैं अपने युवा साथियों से आग्रह करूंगा कि वे 18 साल का होने पर वोटर के रूप में खुद को जरूर रजिस्टर करें। संविधान ने हर नागरिक से जिस कर्तव्य भावना के पालन की अपेक्षा रखी है इससे वो अपेक्षा भी पूरी होगी और भारत का लोकतंत्र भी मजबूत होगा।
- **स्टार्टअप :** भारत में आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इको सिस्टम बन चुका है। यह स्टार्टअप लीक से हट कर हैं। आज वे ऐसे सेक्टर में काम कर रहे हैं, जिनके बारे में 10 साल पहले तक कल्पना भी नहीं की जा सकती थी।
- **भारतीय उत्पाद हों- टॉप क्वालिटी :** हम सबका एक ही मंत्र हो क्वालिटी, क्वालिटी और सिर्फ क्वालिटी। कल से आज बेहतर क्वालिटी। हम जो भी निर्माण कर रहे हैं, उसकी क्वालिटी को बेहतर बनाने का संकल्प लें। चाहे हमारे टेक्सटाइल हों, टेक्नोलॉजी हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स पैकेजिंग भी, भारतीय प्रोडक्ट का मतलब ही बन जाए - टॉप क्वालिटी।
- **जन-भागीदारी :** आजमगढ़ में लोगों ने तमसा नदी को नया जीवन दिया, अनंतपुर में जनभागीदारी से 10 जलाशयों को जीवनदान मिला है। यह देखकर खुशी होती है कि लोग एकजुट होकर कर्तव्य भाव से बड़े संकल्प सिद्ध कर रहे हैं। जन-भागीदारी और सामूहिकता की यही भावना हमारे देश की सबसे बड़ी ताकत है।
- **युवाओं की भक्ति :** देश में भजन और कीर्तन सदियों से हमारी संस्कृति की आत्मा रही है। हमने मंदिरों में भजन सुने हैं। हर दौर ने भक्ति को अपने समय के हिसाब से जिया है। आज की पीढ़ी भी कुछ नए कमाल कर रही है। आज के युवाओं ने भक्ति को अपने अनुभव और अपनी जीवन-शैली में ढाल दिया है।
- **ईयर ऑफ फैमिली :** भारत की परिवार व्यवस्था हमारी परंपरा का अभिन्न हिस्सा है। दुनिया के कई देशों में इसे बहुत कौतूहल के साथ देखा जाता है। कई देशों में ऐसे परिवार व्यवस्था को लेकर बहुत सम्मान का भाव है। यूएई के राष्ट्रपति महामहिम शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने मुझे बताया कि यूएई साल 2026 को ईयर ऑफ फैमिली के रूप में मना रहा है।
- **एक पेड़ मां के नाम :** देशभर में 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान से आज करोड़ों लोग जुड़ चुके हैं। अब तक देश में 200 करोड़ से ज्यादा पेड़ लगाए भी जा चुके हैं। यह बताता है कि पर्यावरण संरक्षण को लेकर अब लोग ज्यादा जागरूक हैं।
- **श्रीअन्न :** मुझे यह देखकर खुशी है कि श्रीअन्न के प्रति देश के लोगों का लगाव निरंतर बढ़ रहा है। वैसे तो हमने 2023 को मिलेट इयर घोषित किया था। लेकिन आज तीन साल बाद भी इसको लेकर देश और दुनिया में जो पैशन और प्रतिबद्धता है वो बहुत उत्साहित करने वाला है।
- **एआई की दुनिया :** फरवरी महीने में इंडिया एआई इंपैक्ट समिट है। इस समिट में दुनियाभर से, विशेषकर टेक्नोलॉजी के क्षेत्र से जुड़े एक्सपर्ट भारत आएंगे। यह सम्मेलन एआई की दुनिया में भारत की प्रगति और उपलब्धियों को भी सामने लाएगा। ■





13 भाषाओं में उपलब्ध
न्यू इंडिया समाचार को पढ़ने
के लिए क्लिक करें।

<https://newindiasamachar.pib.gov.in/news.aspx>

न्यू इंडिया समाचार के पुराने
अंक पढ़ने के लिए क्लिक करें

<https://newindiasamachar.pib.gov.in/archive.aspx>



न्यू इंडिया समाचार के बारे में
लगातार अपडेट के लिए फॉलो
करें: @NISPIBIndia

अंदर के पन्नों पर...



बीते 11 वर्षों में केंद्र सरकार ने विकसित भारत के संकल्प को सिद्ध करने का आधारस्तंभ तैयार किया है, अब वर्ष 2026-27 का बजट बन रहा है विकसित भारत के निर्णायक संकल्प और संकल्प से सिद्धि का प्रतीक। अमृत यात्रा की ओर बढ़ते कदम के साथ यह आम बजट भी बन गया है विकास, विश्वास और भविष्य की त्रिवेणी को साकार करने वाला आत्मनिर्भर भारत का सशक्त बजट... | 16-36



तनाव पर चर्चा और परीक्षाओं को त्योहार की तरह मनाने के उद्देश्य से 2018 में शुरू 'परीक्षा पे चर्चा' कार्यक्रम हर साल कर रहा है नया आयाम तय... 8-11

पद्म सम्मान 2026



पीपुल्स पद्म की वास्तविक भावना के अनुरूप नई परंपरा
निष्काम कर्मयोगियों
को पद्म सम्मान

देश में सकारात्मक ऊर्जा का संचार और मानवता की सेवा करने वाले गुमनाम नायकों को भी मिल रहे हैं अब पद्म सम्मान... 37-39

समाचार सार

व्यक्तित्व : बुधु भगत

लरका विद्रोह के महानायक

केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णय

अटल पेंशन योजना 2030-31 तक बढ़ी

राष्ट्रपति का अभिभाषण

सुशासन को और सुदृढ़ करने की सामूहिक प्रतिबद्धता

केरल से 'विकास की, रोजगार निर्माण की' नई पहल

पीएम स्वनिधि क्रेडिट कार्ड लॉन्च के साथ कई पहल

...ताकि संत परंपरा और विरासत से जुड़ी रहे भावी पीढ़ी

नामकरण... 'श्री गुरु रविदास महाराज जी हवाई अड्डा, आदमपुर'

विंग्स इंडिया 2026

भारत में हवाई यात्रा अब चुनिंदा नहीं, आमजन तक

16वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस

लोकतंत्र की वैश्विक आवाज

राष्ट्र निर्माण का निर्मंत्रण पत्र

रोजगार मेले में सौंपे गए सरकारी सेवा के 61 हजार नियुक्ति पत्र

पराक्रम दिवस

राष्ट्रीय चेतना का उत्सव

आत्मविश्वासी-अनुशासित युवा शक्ति

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वार्षिक एनसीसी पीएम रैली को किया संबोधित | 52-53

भारत ऊर्जा सप्ताह 2026

सिर्फ ऊर्जा सुरक्षा नहीं, अब आत्मनिर्भरता का मिशन

यूएई के राष्ट्रपति की भारत यात्रा

रणनीतिक साझेदारी से विकास को रफ्तार

भारत-ईयू मुक्त व्यापार समझौता

भारत-यूरोपीय यूनियन रिश्तों में नए युग का शंखनाद

संपादक की कलम से...

केंद्रीय बजट 2026-27

विकसित भारत की नींव पर आधारित जन-जन का बजट

सादर नमस्कार।

1 फरवरी 2026 को प्रस्तुत केंद्रीय बजट 2026-27 विकसित भारत 2047 की यात्रा को गति देने वाला एक दूरदर्शी और समावेशी बजट है। आज भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। यह बजट भारत को विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इस बजट में आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने के लिए तमाम प्रवाधान किए गए हैं।

2026-27 के आम बजट में तीन कर्तव्यों का वर्णन है जिसमें आर्थिक विकास की गति को तेज करना पहला कर्तव्य बताया गया है। इसके तहत भारत को वैश्विक बायोफार्मा विनिर्माण केंद्र के रूप में विकसित करना हो या इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 की शुरुआत करना, भारत सरकार लगातार देश की उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए कार्यरत है। आम बजट 2026-27 में इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैनुफैक्चरिंग स्कीम को गति देने के लिए बजट बढ़ाकर 40 हजार करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव है। खनन, प्रसंस्करण, अनुसंधान और विनिर्माण को प्रोत्साहन देने के लिए समर्पित रेयर अर्थ कॉरिडोर की स्थापना का भी प्रस्ताव है। रसायन जगत में आत्मनिर्भरता के लिए तीन केमिकल पार्क स्थापित करने, 5 वर्ष की अवधि में दस हजार करोड़ रुपये के बजट आवंटन के साथ कंटेनर विनिर्माण योजना लाने का भी प्रस्ताव किया गया है।

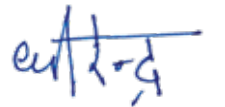
इस बजट में जन-आकांक्षाएं पूरी करने और क्षमता बढ़ाने को दूसरा कर्तव्य बताया गया है। इसमें युवा शक्ति को केंद्र में रखकर रोजगार सृजन, कौशल विकास और

क्षमता निर्माण पर भी विशेष जोर दिया गया है। बजट में भारत विस्तार एआई टूल जैसे प्रावधानों से किसानों को भी लाभान्वित करने पर बल दिया गया है। नारी शक्ति के सशक्तीकरण और महिला SHGs उत्पादों को सुगम बाजार मिले, इसलिए SHE मार्ट स्थापना का प्रस्ताव है। बजट में ऑरेंज इकोनॉमी और कंटेंट क्रिएशन को बढ़ावा देने के लिए 15,000 स्कूलों और 500 कॉलेजों में AVGC कंटेंट क्रिएटर लैब की स्थापना की बात भी की गई है।

बजट में सबका साथ-सबका विकास के दृष्टिकोण के अनुरूप-किसानों की आय बढ़ाने, दिव्यांगजनों के सशक्तीकरण, मानसिक स्वास्थ्य और ट्रॉमा केयर पर ध्यान देने, पूर्वोदय और उत्तर-पूर्व क्षेत्र को और समृद्ध करना तीसरा कर्तव्य बताया गया है। बजट 2026-27 ही इस बार हमारी आवरण कथा बनी है।

व्यक्तित्व की कड़ी में लरका विद्रोह के महानायक बुधु भगत, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु का संसद में अभिभाषण, पद्म सम्मान 2026, केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णय, परीक्षा पे चर्चा का 9वां संस्करण सहित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पखवाड़े भर के कार्यक्रमों को इसमें शामिल किया गया है। साथ ही, पत्रिका के इनसाइड पेज पर मन की बात और बैंक कवर पर बीटिंग रिट्रीट समारोह पर विशेष सामग्री समाहित है।

आप अपना सुझाव हमें भेजते रहें।


(धीरेन्द्र ओझा)



हिंदी, अंग्रेजी व अन्य 11 भाषाओं में उपलब्ध पत्रिका पढ़ें/डाउनलोड करें।

<https://newindiasamachar.pib.gov.in/news.aspx>

आपकी बात...



योजना और उपलब्धियों की मिलती है तथ्यात्मक जानकारी

मैं नियमित रूप से न्यू इंडिया समाचार पत्रिका पढ़ता हूँ। इसमें हमें सरकारी योजना और उपलब्धियों की तथ्यात्मक जानकारी मिलती है। साथ ही यह करेंट अफेयर्स जानने के लिए बहुत उपयोगी है। यह मैगजीन समाज के अलग-अलग तबकों से जुड़े कई विषयों पर काम की जानकारी देती है।

श्रीनिवास उरगोंडा

srinivasuragonda7@gmail.com

डेवलपमेंट एक्टिविटी के बारे में मिलती है जानकारी

न्यू इंडिया समाचार पत्रिका देश में चल रही सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम और प्रोग्राम के बारे में जानकारी पाने का एक शानदार माध्यम है। यह एक शानदार पत्रिका है। मेरे लिए पत्रिका देश में चल रहे विकास कार्यों और योजना के बारे में जानने का माध्यम है।

mhqchoutuppal@gmail.com

सरकारी नीति और विकास पहल के विषय में समझ बढ़ती है

विशेष और महत्वपूर्ण जानकारी देने वाली पत्रिका प्रकाशित करने के लिए न्यू इंडिया समाचार की पूरी टीम को धन्यवाद देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि नागरिकों को अच्छी तरह से जानकारी देने की कोशिशों में आपको लगातार सफलता मिले। पत्रिका पढ़ने से युवाओं में सरकारी नीति और देश के विकास के लिए की जा रही पहल की समझ बढ़ती है।

thirubjp2020@gmail.com

विविध विषयों पर ज्ञानवर्धक आलेख

मैं एक पत्रकार हूँ। न्यू इंडिया समाचार पत्रिका पढ़ना मुझे बहुत ही पसंद है। इस पत्रिका में विविध विषयों पर ज्ञानवर्धक आलेख प्रकाशित होते हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए न्यू इंडिया समाचार पत्रिका उपयोगी है। यह पत्रिका बहुत अच्छे ढंग से डिजाइन की गई है।

urvaadhvaryu@gmail.com

हर अंक होता है संकलन योग्य

मैंने न्यू इंडिया समाचार पत्रिका का तमिल एडिशन देखा। पढ़ने पर यह आम जनता के लिए काफी उपयोगी लगी। यह पत्रिका अति उत्तम जानकारियाँ से भरपूर है। इसका हर अंक संकलन योग्य होता है।

डी. थंगादुरई

thesiyareporter2023@gmail.com



नया आधार एप लॉन्च, पांच प्रोफाइल जोड़ सकेंगे

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने नया मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। यह एप आधार धारकों को अपनी डिजिटल पहचान को सुरक्षित, सुविधाजनक और गोपनीय तरीके से ले जाने, साझा करने, दिखाने और सत्यापित करने के लिए डिजाइन किया गया है। एप के माध्यम से एक ही मोबाइल में अधिकतम पांच आधार प्रोफाइल जोड़े जा सकते हैं, जिससे 'एक परिवार-एक एप' की अवधारणा साकार हुई है। नया एप डेटा के न्यूनतम उपयोग को बढ़ावा देने, सुरक्षा बढ़ाने के साथ ही देगा कई अन्य सुविधाएं:

- आधार नंबर धारकों द्वारा चुनिंदा जानकारी साझा करने को प्रोत्साहित करेगा।
- एप में ऑफ लाइन वेरिफिकेशन सीकिंग एंटीटी के क्यूआर कोड स्कैनिंग के जरिए होटल चेक-इन शामिल। एप में वैकल्पिक चेहरे के सत्यापन, सिनेमा टिकट बुकिंग के लिए आयु सत्यापन, आगंतुकों और परिचारकों के लिए अस्पताल में प्रवेश, गिग वर्कर्स और सेवा भागीदारों के सत्यापन जैसे उपयोग को जोड़ा गया है।
- एप में उपस्थिति प्रमाण के लिए चेहरे की पुष्टि, एक क्लिक में बायोमेट्रिक लॉक/अनलॉक, प्रमाणीकरण इतिहास देखना और संपर्क विवरण साझा करने के लिए क्यूआर-कोड आधारित सुविधाएं भी शामिल हैं।
- पते के अपडेट के अलावा, निवासी अब एप के माध्यम से अपना पंजीकृत मोबाइल नंबर भी अपडेट कर सकते हैं।



मखाना बना ग्लोबल ब्रांड दुबई भेजी गई पहली समुद्री खेप

भारत मखाना का सबसे बड़ा उत्पादक है, जो वैश्विक उत्पादन में 80% की हिस्सेदारी रखता है। इसमें बिहार, राष्ट्रीय मखाना उत्पादन में 85 फीसदी का योगदान देता है। इससे 10 लाख किसानों की आजीविका जुड़ी हुई है। इसी कड़ी में बिहार के पूर्णिया से जीआई टैग प्राप्त मिथिला मखाना की दुबई के लिए पहली समुद्री खेप भेजी गई है। निर्यात के जरिए किसानों की आय बढ़ाने और एफपीओ को सशक्त करने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है। मिथिला मखाना ने वैश्विक मंच पर भारत की कृषि और संस्कृति की पहचान को मजबूत किया है। दरभंगा मखाना के प्रमुख केंद्रों में से एक है जिसे मखाना के लिए 'एक जिला, एक उत्पाद' पहल के तहत मान्यता भी दी गई है। मिथिला मखाना को जीआई टैग भी मिला है। केंद्र सरकार ने मखाना के उत्पादन, प्रोसेसिंग, मूल्यवर्धन, मार्केटिंग और निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए 2025 में मखाना बोर्ड की स्थापना की है। 476 करोड़ रुपये के खर्च वाली मखाना विकास की केंद्रीय योजना को मंजूरी भी दी है। केंद्र सरकार ने निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एक अलग एचएसएन कोड निर्मित किया है।



एयरफोर्स स्टेशन लेह में नागर विमानन इंफ्रास्ट्रक्चर होगा विकसित

केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के एयरफोर्स स्टेशन लेह में नागर विमानन इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित करने के लिए उपराज्यपाल कविंदर गुप्ता ने एक परियोजना का उद्घाटन किया। बेहद चुनौतीपूर्ण ऊंचाई वाले क्षेत्र और प्रतिकूल मौसम की स्थिति के बावजूद बुनियादी ढांचे का रिकॉर्ड समय में उन्नयन किया गया है। विकसित किया गया इंफ्रास्ट्रक्चर विमानों की आवाजाही को आसान बनाने के साथ-साथ नागरिक उड़ानों के प्रस्थान को तेज करेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर की इस परियोजना से लेह में बेहतर वायु संपर्क पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। मानवीय सहायता और आपदा राहत की स्थिति में भी इससे मजबूती मिलेगी।

सहकार से समृद्धि: “भारत टैक्सी” का शुभारंभ

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘सहकार से समृद्धि’ के विजन के अनुरूप केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने पांच फरवरी 2026 को नई दिल्ली में भारत के पहले सहकारिता-आधारित राइड-हेलिंग प्लेटफॉर्म “भारत टैक्सी” का शुभारंभ किया। भारत टैक्सी दुनिया का पहला और सबसे बड़ा सहकारिता-आधारित राइड-हेलिंग प्लेटफॉर्म है। अब तक करीब चार लाख ड्राइवर इससे जुड़ चुके हैं और दस लाख से अधिक उपयोगकर्ता पंजीकृत हो चुके हैं। लगभग 10 करोड़ की राशि अब तक सीधे ड्राइवरों में वितरित की जा चुकी है। भारत टैक्सी से अब सिर्फ सफर ही पूरा नहीं होगा बल्कि सुविधा, सुरक्षा और सशक्तीकरण का नया अनुभव भी प्रदान करेगा। साथ ही इसमें नॉन-एसी टैक्सी का विकल्प और मेट्रो टिकट बुकिंग सुविधा भी होगी। इसके अलावा 100% किराया ड्राइवर की जेब में जाएगा। भारत टैक्सी शुभारंभ के दौरान सहकारिता-आधारित मोबिलिटी इकोसिस्टम में उत्कृष्ट योगदान के लिए शीर्ष छह प्रदर्शन करने वाले सारथियों को सम्मानित किया गया। केंद्रीय मंत्री ने इन सारथियों को शेयर प्रमाणपत्र वितरित किया, जिससे “सारथी ही मालिक” के मूल सिद्धांत को और अधिक मजबूती मिलेगी। प्रत्येक सारथी को 5 लाख रुपये का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा और 5 लाख का पारिवारिक स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया गया।



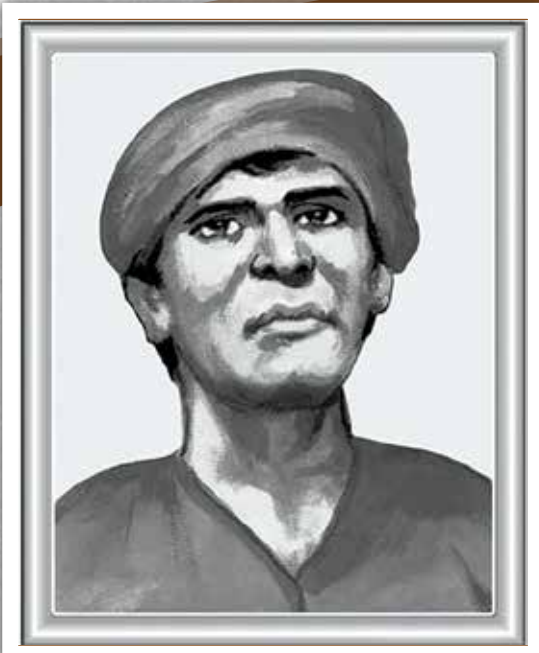
पीएमजीएसवाई-IV में 10 हजार किमी की सड़क परियोजनाओं को मंजूरी

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) IV में जम्मू-कश्मीर, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम के लिए 10 हजार किलोमीटर से अधिक की सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। इन परियोजनाओं के पूरा होने पर पहले से अलग-थलग पड़े लगभग 3,270 बस्तियों को कनेक्टिविटी और आवश्यक सेवाओं तक पहुंच प्राप्त होगी। ऊंचे पहाड़ी क्षेत्र से लेकर ग्रामीण समुदायों के मध्य तक फैली यह सड़कें मात्र इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार नहीं, बल्कि यह प्रगति के लिए महत्वपूर्ण मार्ग हैं। इस योजना का उद्देश्य बस्तियों को 62,500 किलोमीटर लंबी, हर मौसम में उपयोग योग्य सड़कें उपलब्ध कराना है जो अभी तक आपस में जुड़ी नहीं हैं। वित्त वर्ष 2028-29 तक 70,125 करोड़ रुपये इन परियोजनाओं पर खर्च होने का अनुमान है।

अंतरराष्ट्रीय राम कथा संग्रहालय में दिखेगी 233 साल पुरानी वाल्मीकि रामायण

केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर श्रीनिवास वरखेड़ी ने तीन मूर्ति स्थित प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय की कार्यकारी परिषद के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र को वाल्मीकि रामायण (तत्त्वदीपिका टीका सहित) की 233 वर्ष पुरानी संस्कृत की एक दुर्लभ पांडुलिपि सौंपी। यह पांडुलिपि संस्कृत (देवनागरी लिपि) में लिखी गई है। यह विक्रम संवत् 1849 (1792 ईस्वी) की कृति है। रामायण की एक दुर्लभ सुरक्षित पाठ परंपरा का प्रतिनिधित्व करती है। इस पांडुलिपि को उत्तर प्रदेश के अयोध्या में अंतरराष्ट्रीय राम कथा संग्रहालय को स्थायी रूप से उपहार में दिया गया है। आम जनता तक इसकी व्यापक पहुंच के साथ इसका संरक्षण सुनिश्चित होगा। नृपेंद्र मिश्र ने कहा, “वाल्मीकि रामायण की इस दुर्लभ पांडुलिपि का अयोध्या स्थित राम कथा संग्रहालय को दान, राम भक्तों और अयोध्या स्थित मंदिर परिसर के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है।”





■ जन्म : 17 फरवरी 1792 ■ मृत्यु : 13 फरवरी 1832

लरका विद्रोह के महानायक

लरका विद्रोह के नेतृत्वकर्ता तथा स्वाधीनता के स्वप्नद्रष्टा वीर बुधु भगत ने अंग्रेजों तथा साहूकारों के विरुद्ध युद्ध छेड़ा और गुरिल्ला युद्ध करते हुए आजादी की लड़ाई लड़ी। उन्होंने चौरैया, पिठौरिया, लोहरदगा और पलामू क्षेत्र में लोगों को ब्रिटिश शासन से आजाद होने के लिए जागरूक किया। शोषण एवं अत्याचार के खिलाफ संघर्ष किया। वह कई वर्षों तक अंग्रेजों को जंगलों से खदेड़ते रहे और आदिवासियों को अन्याय के खिलाफ लड़ना सिखाया। साहस और प्रतिरोध के प्रतीक बुधु भगत की वीरता और बलिदान हमेशा करती रहेगी प्रेरित...

लरका विद्रोह की चिंगारी भड़काने वाले प्रसिद्ध क्रांतिकारी बुधु भगत ऐसे क्रांतिकारी थे जिन्होंने एक कुल्हाड़ी लेकर ब्रिटिश सरकार की तोपों और बंदूकों का मुकाबला किया। झारखंड के रांची जिले में सिलागाई गांव के एक उरांव परिवार में 17 फरवरी 1792 को जन्मे बुधु भगत के बारे में कहा जाता है कि उन्हें दैवीय शक्तियां प्राप्त थीं, जिसके प्रतीकस्वरूप वे एक कुल्हाड़ी हमेशा अपने साथ रखते थे। बुधु भगत की संगठन क्षमता को देखकर लोग उन्हें देवता का अवतार समझते थे। उन्होंने सिल्ली, चोरेया, पिठौरिया, लोहरदगा और पलामू में भी संगठन का काम किया था।

कुशल संगठनकर्ता के साथ-साथ उन्होंने अपने दस्ते को गुरिल्ला युद्ध के लिए प्रशिक्षित किया। घने जंगलों और दुर्गम पहाड़ियों का फायदा उठा कर कई बार अंग्रेजी सेना को उन्होंने परास्त किया। वे बचपन से ही तलवारबाजी और धनुर्विद्या का अभ्यास करते थे। उन्होंने अंग्रेजों के चाटुकार जमींदारों, दलालों के विरुद्ध भूमि और वन सुरक्षा के लिए भी जंग छेड़ी थी। इतना ही नहीं, अपने साहस और नेतृत्व क्षमता के दम पर उन्होंने आदिवासी इलाकों में अंग्रेजी हुकूमत की बर्बरता के खिलाफ लरका विद्रोह का सूत्रपात कर हथियारबंद विद्रोह का भी नेतृत्व किया था।

कहा जाता है कि बुधु भगत का छोटानागपुर के रांची और

आसपास के इलाके पर जबरदस्त असर था। लोग उनके एक इशारे पर अपनी जान तक देने के लिए तैयार रहते थे। बुधु भगत का सैनिक अड्डा चोगारी पहाड़ की चोटी पर घने जंगलों के बीच था और रणनीति बनाने का काम यहीं पर होता था। एक समय ऐसा भी आया, जब उनकी वीरता और साहस से तंग आकर अंग्रेजों ने उन्हें पकड़ने के लिए एक हजार रुपये के इनाम की घोषणा की थी जो उस जमाने में बहुत बड़ी राशि थी।

13 फरवरी, 1832 को बुधु और उनके साथियों को कैप्टन इंपे ने सिलागाई गांव में घेर लिया। बुधु आत्मसमर्पण करना चाहते थे, क्योंकि अंग्रेजों की ओर से हो रही अंधाधुंध गोलीबारी में निर्दोष ग्रामीण न मारे जाएं। लेकिन बुधु भगत के अनुयायियों ने वृत्ताकार सुरक्षा कवच बना लिया। इस बीच अंग्रेजी कैप्टन ने गोली चलाने का आदेश दे दिया। अंधाधुंध गोलियां चलने लगीं और बूढ़े, बच्चों, महिलाओं एवं युवाओं के भीषण चीत्कार से इलाका कांप उठा। उस खूनी तांडव में करीब 300 ग्रामीण मारे गए। अन्याय के विरुद्ध जन विद्रोह को हथियार के बल पर जबरन खामोश कर दिया गया। बुधु भगत तथा उनके बेटे हलधर और गिरधर भी अंग्रेजों से लोहा लेते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। आज भी लोग अपनी लोक कथाओं और लोक गीतों में वीर बुधु भगत और उनके सहयोगियों को याद करते हैं। यह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम ने उनके योगदान और लोकप्रियता को दर्शाता है। ■

अटल पेंशन योजना 2030-31 तक बढ़ी सिडबी को मिलेंगे 5,000 करोड़ रुपये

असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के कल्याण के लिए केंद्र सरकार प्रतिबद्ध है। इसी कड़ी में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए अटल पेंशन योजना को 2030-31 तक जारी रखने की मंजूरी दी है। इससे निम्न-आय वर्ग और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए वृद्धावस्था आय सुरक्षा सुनिश्चित होगी। साथ ही, सिडबी को 5,000 करोड़ रुपये की इक्विटी सहायता के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है जिससे कई एमएसएमई को होगा फायदा...

निर्णय : अटल पेंशन योजना (एपीवाई) को वित्त वर्ष 2030-31 तक जारी रखने की मंजूरी।

प्रभाव : अटल पेंशन योजना में 19 जनवरी, 2026 तक, 8.66 करोड़ से अधिक ग्राहक नामांकित हो चुके हैं, जिससे यह योजना भारत के समावेशी सामाजिक सुरक्षा ढांचे की एक आधारशिला बन गई है। एपीवाई 60 वर्ष की आयु से शुरू होकर, अंशदान के आधार पर, प्रति माह 1,000 रुपये से 5,000 रुपये तक की गारंटीकृत न्यूनतम पेंशन प्रदान करता है। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को वृद्धावस्था आय सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से एपीवाई 9 मई, 2015 को शुरू की गई थी।

प्रमुख प्रभाव:

- यह लाखों निम्न-आय वर्ग और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए वृद्धावस्था आय सुरक्षा सुनिश्चित करता है।
- यह वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देता है। भारत के पेंशन-आधारित समाज में परिवर्तन का समर्थन करता है।
- सतत सामाजिक सुरक्षा प्रदान करके विकसित भारत@2047 के दृष्टिकोण को मजबूत बनाता है।

जागरूकता और क्षमता निर्माण में सरकार करेगी सहयोग

- असंगठित श्रमिकों के बीच पहुंच बढ़ाने के लिए प्रचार और विकासात्मक गतिविधियां, जिनमें जागरूकता और क्षमता निर्माण शामिल हैं।
- योजना की व्यवहार्यता संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने और उसकी स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक धनराशि का आवंटन।



कैबिनेट के फैसलों पर प्रेस ब्रीफिंग देखने के लिए QR कोड स्कैन करें।



निर्णय : भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) को 5,000 करोड़ रुपये की इक्विटी सहायता को मंजूरी।

प्रभाव : 5,000 करोड़ रुपये की इक्विटी पूंजी निवेश के बाद वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाले एमएसएमई की संख्या वित्त वर्ष 2025 के अंत में 76.26 लाख से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2028 के अंत तक 1.02 करोड़ (अर्थात लगभग 25.74 लाख नए एमएसएमई लाभार्थी जोड़े जाएंगे) होने की उम्मीद है।

- एमएसएमई मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट से उपलब्ध नवीनतम आंकड़ों (30.09.2025 तक) के अनुसार, 6.90 करोड़ एमएसएमई (अर्थात प्रति एमएसएमई औसतन 4.37 व्यक्तियों का रोजगार सृजन) द्वारा कुल 30.16 करोड़ लोगों को रोजगार प्रदान किया गया है।
- इस औसत को ध्यान में रखते हुए वित्तीय वर्ष 2027-28 के अंत तक अनुमानित 25.74 लाख नए एमएसएमई लाभार्थियों के जुड़ने से लगभग 1.12 करोड़ नए रोजगार के सृजन का अनुमान है। ■



संवाद से सफलता

9वां संस्करण

परीक्षा पे
चर्चा 2026

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मंत्र अपने पैटर्न पर रखें पूरा भरोसा

तनाव पर चर्चा करने और परीक्षाओं को एक त्योहार की तरह मनाने के उद्देश्य से साल 2018 में शुरू किया गया 'परीक्षा पे चर्चा' कार्यक्रम हर साल नया आयाम तय कर रहा है। इस साल भी छात्र-छात्राओं के मन से परीक्षा का डर दूर करने और उन्हें सफलता का मंत्र सिखाने के लिए अनोखे और व्यापक अंदाज में परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 6 फरवरी को 'परीक्षा पे चर्चा' के 9वें संस्करण में पीएम मोदी ने छात्रों को दिए महत्वपूर्ण मंत्र और कई विषयों पर की चर्चा...

छात्रों को गुरु पीएम मोदी का मंत्र

पैटर्न पर करें भरोसा : आप अपना जो पैटर्न है, उस पर पूरा भरोसा करो। लेकिन जो पैटर्न के लिए सुझाव देते हैं, उसको ध्यान से सुनें, समझने की कोशिश करें। उसमें आपको लगता है कि मेरा पैटर्न तो है लेकिन यह चीज मैं अगर जोड़ दूँ तो अच्छा होगा। लेकिन किसी के कहने पर मत जोड़ो, अपने अनुभव से जोड़ो। अब जैसे परीक्षा पे चर्चा मैंने जब शुरू की, तब एक पैटर्न था। अब धीरे-धीरे मैं उसमें इंप्रूव करता जा रहा हूँ।

दो प्रकार के स्किल : स्किल में भी दो प्रकार के स्किल हैं। एक है, लाइफ स्किल। दूसरा है, प्रोफेशनल स्किल। उसमें भी कोई मुझे पूछेगा कि साहब लाइफ स्किल में ध्यान देना चाहिए कि प्रोफेशनल

में? मैं कहूँगा दोनों में देना चाहिए। अब मुझे बताइए, बिना अध्ययन किए, बिना ऑब्जरवेशन किए, बिना ज्ञान प्रयुक्त किए, कोई भी स्किल आ सकता है क्या?

शिक्षा एक माध्यम : हमारी जिंदगी परीक्षा के लिए नहीं है, बल्कि शिक्षा हमारे जीवन को बनाने का एक माध्यम है। शिक्षा के लिए हम बार-बार एग्जाम देते हैं। यह जो एग्जाम है, वह हमें अपने आप को एग्जामिन करने के लिए एग्जाम है। अल्टीमेट गोल एग्जाम के नंबर नहीं हो सकते हैं। अल्टीमेट गोल संपूर्ण जीवन के विकास का होना चाहिए। मेरा तो सभी विद्यार्थियों से आग्रह है कि आप जिंदगी में सबसे ज्यादा उत्तम बनें, अपना जीवन श्रेष्ठ बनाएं, आपका पूरा जीवन शानदार रहे, उसके लिए जीवन को तैयार करना है।



असमी गमोछा

पीएम मोदी ने असमी गमोछा से छात्रों का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि इसे असमी गमोछा कहते हैं। यह सबसे बड़ी चीज है, यह मेरी सबसे प्रिय चीज है। उसकी रचना बहुत अच्छी लगती है। दूसरा है, यह असम का और खासकर के नॉर्थ ईस्ट की वूमेन एंपावरमेंट का सिंबल है। यह घर में बनाते हैं। सचमुच में वहां की मातृशक्ति, नारी शक्ति कैसे काम करती है। एक प्रकार से मन को बड़ा आदर होता है, सम्मान होता है। तो मेरा मन कर गया कि इन बच्चों को मैं आज असम का गमोछा दूंगा।



इस साल की पीपीसी में परीक्षाओं से जुड़े बहुत ही रोचक विषय शामिल हैं, खासकर तनाव मुक्त रहने की आवश्यकता, सीखने पर ध्यान केंद्रित करना और भी बहुत कुछ। यह एक ऐसा मंच है जिसे मुझे हमेशा पसंद आया है, क्योंकि इससे मुझे पूरे देश के होनहार छात्रों के साथ बातचीत करने का मौका मिलता है। - नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री



मैं बीते हुए को नहीं, बचे हुए को गिनता हूँ

छात्रों से बातचीत में पीएम मोदी ने कहा कि मुझे अभी एक नेता ने फोन किया था। मेरे जन्मदिन पर 17 सितंबर को, तो उसने मुझे कहा कि आप 75 के हो गए। तो मैंने कहा कि अभी 25 बाकी हैं। तो मैं जो बीता है, उसको गिनता नहीं हूँ। जो बचा है उसको गिनता हूँ और इसलिए जीवन में मैं आपको भी कहता हूँ। बीता है, उसकी गिनती में समय बर्बाद मत कीजिए। जो बचा है, उसको जीने के लिए सोचिए।

बनें गेम क्रिएटर: भारत के अंदर ढेरों कथा-कहानियां हैं। आपने कभी सोचा है कि पंचतंत्र पर मैं एक गेम बनाऊं, मैं गेम क्रिएटर बनूँ। आप भी अपना एक सोशल मीडिया प्रोफाइल बनाइए और आप एक या दो गेम खुद तैयार कीजिए और इन गेम को आप लॉन्च कीजिए। तो आपके घर के लोगों को लगेगा, अरे देखो इतना छोटा है, 10,000 - 20,000 इसके फॉलोअर हैं। तो आपके पास नए-

नए आइडियाज आएंगे। इसलिए गेमिंग में आपकी रुचि है, अच्छी चीज है। आप कभी भी संकोच मत कीजिए।

डायरी में लिखो: रात को आप जब सोने जाएं, उसके पहले डायरी में लिखो कि कल मुझे जो काम बिल्कुल करने ही करने हैं। ऐसे कौन से काम हैं। दूसरा फिर आज जो लिखा है, वह दूसरे दिन टैली करो,



रिकॉर्ड छात्रों ने कराया पंजीकरण

परीक्षा पे चर्चा (पीपीसी) कार्यक्रम के 9वें संस्करण में अभूतपूर्व वृद्धि देखी गई और इसके लिए 4.5 करोड़ से अधिक छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों ने मायगॉव पोर्टल के माध्यम से पंजीकरण कराया। इसमें छात्रों की संख्या 4,19,14,056, शिक्षक 24,84,259 और अभिभावक की संख्या 6,15,064 रही।



2018

पहली बार हुई बातचीत

पहली बार परीक्षा पे चर्चा 16 फरवरी, 2018 को नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में आयोजित की गई। इस कार्यक्रम में 2500 से अधिक विद्यार्थी मौजूद थे। देश भर के 8.5 करोड़ से अधिक छात्रों ने कार्यक्रम देखा।

2019

बढ़ती पहुंच

29 जनवरी, 2019 को परीक्षा पे चर्चा का दूसरा संस्करण भी नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम आयोजित किया गया, जिसमें भागीदारी का स्तर और भी अधिक बढ़ा। नब्बे मिनट से अधिक समय तक चली इस बातचीत में छात्र, शिक्षक और अभिभावक शामिल हुए।

2020

भागीदारी का विस्तार

20 जनवरी, 2020 को नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में आयोजित इस कार्यक्रम के लिए 2.63 लाख प्रविष्टियां प्राप्त हुईं। देश और विदेश में रहने वाले 25 देश के भारतीय छात्रों ने इसमें भाग लिया।

2021

वर्चुअल संपर्क

कोविड-19 महामारी के कारण, पीपीसी का चौथा संस्करण 7 अप्रैल 2021 को ऑनलाइन आयोजित किया गया।

2022

5वें संस्करण का आयोजन

1 अप्रैल 2022 को तालकटोरा स्टेडियम, नई दिल्ली में परीक्षा पे चर्चा के 5वें संस्करण में पीएम मोदी ने छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों से बातचीत की। 9,69,836 छात्रों, 47,200 शिक्षकों और 1,86,517 अभिभावकों ने परीक्षा पे चर्चा-2022 का सीधा प्रसारण देखा।

2023

संख्या बढ़ी

27 जनवरी 2023 को परीक्षा पे चर्चा का छठा संस्करण तालकटोरा स्टेडियम में आयोजित किया गया। 7,18,110 छात्र, 42,337 शिक्षकों और 88,544 अभिभावकों ने सीधा प्रसारण देखा।

2024

राष्ट्रव्यापी भागीदारी

29 जनवरी 2024 को सातवां संस्करण भारत मंडपम में आयोजित। कार्यक्रम के लिए MyGov पोर्टल पर 2.26 करोड़ पंजीकरण। इसमें छात्रों, शिक्षकों, अभिभावकों और कला उत्सव के विजेताओं सहित लगभग 3,000 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

2025

बातचीत में कई विषयों पर चर्चा

10 फरवरी 2025 को नए फॉर्मेट में नई दिल्ली की सुंदर नर्सरी में परीक्षा पे चर्चा का 8वां संस्करण आयोजित। पीएम मोदी ने छात्रों के साथ कई विषयों पर चर्चा की। उन्होंने छात्रों को तिल से बनी मिठाइयां वितरित की।

हुआ कि नहीं हुआ और टिक मार्क करो कि कल मैंने लिखा था कि मैं आज पांच काम करूं, लेकिन तीन ही किया तो टिक मार्क करो, दो रह गए। फिर सोचो यह दो क्यों रह गए? जीवन में अगर टाइम मैनेजमेंट सीख लिए और समय का प्रोडक्टिव यूज सीख लिया, तो

देखिए आपको कभी भी प्रेशर नहीं लगेगा। थकान नहीं लगेगी। अब जैसे मैं हूं, इतने सारे काम होते हैं लेकिन मुझे टेंशन नहीं है क्योंकि मुझे बहुत पहले से ही एक प्रकार से समय का सही उपयोग करने की आदत बन गई।

पहली बार देश के कई स्थानों पर आयोजित हुआ पीपीसी

पहली बार, पीपीसी 2026 का आयोजन देश के सभी हिस्सों को कवर करते हुए कई स्थानों पर किया गया। दिल्ली के अलावा, पीपीसी 2026 का आयोजन तमिलनाडु के कोयंबटूर, छत्तीसगढ़ के रायपुर, गुजरात के देव मोगरा और असम के गुवाहाटी सहित चार अलग-अलग स्थानों पर किया गया, जिसमें देश के पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण और मध्य भाग शामिल थे।

देशभर के विद्यालयों में छात्र-केंद्रित गतिविधियों का आयोजन

परीक्षा पे चर्चा 2026 के आयोजन की तैयारियों के तहत, देशभर के विद्यालयों में छात्र-केंद्रित गतिविधियां आयोजित की गईं। इनमें आत्मनिर्भरता की भावना को बढ़ावा देने के लिए छात्रों द्वारा आयोजित स्वदेशी संकल्प दौड़ और पराक्रम दिवस पर चिन्हित केंद्रीय विद्यालयों में आयोजित प्रश्नोत्तरी और लेखन प्रतियोगिताएं शामिल थीं। इन गतिविधियों में लगभग 2.26 करोड़ छात्रों ने भाग लिया।



देखने ही चाहिए सपने

छात्रों से मुलाकात में पीएम मोदी ने कहा कि सपने न देखना, वो तो क्राइम है। सपने देखने ही चाहिए, लेकिन सपनों को गुनगुनाते रहना यह कभी काम नहीं आता है। इसलिए जीवन में कर्म को प्रधानता देना चाहिए। मैं जहां हूँ, वहां मुझे सफल होना है, तभी मैं आगे जाऊंगा। हमारा मन कर गया कि मुझे एस्ट्रोनॉट होना है और मुझे चंद्रमा पे जाना है, तो फिर मुझे पढ़ना चाहिए कि भई एस्ट्रोनॉट कौन हुए। उनकी बायोग्राफी क्या थी? यह स्पेस होता क्या है? धीरे-धीरे-धीरे उसमें हमें रुचि बढ़ानी चाहिए।

जिंदगी जीने के तरीके से जीवन बनता है: कुछ लोग होते हैं कि भई नींद नहीं आती। क्यों नहीं आती? कमरा ऐसा है। अगर उसको फाइव स्टार होटल में रखोगे न, तो भी नींद नहीं आएगी। तो यह जो सोच है कि सुविधा होगी तो क्षमता आएगी, ऐसा नहीं



...एक विद्यार्थी ने सुनाई कविता

हम सबके अरमान हैं आप। भारत के अभिमान हैं आप।
भारतवर्ष के केवट हैं आप। मानवता के सेवक हैं आप।
मैं बड़ी दूर से आई हूँ। कुछ प्रश्नों को अपने साथ भी लाई हूँ।
परीक्षा पे चर्चा की सौगात उठाए हैं। फिर हम यह मौका पाए हैं।
आप ममता की परछाई हैं। वंचितों के हमराही हैं।
देश को आगे रखते हैं। भारत मां की जय कहते हैं।
तो लो मैं भी यह कहती हूँ, मन की बात रखती हूँ।
आप साधना पुरुष और योगी हो।
भारत के सपनों के मोदी हो।
यह कहकर मैंने वाणी को विराम दिया।
फिर से आपको प्रणाम किया।

परीक्षा पे चर्चा से मिलते महत्वपूर्ण टिप्स

- स्ट्रेस मैनेजमेंट और टाइम मैनेजमेंट।
- एग्जाम के दौरान होने वाली घबराहट को दूर करने के उपाय।
- आखिरी दिनों में रिवीजन का सही तरीका।
- अभिभावक, बच्चों की मदद कैसे करें।



प्रधानमंत्री का पूरा कार्यक्रम देखने के लिए QR कोड स्कैन करें।

है। हमारे देश में बोर्ड के एग्जाम में जो नंबर लाते हैं, वो बच्चे कौन है? छोटे-छोटे गांव के हैं। वहां तो कोई कंफर्ट नहीं है। कंफर्ट जोन ही जीवन बनाता है, इस भ्रम में नहीं रहना चाहिए। जीवन बनता है जिंदगी जीने के तरीके से। ■

राष्ट्रपति का अभिभाषण

सुशासन को और सुदृढ़ करने की सामूहिक प्रतिबद्धता

वर्ष 2026 के पहले संसद सत्र की शुरुआत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के संबोधन के साथ हुई। यह संबोधन जहां हाल के वर्षों में भारत की विकास यात्रा का सजीव चित्रण था, वहीं भविष्य के लिए सुदृढ़ मार्गदर्शन और 140 करोड़ देशवासियों के आत्मविश्वास की अभिव्यक्ति। अभिभाषण में किसानों, युवाओं, गरीबों और वंचित वर्गों के सशक्तीकरण के लिए निरंतर किए जा रहे प्रयासों को रेखांकित किया गया। साथ ही रिफॉर्म एक्सप्रेस को और गति देने, इनोवेशन को बढ़ावा देने एवं सुशासन को और सुदृढ़ करने की नए भारत की सामूहिक प्रतिबद्धता को भी दोहराया, जो एक सशक्त, आत्मनिर्भर और समृद्ध राष्ट्र के साझा संकल्प को दर्शाता है। प्रस्तुत है संबोधन के संपादित अंश...



अतीत से प्रेरणा: वंदे मातरम् के 150 वर्ष होने पर पूरे देश में समारोह आयोजित हो रहे हैं। सभी देशवासी इस महान प्रेरणा के लिए, ऋषि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी को नमन कर रहे हैं। देशवासियों ने श्री गुरु तेग बहादुर जी का 350वां शहीदी पर्व पूरी श्रद्धा से मनाया। भगवान बिरसा मुंडा के 150वें जन्म-जयंती वर्ष के दौरान देश ने उन्हें श्रद्धांजलि दी, सरदार पटेल की 150वीं जन्म-जयंती से जुड़े आयोजनों ने एक भारत, श्रेष्ठ भारत के भाव को मजबूती दी। सभी देशवासी इस बात के भी साक्षी बने कि कैसे भारत रत्न भूपेन हजारिका की जन्म-शताब्दी के समारोह, सुरों और देश की एकता के भाव से भरे हुए थे। जब देशवासी अतीत के ऐसे महान पड़ावों और अपने पूर्वजों के महान योगदान को याद करते हैं, तो नई पीढ़ी को प्रेरणा मिलती है।

गरीबी में कमी: पिछले एक दशक में 25 करोड़ देशवासी गरीबी को हराकर गरीबी से बाहर निकले हैं। सरकार के तीसरे कार्यकाल में गरीबों को सशक्त करने का अभियान और तेजी से आगे बढ़ा है।

एलपीजी: उज्ज्वला योजना के माध्यम से अब तक 10 करोड़ से ज्यादा परिवारों को एलपीजी कनेक्शन मिले हैं। एक वर्ष में सरकार ने पौने सात लाख करोड़ रुपये से अधिक का लाभ डीबीटी के माध्यम से सीधे लाभार्थियों को पहुंचाया है।



पक्के घर: पिछले एक दशक में गरीबों के चार करोड़ पक्के घर बने। बीते एक वर्ष में 32 लाख नए घर गरीबों को मिले हैं।

नल से जल: जल जीवन मिशन के पांच वर्षों में साढ़े 12 करोड़ नए परिवारों तक पाइप से पानी पहुंचाया गया। बीते एक वर्ष में करीब एक करोड़ नए परिवारों तक नल से जल की सुविधा पहुंची है।

सामाजिक सुरक्षा: वर्ष 2014 की शुरुआत में सिर्फ 25 करोड़ नागरिकों तक ही सोशल सिक्योरिटी की योजनाएं पहुंच पाती थीं। सरकार के प्रयासों में निरंतरता की वजह से आज करीब 95 करोड़ भारतीयों को सोशल सिक्योरिटी का कवच मिला है।

स्वास्थ्य: गरीब मरीजों के लिए शुरू की गई आयुष्मान भारत योजना से बीते वर्ष तक 11 करोड़ से अधिक मरीजों को मुफ्त इलाज दिया गया है। बीते लगभग डेढ़ वर्ष में करीब एक करोड़ बुजुर्गों को वय वंदना कार्ड जारी किए गए हैं। इनकी मदद से करीब 8 लाख बुजुर्गों ने अस्पताल में भर्ती रहते हुए अपना मुफ्त इलाज कराया है। सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन में साढ़े छह करोड़ से अधिक नागरिकों की स्क्रीनिंग की गई है। गर्व की बात है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत को आंखों के संक्रमण, ट्रैकोमा से मुक्त घोषित किया है।

बीमा सुरक्षा: प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और पीएम सुरक्षा बीमा योजना के माध्यम से करोड़ों जरूरतमंद नागरिकों को बीमा कवरेज मिला है। इसके तहत 24 हजार करोड़ रुपये से अधिक का क्लेम भी दिया गया है।

किसान: पिछले वर्ष में भारत ने रिकॉर्ड साढ़े तीन सौ मिलियन टन से ज्यादा खाद्यान्न का उत्पादन किया है। 150 मिलियन टन उत्पादन के साथ भारत दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बन गया है। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश भी बना है। दूध उत्पादन के क्षेत्र में भी, भारत दुनिया के सबसे सफल देश के रूप में जाना जाता है।

मोबाइल-ईवी विनिर्माण: मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग जैसी फील्ड में भारत अब दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश बन गया है। 2025-26 के पहले 5 महीनों में भारत का स्मार्टफोन एक्सपोर्ट 1 लाख करोड़ रुपये के पार हो गया है। इस साल भारत ने सौ से अधिक देशों को इलेक्ट्रिक व्हीकल का निर्यात शुरू किया है।

पीएम ग्रामीण सड़क योजना : बीते एक वर्ष में देश में लगभग 18 हजार किलोमीटर नई ग्रामीण सड़कें जोड़ी गई हैं। अब भारत की करीब-करीब पूरी ग्रामीण आबादी सड़क से जुड़ चुकी है।

आइजोल पहुंची रेल : मिजोरम के आइजोल और नई दिल्ली को डायरेक्ट रेल रूट से जोड़ा गया है। बीते वर्ष जब आइजोल के स्टेशन पर पहली बार राजधानी एक्सप्रेस का आगमन हुआ, तो स्थानीय लोगों के उत्साह ने सारे देश को प्रसन्नता के भाव से जोड़ दिया।

सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज : जम्मू-कश्मीर में विश्व के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च चिनाब ब्रिज और तमिलनाडु में नए पंबन ब्रिज का निर्माण कर भारत ने इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में एक कीर्तिमान स्थापित किया।



राष्ट्रपति का अभिभाषण देखने के लिए QR कोड स्कैन करें।

जलमार्ग : पहले भारत में राष्ट्रीय जल मार्गों की संख्या 5 थी, जो अब 100 से अधिक हो चुकी है। इससे उत्तर प्रदेश, बंगाल, बिहार समेत पूर्वी भारत के राज्य लॉजिस्टिक हब बनकर उभर रहे हैं।

प्रगति : योजनाओं के लाभ को हर लाभार्थी तक पहुंचाने के लिए सरकार ने 'प्रगति' नाम से एक नई व्यवस्था आरंभ की थी। दिसंबर 2025 में 'प्रगति' की 50वीं बैठक हुई, बीते वर्षों में 'प्रगति' ने 85 लाख करोड़ रुपये से अधिक के प्रोजेक्ट्स को गति दी।

एक लाख करोड़ रुपये की बचत : जीएसटी रिफॉर्म के कारण देशवासियों को एक लाख करोड़ रुपये की बचत हुई। जीएसटी में कटौती के बाद वर्ष 2025 में टू व्हीलर का रजिस्ट्रेशन दो करोड़ पार कर गया है।

आयकर पर राहत : 12 लाख रुपये तक की आय पर टैक्स जीरो करने का ऐतिहासिक फैसला लिया गया है। ऐसे रिफॉर्म से गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को अभूतपूर्व फायदा हो रहा है।

नया श्रम कानून : देश में नया श्रम कानून लागू किया गया है। इससे श्रमिकों को उचित वेतन-भत्ते और अन्य कल्याणकारी लाभ मिलने आसान हुए हैं। देश के युवाओं और महिलाओं को इसका खासतौर से फायदा होगा।



मेट्रो नेटवर्क

2025 में भारत का कुल मेट्रो नेटवर्क 1,000 किलोमीटर के ऐतिहासिक आंकड़े को पार कर गया है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क वाला देश बन गया है।

सौर ऊर्जा : न्यूक्लियर के अलावा, भारत सोलर पावर सेक्टर में तेजी से आगे बढ़ रहा है। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से देश के आम उपभोक्ता अब बिजली के उत्पादक बन रहे हैं। अब तक लगभग 20 लाख रूफ टॉप सोलर सिस्टम लगाए जा चुके हैं।

सीमावर्ती इलाके तक पहुंच आसान : बीते 11 वर्षों में पूर्वोत्तर में 7,200 किलोमीटर से ज्यादा राष्ट्रीय राजमार्ग बनाए गए हैं। इससे दूर-दराज, पहाड़ी, जनजातीय और सीमावर्ती इलाकों तक पहुंचना आसान हुआ है।



स्वयं सहायता समूह

सरकार ने 10 करोड़ महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों से जोड़ा है। आज देश में लखपति दीदियों की संख्या 2 करोड़ से ज्यादा हो चुकी है। बीते एक वर्ष में ही 60 लाख से ज्यादा महिलाएं लखपति दीदी बनी हैं। मेरी सरकार कुल 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने के लक्ष्य को जल्द प्राप्त करने वाली है।

पीएम जनमन योजना : योजना के तहत, आदिवासियों में भी सबसे पिछड़ी जनजातियों के 20 हजार से ज्यादा गांवों को विकास से जोड़ा जा रहा है। इन गांवों में गरीबों के करीब ढाई लाख घर इसी योजना के माध्यम से बने हैं।

आदिवासी शिक्षा : पिछले 11 वर्षों में अनुसूचित जाति के लाखों छात्रों को 42 हजार करोड़ रुपये से अधिक की पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति दी गई है। करीब 5 करोड़ विद्यार्थियों को लाभ हुआ है। आदिवासी क्षेत्रों में सरकार ने 400 से अधिक एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय भी खोले हैं।

पीएम किसान सम्मान निधि : योजना के तहत अब तक किसानों को 4 लाख करोड़ रुपये से अधिक राशि सीधे उनके खातों में भेजी गई है।

जी राम जी कानून : जी राम जी कानून से गांव में एक सौ पच्चीस दिन के रोजगार की गारंटी दी गई। साथ ही भ्रष्टाचार और लीकेज को रोकना सुनिश्चित हो पाएगा। अब इस योजना से गांवों के विकास को नई गति मिलेगी।

ऑपरेशन सिंदूर : ऑपरेशन सिंदूर से विश्व ने भारतीय सेना का शौर्य और पराक्रम देखा है। देश ने अपने संसाधनों के बल पर आतंकियों के अड्डों को ध्वस्त किया। सरकार ने कड़ा संदेश दिया कि भारत पर किसी भी आतंकी हमले का जवाब दृढ़ और निर्णायक होगा। सिंधु जल समझौते को स्थगित किया जाना भी आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई का हिस्सा है।

माओवाद का अंत : माओवादी आतंक की चुनौती 126 जिलों से घटकर आठ जिलों तक सिमट गई है। इनमें से 3 जिले ही ऐसे हैं, जो गंभीर रूप से प्रभावित हैं। वो दिन दूर नहीं है, जब देश से माओवादी आतंक पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा।

सेमीकंडक्टर : वर्ष 2025 में चार सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को मंजूरी दी गई है। भारत में 10 ऐसी फैक्ट्रियां, आने वाले समय में अपना काम शुरू करने वाली हैं। भारत अब नैनो चिप निर्माण के लिए भी बड़े कदम उठा रहा है।

मुद्रा योजना : युवाओं में उद्यमिता और स्वरोजगार की भावना को बढ़ावा मिल रहा है। स्कीम के तहत, अभी तक 38 लाख करोड़ रुपये से अधिक का फंड, छोटे-छोटे उद्यमियों को मिला है। करीब 12 करोड़ से अधिक लोन पहली बार स्वरोजगार शुरू करने के लिए दिए गए हैं।

स्टार्टअप इंडिया : स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम ने अपने 10 साल पूरे किए हैं। इन 10 वर्षों में भारत दुनिया का तीसरा बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है। एक दशक पहले तक देश में 500 से भी कम स्टार्टअप थे। आज देश में लगभग 2 लाख स्टार्टअप पंजीकृत हो चुके हैं।

मोबाइल नेटवर्क : बीते वर्ष देश में 1 लाख से ज्यादा मोबाइल टावरों के जरिए 4G और 5G नेटवर्क को देश के कोने-कोने तक पहुंचाया गया है। डिजिटल इंडिया के विस्तार ने भारत को हजारों करोड़ की क्रिएटिव इकोनॉमी के एक बड़े ग्लोबल सेंटर के रूप में पहचान दी है। ■

सत्यमेव
जयते

विकसित भारत संकल्प की अमृत यात्रा

विकास, विश्वास और भविष्य की त्रिवेणी को साकार करता बजट



आम बजट 2026-27 देखने-सुनने
के लिए QR कोड स्कैन करें।

बीते 11 वर्षों में केंद्र सरकार ने विकसित भारत के संकल्प को सिद्ध करने का आधारस्तंभ तैयार किया है, अब वर्ष 2026-27 का बजट भी विकसित भारत के विराट व निर्णायक संकल्प को साकार करने की निरंतरता का प्रतीक बन गया है। संकल्प से सिद्धि के मंत्र और अमृत यात्रा की ओर बढ़ते निर्णायक कदम के साथ यह आम बजट भी बन गया है विकास, विश्वास और भविष्य की त्रिवेणी को साकार करने वाला आत्मनिर्भर भारत का सशक्त बजट...



यह विकसित भारत के संकल्प की अमृत यात्रा का दिशा-निर्देशक बजट है। बीते 11 वर्षों में विकास की यात्रा से स्वर्णिम भारत के आधार को सशक्त करने वाला बजट है। बजट में गांव- गरीब-किसान का कल्याण, मातृशक्ति का दर्शन, तो युवा भारत की युवा सोच भी है। युवाओं के संकल्प, सपने और युवाओं की गति भी है। सही अर्थों में यह बजट भी भारतीय अर्थव्यवस्था के गुणात्मक और मात्रात्मक परिवर्तन का एक उत्कृष्ट सारांश है। विकसित भारत के लिए शुरू हुई अमृत यात्रा को यथार्थ में बदलने वाला बजट है। यह बजट सटीक, सक्षम, सामर्थ्यवान भारत का बजट है। बीते 11 वर्षों की निरंतरता और दूरदृष्टि वाले आम बजट का उद्देश्य सदैव यही रहा है कि केंद्र सरकार के प्रत्येक कदम का लाभ देश के नागरिकों को मिले और राष्ट्र सशक्त हो।

इस वर्ष का आम बजट विशेष है क्योंकि यह कर्तव्य भवन में तैयार हुआ देश का पहला बजट है, जो तीन कर्तव्यों से प्रेरित है-

- पहला- आर्थिक वृद्धि को तेज करना व उसे बनाए रखना।
- दूसरा- नागरिकों की आकांक्षाओं को पूरा करना और उनकी क्षमता का निर्माण करना।
- तीसरा- सबका साथ-सबका विकास।

एक समय था जब आम बजट को केवल मात्र वित्तीय दस्तावेज के रूप में साल भर का लेखा-जोखा भर माना जाता था। लेकिन 2014 के बाद से यह वित्तीय विवरण पेश करने की संवैधानिक जरूरत भर नहीं, बल्कि केंद्र सरकार की दीर्घकालिक सोच के साथ इसे निरंतरता का प्रतीक वाला दस्तावेज बना दिया है। विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि, इसी सोच का परिणाम है।

सर्वस्पर्शी आम बजट

सर्वस्पर्शी और सर्वसमावेशी आम बजट 2026-27 देश के हर वर्ग और हर क्षेत्र के समग्र विकास पर केंद्रित है। निरंतरता के साथ आगे बढ़ता यह बजट आत्मनिर्भर और विकसित भारत के उस संकल्प को मजबूती देता है, जो केवल नारा नहीं बल्कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में ठोस प्रयास है। इस बजट में न केवल प्रत्येक क्षेत्र, प्रत्येक वर्ग और प्रत्येक नागरिक को सशक्त बनाने का एक स्पष्ट ब्लूप्रिंट है, बल्कि उसे प्रोत्साहन देने का एक जमीनी विजन भी है, जो उसे हर कदम पर मदद करेगा। विकसित भारत के संकल्प का यह आम बजट एक ऐसे भारत के निर्माण का विजन है, जो विश्व में हर क्षेत्र में अग्रणी हो। विनिर्माण क्षेत्र से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर तक, स्वास्थ्य से लेकर पर्यटन तक, ग्रामीण क्षेत्र से लेकर एआई तक, खेल से लेकर तीर्थों के विकास तक, प्रत्येक गांव, सभी कस्बे और प्रत्येक शहर के युवाओं, महिलाओं और किसानों के सपनों को शक्ति देकर समर्पित भाव से उन्हें पूरा करने वाला बजट है।

यह आम बजट भारत को एक नई पहचान देने वाले देश के रूप में प्रस्तुत करता है, जो अपनी ताकत पर अडिग भरोसा रखता है। एक मजबूत आर्थिक शक्ति केंद्र के रूप में उभर रहा है। कोविड के बाद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी आर्थिक नीतियों ने भारतीय अर्थव्यवस्था को नई गति दी है। यह बजट उस गति को और तेज करने वाला है। यह भारत को वैश्विक मंच पर सबसे आकर्षक निवेश केंद्र के रूप में स्थापित करने में मदद करने वाला है, चाहे वह पारंपरिक क्षेत्र हों या नए युग के उद्योग। इस बजट में पशुधन के माध्यम से किसानों की आय बढ़ाने का एक दूरदर्शी निर्णय लिया गया है। पशु चिकित्सकों की संख्या बढ़ाने, वेटेनरी सेंटर और ट्रेनिंग सेंटर के विस्तार से पशुधन आधारित अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। डेयरी और पोल्ट्री क्षेत्र के लिए क्रेडिट लिंकड सब्सिडी देने, 500 सरोवरों के विकास से मत्स्य पालन को बढ़ावा देने और वैश्विक बाजार उपलब्ध कराने जैसे निर्णयों से किसानों की आय बढ़ाने के संकल्प की दिशा में मील का पत्थर सिद्ध होंगे। महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज के स्वप्न को साकार करने की दिशा में 'महात्मा गांधी ग्राम स्वराज योजना' की शुरुआत का ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और बुनकरों, किसानों तथा हथकरघा उद्योग को नया संबल प्राप्त होगा। तटीय क्षेत्रों में कोकोनट प्रमोशन स्कीम से 3 करोड़ किसानों को लाभ,



काजू-कोको के उत्पादन एवं निर्यात को बढ़ावा व चंदन संरक्षण का निर्णय यह दर्शाता है कि नया भारत किसानों की समृद्धि और कृषि को लाभ का व्यवसाय बनाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। बजट भारत में कनेक्टिविटी को नई ऊंचाई देगा। आम बजट में सात हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर की घोषणा की गई है, जो प्रमुख आर्थिक और जनसंख्या केंद्रों के बीच यात्रा समय कम करके शहरों को तेजी से जोड़ेंगे।

भविष्य के भारत का दर्शन

बजट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की नीतिगत ईमानदारी का भी पर्याय है क्योंकि आमतौर पर चुनाव से पहले पेश होने वाले बजट में लोक-लुभावन घोषणाएं एक परंपरा सी बन गई थी। लेकिन इस बजट में कोई लोक-लुभावन घोषणा करने की बजाय दीर्घकालिक दृष्टिकोण के साथ 'राष्ट्र प्रथम' की सोच को



बजट ऐतिहासिक है, इसमें देश की नारीशक्ति का सशक्त प्रतिबिंब झलकता है। महिला वित्त मंत्री के रूप में निर्मला सीतारमण ने लगातार 9वीं बार देश का बजट प्रस्तुत करके नया रिकॉर्ड बनाया है। यह बजट अपार अवसरों का राजमार्ग है। ये बजट 2047 के विकसित भारत की हमारी ऊंची उड़ान का मजबूत आधार है।

-नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री

करेगा। पूर्वोत्तर के 5 राज्यों में बौद्ध सर्किट के निर्माण, हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर और अराकू घाटी में माउंटेन ट्रेल्स तथा ओडिशा, कर्नाटक और केरल में टर्टल ट्रेल्स विकसित करने से इन क्षेत्रों में विकास को नई गति मिलेगी। इको-टूरिज्म को प्रोत्साहन मिलेगा। साथ ही, नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ हॉस्पिटैलिटी की स्थापना से युवाओं को कौशल और रोजगार के अवसर मिलेंगे तथा पर्यटन क्षेत्र को भी नई मजबूती मिलेगी।

निश्चित रूप से रिफॉर्म एक्सप्रेस पर सवार नए भारत के संकल्प को इस आम बजट से नई ऊर्जा, नई गति मिलने वाली है जो 2047 तक राष्ट्र को विकसित बनाने का आधार बना है।

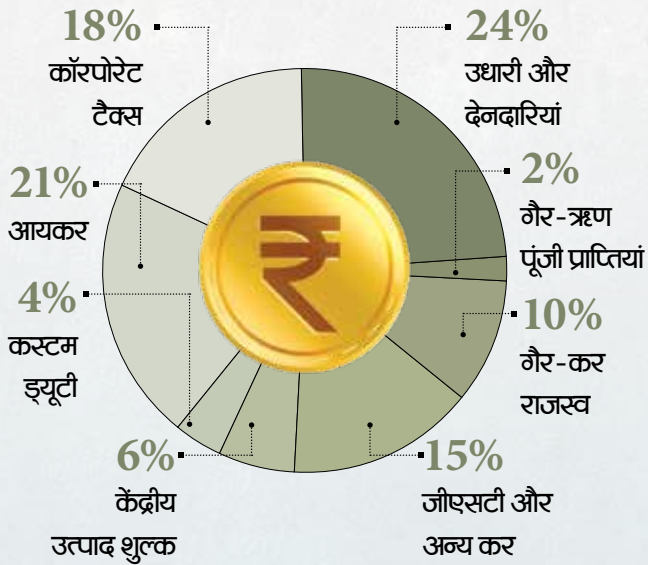
आइए 11 क्षेत्रों के माध्यम से समझते हैं कि अपने कार्यकाल के 12वें वर्ष में आगे बढ़ रही केंद्र सरकार ने आम बजट से किस तरह नए भारत की दिशा निर्धारित की है...

सर्वोपरि रखा गया है। नए भारत की नई रीति-नीति का ही परिणाम है कि केंद्र सरकार ने पिछले 11 वर्षों में लगभग 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला है तो दूसरी तरफ अर्थव्यवस्था तेज गति से आगे बढ़ रही है। ऐसे में यह बजट भी केंद्र सरकार की विकास और प्रगति को वित्तीय अनुशासन के साथ आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता को मजबूती से दर्शाता है। बजट ने राजकोषीय घाटे को 4.5% से नीचे रखने का लक्ष्य पूरा किया है। बजट में राष्ट्र प्रथम की सोच और “फ्यूचर रेडी भारत” का विजन है, जहां विकास केवल बड़े शहरों तक सीमित नहीं रहेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 12.2 लाख करोड़ रुपये पूंजीगत खर्च के रूप में आवंटित किए गए हैं। नए रेल कॉरिडोर, राष्ट्रीय जलमार्ग और बेहतर कनेक्टिविटी के माध्यम से टियर-2 और टियर-3 शहरों तक पहुंच बनाना रोजगार को बढ़ावा देगा और भारत की महत्वाकांक्षाओं को नई ऊंचाई तक ले जाएगा। यह बजट पीएम मोदी के उस विजन को साकार करता है, जिसमें एमएसएमई को भारत के विकास की कहानी का प्रमुख स्तंभ यानी रीढ़ बनाया गया है। एमएसएमई सेक्टर को ग्लोबल बनाने के लिए सरकार ने जो निर्णय लिए हैं, वह आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को साकार करने में सहायक सिद्ध होंगे। बजट में पर्यटन पर भी खासा ध्यान रखा गया है। बजट में किसान, मध्यवर्ग, महिला से लेकर सभी वर्गों को उज्ज्वल भविष्य की ओर ले जाएगी। एमएसएमई के लिए 10,000 करोड़ रुपये का ग्रोथ फंड रखा गया है। यह फंड टियर-2 और टियर-3 शहरों के एमएसएमई को मजबूती देते हुए लक्ष्य हासिल करने में मदद करेगा। आम बजट 2026-27, शिक्षा से स्वरोजगार तक प्रधानमंत्री मोदी के विजन का सशक्त प्रतिबिंब है। बड़े औद्योगिक और लॉजिस्टिक्स कॉरिडोर के आसपास 5 यूनिवर्सिटी टाउनशिप के विकास से शिक्षा-उद्योग के समन्वय को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही, चार टेलीस्कोप इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाओं के निर्माण व अपग्रेडेशन से अनुसंधान को नई गति मिलेगी। नेशनल डिजाइन इंस्टिट्यूट, 15,000 सेकेंडरी स्कूलों और 500 कॉलेजों में एवीजीसी लैब की स्थापना तथा ‘एजुकेशन टू एम्प्लॉयमेंट एंड एंटरप्राइज’ हाई-पावर्ड कमेटी का गठन नई पीढ़ी को कौशल-संपन्न बनाकर हर क्षेत्र में अग्रणी भारत के निर्माण के संकल्प को दर्शाता है।

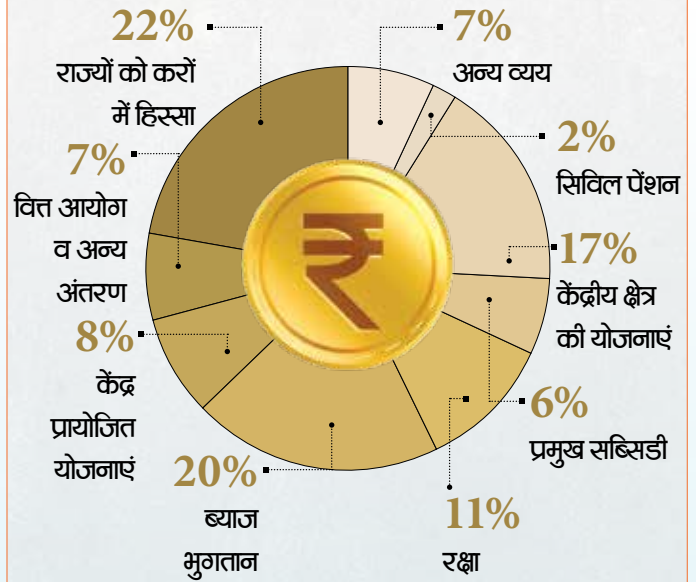
विकास भी, विरासत भी

विकास और विरासत, वर्तमान केंद्र सरकार की सोच का महत्वपूर्ण पहलू है। इस बजट में केंद्र सरकार द्वारा धोलावीरा सहित 15 पुरातात्विक स्थलों को सांस्कृतिक गंतव्य के रूप में विकसित करने का निर्णय भारत की प्राचीन संस्कृति को वैश्विक मंच पर स्थापित

पैसा कहां से आता है



कहां खर्च होता है

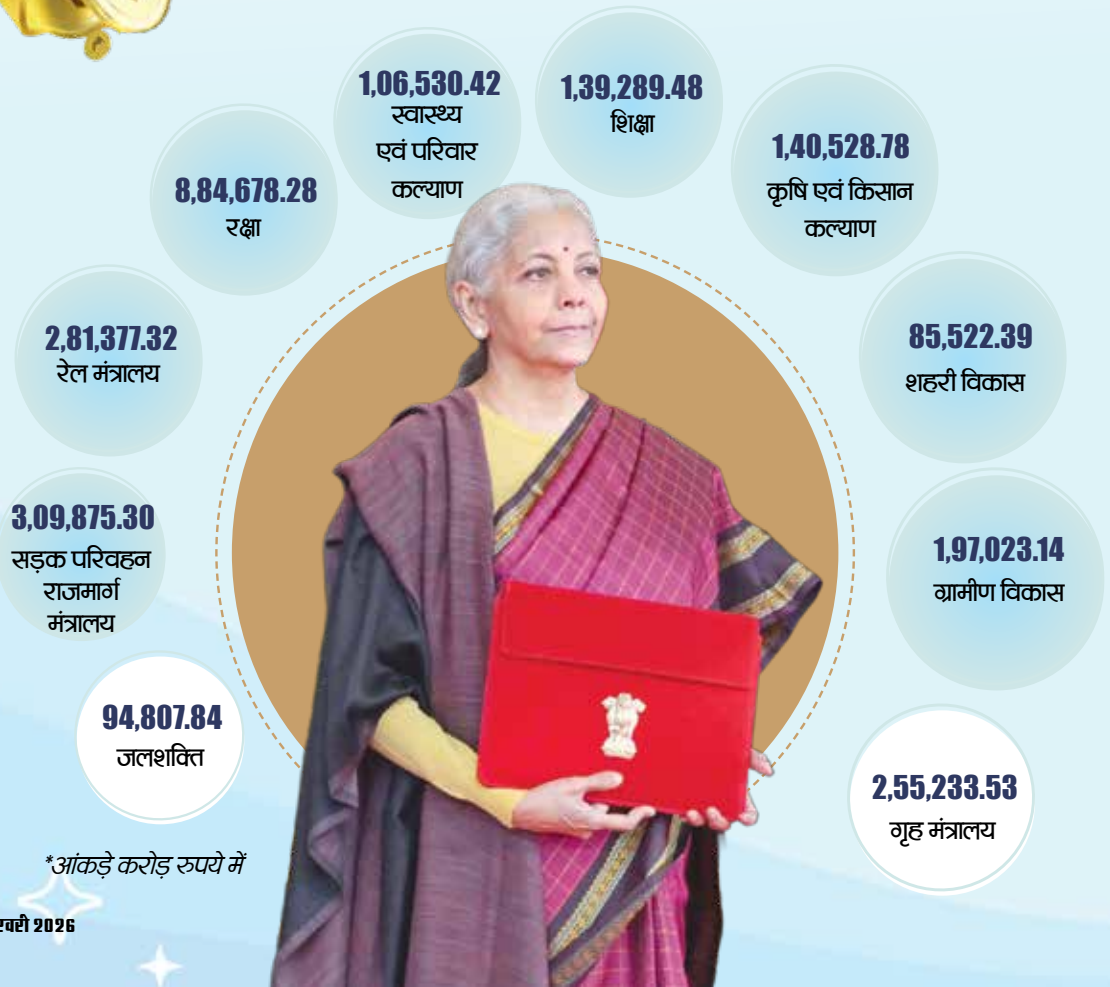


बजट अनुमान 2026-2027

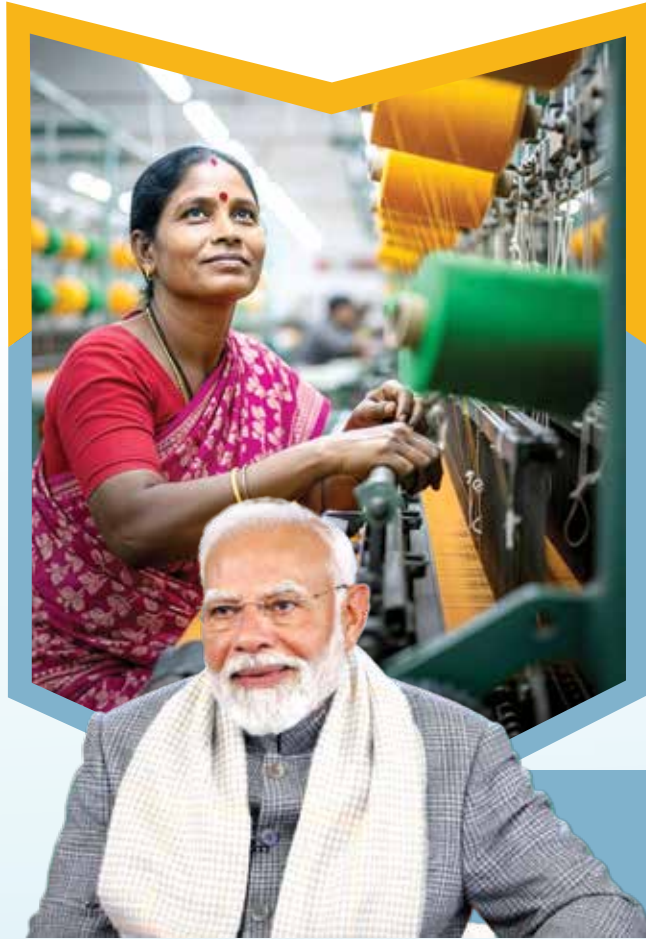


- ➔ **53.5** लाख करोड़ रुपये का बजट अनुमान।
- ➔ **₹36.5** लाख करोड़ गैर ऋण प्राप्ति।
- ➔ **₹28.7** लाख करोड़ केंद्र की नेट टैक्स प्राप्ति का अनुमान।
- ➔ **₹17.2** लाख करोड़ सकल बाजार उधारी का अनुमान।
- ➔ **4.3%** जीडीपी का राजकोषीय घाटा होने का अनुमान।

प्रमुख मंत्रालयों का बजट



*आंकड़े करोड़ रुपये में



एमएसएमई उद्यम से रोजगार तक

देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ माने जाने वाले सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र को इस वर्ष के बजट में नई ऊर्जा देने का प्रयास किया गया है। रोजगार सृजन, इनोवेशन और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को मजबूती देने वाले इस क्षेत्र को सरकारी समर्थन मिलने से लोकल से ग्लोबल बनने की मिलेगी नई ताकत...

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम
एमएसएमई का वित्त वर्ष
2026-27 का बजट

24,566.27
करोड़ रुपये

बढ़ेगा एमएसएमई का दायरा

- उद्यमों के विकास के लिए 10,000 करोड़ रुपये की समर्पित एमएसएमई निधि बनाने की घोषणा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में की है।
 - विनिर्माण में **MSMEs** की हिस्सेदारी 35.4 प्रतिशत, निर्यात में 48.58 प्रतिशत और **GDP** में 31.1 प्रतिशत है।
 - टीयर टू और टीयर थ्री शहरों में कॉर्पोरेट मित्र कैडर विकसित करने के लिए आई.सी.ए.आई., आई.सी.एस.आई., आई.सी.एम.ए.आई. जैसे व्यवसायिक शिक्षा संस्थानों को सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। ये प्रमाणित अर्ध-पेशेवर एमएसएमई को किफायती लागत पर अनुपालन अपेक्षाओं को पूरा करने में सहायता करेंगे।
- नकदी सहायता : ट्रेड्स के साथ, एमएसएमई को 7 लाख करोड़ रु से अधिक उपलब्ध कराई गई है। क्षमता का लाभ लेने के लिए 4 प्रस्ताव...
- केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों को एमएसएमई से सभी खरीद के लिए ट्रेड्स को अनिवार्य भुगतान प्लेटफॉर्म बनाना चाहिए।
 - ट्रेड्स प्लेटफॉर्म पर सीजीटीएमएसई के माध्यम से ऋण गारंटी सहायता तंत्र।
 - एमएसएमई से सरकारी खरीद पर वित्त प्रदाताओं को सूचना देने करने के लिए जेम को ट्रेड्स से जोड़ना।
 - ट्रेड्स की प्राप्तियों को आस्ति-समर्थित प्रतिभूतियों के रूप में शुरू किया जाएगा जिससे द्वितीयक बाजार बढ़ेगा और नकदी व भुगतान निपटान बेहतर होगा।

आर्थिक विकास में तेजी के लिए छह प्रस्ताव
आर्थिक विकास में तेजी लाने और इसे बनाए रखने के लिए छह क्षेत्रों में पहल का प्रस्ताव...

- 7 रणनीतिक व अग्रणी क्षेत्रों में विनिर्माण को तेज करना।
- विरासत के औद्योगिक क्षेत्रों का कार्याकल्प करना।
- “चैंपियन एमएसएमई” का निर्माण करना।
- इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोत्साहन देना।
- दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा व स्थायित्व सुनिश्चित करना।
- शहरी आर्थिक क्षेत्र विकसित करना।

एमएसएमई को चैंपियन बनाने के लिए
तीन स्तरीय रणनीति इक्विटी सपोर्ट

- 10 हजार करोड़ रुपये के एसएमई ग्रोथ फंड, आत्मनिर्भर भारत कोष को टॉप-अप।
- लिक्विडिटी सपोर्ट: TReDS से 7 लाख करोड़ रुपये+ लिक्विडिटी।
- प्रोफेशनल सपोर्ट: “कॉर्पोरेट मित्र” व आसान अनुपालन।

आर्थिक सुधार

‘सुधार एक्सप्रेस’ से भारत बन रहा और बड़ी अर्थव्यवस्था

भारत विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में से एक बनने की दिशा में आर्थिक, व्यापारिक और जीवन जीने की सुगमता के साथ सुधार एक्सप्रेस पर तेजी से दौड़ रही है। बीते 11 वर्ष में सरकार ने कार्रवाई, सुधार और जनहित को प्राथमिकता दी। अब वित्त वर्ष 2026-27 के बजट में इसे और दी गई है गति...



सरकार का ‘संकल्प’ गरीब, शोषित और वंचितों पर ध्यान देने के लिए त्रि-आयामी दृष्टिकोण...

- 1 ढांचागत सुधार की गति को निरंतर, अनुकूल और प्रगतिशील बनाए रखना होगा।
- 2 एक मजबूत और लचीला वित्तीय क्षेत्र बचत जुटाने, पूंजी का सही उपयोग करने और जोखिमों के प्रबंधन का आधार है।
- 3 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एप्लीकेशन सहित अति उन्नत प्रौद्योगिकियां सुशासन में सहायक बन सकती हैं।

केंद्र सरकार ने रोजगार के सृजन, उत्पादकता को बढ़ाने तथा विकास में तेजी लाने की दिशा में खूब आर्थिक सुधार किए हैं। वर्ष 2025 में स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुधार की घोषणाएं कीं, उसके बाद 350 से अधिक सुधारों को शुरू किया गया है।

विकसित भारत के लिए तैयार होगी बैंकिंग

आज भारत का बैंकिंग क्षेत्र पहले से कहीं अधिक मजबूत है। बेहतर वित्तीय स्थिति, ऐतिहासिक मुनाफा, कर्ज गुणवत्ता में सुधार और 98% से ज्यादा गांवों तक बैंकिंग सेवाओं की पहुंच है। इस क्षेत्र की प्रगति को और आगे बढ़ाने और भारत की अगली विकास जरूरतों के अनुसार इस क्षेत्र की समग्र समीक्षा के लिए “विकसित भारत के लिए बैंकिंग पर उच्च स्तरीय समिति” गठित की जाएगी।



शेयर के बायबैक को माना जाएगा कैपिटल गेन

शेयर बायबैक से मिलने वाली राशि को अब डिविडेंट नहीं, बल्कि पूंजीगत लाभ माना जाएगा। साथ ही, बायबैक पर प्रोमोटरों के लिए कर की दरें अलग-अलग होंगी। इसमें घरेलू कंपनियों के प्रोमोटरों पर 22% और अन्य कंपनियों पर 30% कर होगा। शेयर बाजार में फ्यूचर और ऑप्शन ट्रेडिंग को सट्टा बाजार की तरह फटाफट पैसा बनाने की खातिर उतरने वालों को थोड़ा हतोत्साहित करने के लिए सरकार ने फ्यूचर ट्रेडिंग पर मौजूदा सिक्कोरिटी ट्रांसफर इयूटी(एसटीटी) को 0.02% से बढ़ाकर 0.05% करने का प्रस्ताव किया है। वहीं ऑप्शन प्रीमियम और ऑप्शन ट्रेडिंग पर लगने वाले 0.1% और 0.125% एसटीटी को बढ़ाकर 0.15% करने का प्रस्ताव किया है।

ईज ऑफ लीविंग

कानूनी उलझनें घटाई गई... 1 अप्रैल से नया आयकर कानून लागू होगा



आयकर के स्लैब या छूट में किसी तरह का बदलाव नहीं किया गया है। 1 अप्रैल, 2026 से आयकर अधिनियम, 2025 लागू होगा।



सरलीकृत आयकर नियमावली और फार्म जल्द किए जाएंगे अधिसूचित। नए फार्म आम नागरिक के आसान अनुपालन के हिसाब से पुनः डिजाइन किए गए हैं।



मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण ने जो ब्याज तय किए उस पर आम व्यक्ति को आयकर नहीं देना होगा। इस पर कोई टीडीएस भी नहीं काटा जाएगा।



विदेश यात्रा पैकेज की बिक्री पर वसूले जाने वाले टीसीएस की दर को किसी राशि की सीमा के बिना, मौजूदा 5% और 20% से घटाकर 2% करने का प्रस्ताव।



शिक्षा और चिकित्सा के लिए उद्धारीकृत धनप्रेषण योजना (एलआरएस) के तहत टीसीएस की दर को 5% से घटाकर 2% करने का प्रस्ताव।



टीडीएस को लेकर भ्रम दूर करने के लिए कार्यबल सेवाओं की आपूर्ति को खासतौर पर संविदाकारों को भुगतान की श्रेणी में लाने का प्रस्ताव है। इन सेवाओं पर टीडीएस की दर केवल 1% या 2% होगी।



छोटे करदाताओं के लिए एक नई योजना जिसमें नियमों पर आधारित स्वचालित प्रक्रिया के जरिए, कर निर्धारण अधिकारी के पास आवेदन किए बिना कम या शून्य कटौती का प्रमाण-पत्र मिल सकेगा।



एक मामूली शुल्क देकर रिटर्न में संशोधन करने की समय-सीमा को 31 दिसंबर से बढ़ाकर 31 मार्च करने का प्रस्ताव।



कर रिटर्न दाखिल करने की अलग-अलग समय-सीमा रहेगी। आईटीआर-1 और आईटीआर-2 भरने वाले पहले की तरह 31 जुलाई तक रिटर्न होगा। जबकि गैर-लेखापरीक्षा वाले व्यापार मामलों और न्यासों को 31 अगस्त तक का समय दिया जाएगा।



किसी अनिवासी द्वारा अचल संपत्ति बेचने पर टीडीएस काटने के लिए टैन लेने की जरूरत नहीं होगी। निवासी खरीदार अपने पैसों के आधार पर चालान के जरिए टीडीएस जमा कर सकेगा।



छात्रों, युवा पेशेवरों, तकनीकी कर्मचारियों, विदेश में रह रहे अनिवासी भारतीयों और अन्य छोटे करदाताओं के लिए, एक नई योजना का प्रस्ताव। विदेशी संपत्ति को बताने के लिए 6 महीने का समय दिया जाएगा।

दंड और अभियोजन को सरल बनाना

- कर निर्धारण और दंड की कार्यवाही को एक ही सामान्य आदेश से जोड़ने का प्रस्ताव। पहली अपील की अवधि के दौरान दंड की राशि पर करदाता से कोई ब्याज नहीं लिया जाएगा। पहले जमा की जाने वाली राशि को 20% से घटाकर 10% किया जा रहा है।



- करदाता, पुनर्निर्धारण की कार्यवाही के बाद भी, संबंधित वर्ष की दर के अलावा 10% अतिरिक्त कर देकर अपनी रिटर्न अपडेट कर सकेगा।
- कम आय बताने के मामलों में दंड और अभियोजन से राहत को अब गलत जानकारी देने के मामलों में भी लागू किया जाएगा। हालांकि, ऐसे मामलों में करदाता को अतिरिक्त आयकर के रूप में कर की 100% राशि भी चुकानी होगी।
- खाते-किताब या दस्तावेज न देने और वस्तु के रूप में भुगतान पर टीडीएस न चुकाने को अपराध नहीं माना जाएगा। छोटे मामलों में केवल जुर्माना लगेगा।

स्वास्थ्य

सामाजिक सुरक्षा की रीढ़ बनता स्वास्थ्य बजट

स्वास्थ्य बजट न केवल बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर केंद्रित है बल्कि सुलभ, सस्ती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का भी है संकल्प...

स्वास्थ्य और परिवार
कल्याण मंत्रालय का बजट

1,06,530.42 करोड़ रुपये

194%

से अधिक की कुल वृद्धि दर्ज की गई
पिछले 12 वर्षों में स्वास्थ्य बजट में।



कैंसर की दवाएं सस्ती

कैंसर मरीजों की 17 जीवन रक्षक दवाओं पर बुनियादी सीमा शुल्क से पूर्ण छूट का प्रस्ताव है। इसके अलावा, विशेष चिकित्सा उद्देश्यों के लिए दवाओं, औषधियों और खाद्य पदार्थों के निजी तौर पर मंगाने पर आयात शुल्क से छूट के साथ-साथ इसमें 7 अतिरिक्त दुर्लभ बीमारियों को भी शामिल किया गया है।



मानसिक स्वास्थ्य और ट्रॉमा केयर

मानसिक स्वास्थ्य के लिए निमहांस-2 की स्थापना होगी। साथ ही रांची एवं तेजपुर में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य संस्थानों का क्षेत्रीय शीर्ष संस्थानों के रूप में भी उन्नयन किया जाएगा।



अनुसंधान

बजट 2026-27 से चिकित्सा अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए 24% की वृद्धि करते हुए 4,821 करोड़ रुपये से अधिक का बजट प्रावधान किया गया है।



बुजुर्गों की चिकित्सा

बुजुर्गों की चिकित्सा और संबद्ध सेवाओं के लिए आने वाले पांच वर्षों में 1.5 लाख देखभाल सेवा प्रदाताओं को प्रशिक्षित किया जाएगा।



चिकित्सा पर्यटन सेवा केंद्र

भारत को चिकित्सा पर्यटन सेवा केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए निजी क्षेत्र की साझेदारी में पांच क्षेत्रीय चिकित्सा केंद्रों की स्थापना में राज्यों को सहायता दी जाएगी। इसमें चिकित्सा, शैक्षिक और अनुसंधान सुविधाएं होंगी।



जिला अस्पताल

50% जिला अस्पतालों में आपातकालीन और ट्रॉमा केयर केंद्र की स्थापना करके इनकी क्षमताओं को सुदृढ़ किया जाएगा।

एचपी संस्थान की स्थापना



स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों (एचपी) के लिए मौजूदा संस्थानों का उन्नयन किया जाएगा। साथ ही, निजी और सरकारी क्षेत्रों में नए एचपी संस्थानों की स्थापना की जाएगी। इसमें आप्टोमेट्री, रेडियोलॉजी, एनेस्थीसिया,

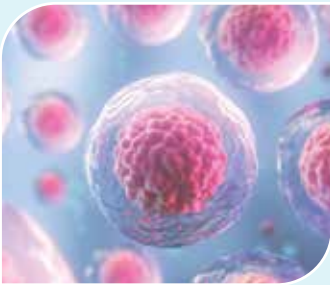
ओटी टेक्नोलॉजी, अप्लाइड साइकोलॉजी और व्यवहार संबंधी स्वास्थ्य सहित 10 चयनित विषय क्षेत्रों को शामिल किया जाएगा। अगले 5 वर्ष में एक लाख एचपी जोड़े जाएंगे।

पशु चिकित्सक



पशु चिकित्सा पेशेवरों की संख्या 20,000 से अधिक करने के लिए ऋण से जुड़े पूंजीगत सब्सिडी का प्रस्ताव किया गया है। इसका उद्देश्य निजी क्षेत्र में पशु चिकित्सा और प्राइवेट कॉलेज, पशु चिकित्सालय, जांच

प्रयोगशाला, प्रजनन सुविधा की स्थापना में समर्थन देना है।



बायोफार्मा शक्ति (ज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं नवाचार के माध्यम से स्वास्थ्य सेवा के लिए रणनीति)

मधुमेह, कैंसर और

ऑटोइम्यून डिसऑर्डर जैसी गैर संक्रामक बीमारियां देश में तेजी से बढ़ रही हैं। लिहाजा भारत को एक वैश्विक बायोफार्मा विनिर्माण केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए अगले 5 वर्षों में 10,000 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ बायोफार्मा शक्ति का प्रस्ताव किया गया है। इससे 3 नए राष्ट्रीय फार्मास्यूटिकल शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान और 7 मौजूदा संस्थानों के उन्नयन के साथ बायोफार्मा केंद्रित नेटवर्क शामिल होगा। इससे 1,000 से अधिक मान्यता प्राप्त इंडिया क्लीनिकल ट्रायल साइट का एक नेटवर्क भी तैयार होगा।

आयुष

बनेंगे तीन नए एम्स

- परंपरागत चिकित्सा पद्धति से मरीजों के लिए तीन नए अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान की स्थापना की जाएगी।
- आयुष फार्मसी, औषधि परीक्षण प्रयोगशाला, साक्ष्य आधारित अनुसंधान के साथ-साथ जामनगर में डब्ल्यूएचओ वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा केंद्र का उन्नयन भी किया जाएगा।

आयुष मंत्रालय का बजट

4,408.93 करोड़ रुपये



मेडिकल हब्स के निर्माण से, एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स के माध्यम से, ऑरेंज इकोनॉमी यानी ऑडियो विजुअल्स, गेमिंग को बढ़ावा देकर, पर्यटन को प्रोत्साहन देकर और खेलो इंडिया मिशन के माध्यम से, युवाओं के लिए नए अवसरों के द्वार खुलेंगे।

-नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री

आत्मनिर्भर भारत

टेक्सटाइल उद्योग की नई बुनावट

केंद्रीय बजट में टेक्सटाइल क्षेत्र को रोजगार सृजन, निर्यात वृद्धि और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य से जोड़ते हुए विशेष महत्व दिया गया है। परंपरागत हैंडलूम से लेकर आधुनिक मैन्-मेड फाइबर और तकनीक-आधारित वस्त्र निर्माण तक, पूरे वैल्यू चेन को सशक्त करने पर सरकार का स्पष्ट रूप से दिखता फोकस...

कपड़ा मंत्रालय का
वित्त वर्ष 2026-27
में बजट

5729.01
करोड़ रुपये



सरकार ने प्रतिस्पर्धात्मकता, आत्मनिर्भरता और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए वस्त्र क्षेत्र के लिए एक एकीकृत कार्यक्रम का प्रस्ताव किया है जिसमें पांच उप-घटक शामिल हैं

- **राष्ट्रीय रेशा योजना:** रेशा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के उद्देश्य से शुरू की गई यह योजना रेशम, ऊन और जूट जैसे प्राकृतिक रेशों, मानव निर्मित रेशों और आधुनिक युग के रेशों को समर्थन प्रदान करेगी।
- **वस्त्र विस्तार एवं रोजगार योजना:** इस घटक का उद्देश्य मशीनरी, प्रौद्योगिकी उन्नयन और साझा परीक्षण एवं प्रमाणन केंद्रों की स्थापना के लिए पूंजीगत सहायता के माध्यम से पारंपरिक वस्त्र समूहों का आधुनिकीकरण करना है।
- **राष्ट्रीय हथकरघा एवं हस्तशिल्प कार्यक्रम:** हथकरघा एवं हस्तशिल्प के लिए मौजूदा योजनाओं को एक किया जाएगा और एक एकीकृत राष्ट्रीय कार्यक्रम के तहत मजबूत किया जाएगा। इससे बुनकरों और कारीगरों को लक्षित एवं प्रभावी सहायता सुनिश्चित की जा सकेगी।
- **टेक्स-इको पहल:** इस पहल का उद्देश्य वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी, पर्यावरण की दृष्टि से टिकाऊ वस्त्र और परिधान निर्माण को बढ़ावा देना है।

“

इस बजट में मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान को नई रफ्तार के लिए महत्वाकांक्षी रोडमैप प्रस्तुत किया गया है। इस बजट में नई उभरती इंडस्ट्रीज, यानी सनराइज सेक्टर को जिस मजबूती के साथ समर्थन दिया गया है, वो अभूतपूर्व है।

-नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री

व्यापार करने की सुविधा

भारत के बाहर रहने वाले व्यक्तिगत निवेशकों (PROI) को सूचीबद्ध भारतीय कंपनियों के शेयरों में निवेश की अनुमति दी जाएगी। कुल निवेश की सीमा 10% से बढ़ाकर 24% और किसी एक निवेशक की सीमा 5% से बढ़ाकर 10% किया जाएगा।





समर्थ 2.0

उन्नत कौशल कार्यक्रम उद्योग और शैक्षणिक संस्थानों के साथ गहन सहयोग के माध्यम से वस्त्र कौशल तंत्र का आधुनिकीकरण करेगा।

महात्मा गांधी ग्राम स्वराज योजना

खादी, हथकरघा और हस्तशिल्प को सुदृढ़ बनाने के लिए महात्मा गांधी ग्राम स्वराज योजना का शुभारंभ होगा। इससे वैश्विक बाजार संबद्धता और ब्रांडिंग में सहायता मिलेगी। यह प्रशिक्षण, कौशल, प्रक्रिया और उत्पादन गुणवत्ता को सुसंगत बनाएगा और सहायता प्रदान करेगा।

रेयर अर्थ

नवंबर, 2025 में रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट स्कीम आरंभ की गई थी। अब बजट में खनन, प्रसंस्करण, अनुसंधान और विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए दुर्लभ खनिज कॉरिडोर स्थापित करने की घोषणा की गई है। यह कॉरिडोर खनिज संपन्न राज्य ओडिशा, केरल, आन्ध्र प्रदेश और तमिलनाडु को सहायता करेगा।

कंटेनर विनिर्माण

10,000 करोड़ रु. के बजटीय आबंटन के साथ 5 वर्षों की अवधि के लिए कंटेनर विनिर्माण योजना शुरू की जाएगी।



हम ग्रोथ की गति बनाए रखने के लिए रास्ता बना रहे हैं। उस ग्रोथ की गति या लगातार आर्थिक विकास को हम सुनिश्चित करना चाहते हैं। मुख्य रूप से, हम स्ट्रक्चरल सुधारों के साथ इकोसिस्टम बनाने पर ध्यान दे रहे हैं। सुधार गतिविधियां इस लक्ष्य के साथ जारी रहेंगी कि हम प्रोडक्टिविटी में सुधार और रोजगार पैदा करने के लिए पर्याप्त माहौल बनाएं।

-निर्मला सीतारमण, केंद्रीय वित्त मंत्री

व्यापक और एकीकृत नीतिगत ढांचे की घोषणा

बजट 2026-27 में श्रम प्रधान वस्त्र क्षेत्र पर विशेष बल दिया गया है, क्योंकि इसमें रोजगार सृजन, निर्यात, ग्रामीण आजीविका और टिकाऊ विनिर्माण में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। फाइबर से लेकर फैशन तक, ग्रामीण उद्योगों से लेकर वैश्विक बाजारों तक, संपूर्ण वस्त्र मूल्य श्रृंखला को मजबूत करने के लिए एक व्यापक और एकीकृत नीतिगत ढांचे की घोषणा की गई है।

मेगा टेक्सटाइल पार्क

सरकार ने मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने की घोषणा की है। यह पार्क तकनीकी वस्त्रों के विकास को भी बढ़ावा देगा।

व्यापार प्राप्य छूट प्रणाली

वस्त्र उद्योग के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए नकदी पहुंच सुगम और मजबूत करने के लिए सरकार ने व्यापार प्राप्य छूट प्रणाली (टीआरईडीएस) की प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए प्रमुख उपायों की घोषणा की है।

वस्त्र, चमड़ा और समुद्री उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण घोषणाएं

- शुल्क-मुक्त आयातित कच्चे माल का उपयोग करके निर्मित वस्त्र, चमड़े के वस्त्र, चमड़े या सिंथेटिक जूते और अन्य चमड़े के उत्पादों के निर्यातकों के लिए निर्यात दायित्व अवधि बढ़ाकर 12 महीने कर दिया गया है।
- इस उपाय से निर्यातकों को परिचालन में अधिक लचीलापन, अनुपालन में आसानी और कार्यशील पूंजी प्रबंधन में सुधार होगा।
- टीआरईडीएस के माध्यम से वस्त्र उद्योग के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए नकद सहायता की व्यवस्था।

महिला

समृद्ध बनाने की दिशा में निरंतर बढ़ते कदम

केंद्र सरकार महिलाओं को शिक्षित, समृद्ध बनाकर सशक्त करने की दिशा में निरंतर काम कर रही है। इसी कड़ी में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में महिलाओं से जुड़ी कई घोषणाएं की हैं। इसका सीधा फायदा देश की आधी आबादी को होगा। इस वर्ष का बजट महिलाओं द्वारा निर्मित और संचालित स्वयं सहायता समूहों के एक आधुनिक तंत्र को प्राथमिकता देता है, जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक घर तक पहुंचे समृद्धि...

महिला छात्रावास

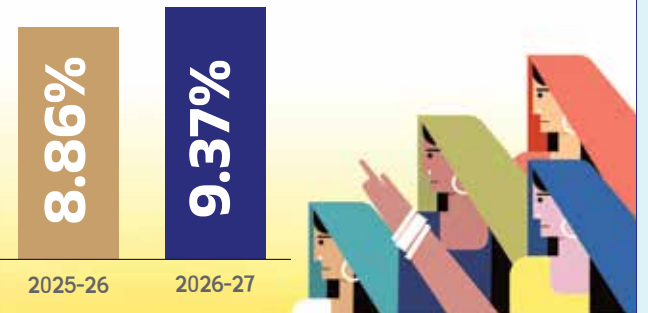
केंद्र सरकार ने देश के हर जिले में महिला छात्रावास के निर्माण का निर्णय लिया है। यह पहल शिक्षा के क्षेत्र में लैंगिक समानता, सुरक्षा और सशक्तीकरण को मजबूत करने वाला एक मील का पत्थर है।



सेल्फ हेल्प एंटरप्रेन्योर 'SHE मार्ट' की व्यवस्था

- लखपति दीदी योजना की सफलता को आगे बढ़ाते हुए बजट में सेल्फ हेल्प एंटरप्रेन्योर 'SHE मार्ट' की व्यवस्था की गई है।
- पशुपालन, कृषि से जुड़ी गतिविधियों और अन्य कार्यों में लगी बहनें अब केवल आजीविका तक सीमित न रहकर उद्यमी के रूप में आगे बढ़ सकेंगी, यही इस पहल का उद्देश्य है।
- हर जिले में महिलाओं के उत्पादों को बेचने के लिए एक प्लेटफॉर्म के रूप में कम्युनिटी रिटेल आउटलेट स्थापित होंगे, जहां स्वयं सहायता समूहों और ग्रामीण बहनों द्वारा तैयार उत्पादों को नया बाजार मिलेगा।
- साथ ही **She-Mark** बैज की लॉन्चिंग से महिलाओं को आसान फाइनेंसिंग सुविधा सुनिश्चित हो सकेगी।

लैंगिक समानता के लिए बजट आवंटन



2026-27 के लैंगिक बजट अनुमान (जीबीएस) में महिलाओं और बालिकाओं के कल्याण के लिए पांच लाख करोड़ रुपये का आवंटन किया गया जो 2025-26 में 4.49 लाख करोड़ रुपये के मुकाबले 11.36 प्रतिशत अधिक है।

युवा

खुलेंगे अवसरों के नए द्वार

संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते समय कहा- यह युवा शक्ति का बजट है। इसमें युवा की सोच भी है, युवा के सपने भी हैं, युवा के संकल्प भी हैं और साथ-साथ युवा की गति भी है। बजट में जो प्रावधान किए गए हैं, उससे अलग-अलग सेक्टर्स में लीडर्स, इनोवेटर्स और क्रिएटर्स तैयार होंगे। साथ ही खेलो इंडिया मिशन के माध्यम से युवाओं के लिए खुलेंगे अवसरों के नए द्वार...

शिक्षा

- सरकार बड़े औद्योगिक और लॉजिस्टिक कॉरिडोर के आसपास चुनौती मार्ग के माध्यम से पांच विश्वविद्यालय टाउनशिप का निर्माण करने में राज्यों की सहायता करेगी।
- भारत के पूर्वी क्षेत्र में एक नए राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान की स्थापना का प्रस्ताव।
- एस्ट्रो फिजिक्स व एस्ट्रोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए 4 टेलीस्कोप सुविधाओं की स्थापना की जाएगी।

बजट

शिक्षा मंत्रालय के लिए
कुल बजट आवंटन

1,39,289.48

करोड़ रुपये तक पहुंच गया है

जो बजट अनुमान 2025-26 की तुलना में 8.27% की वृद्धि है।

शिक्षा से रोजगार एवं उद्यम

विकसित भारत के मुख्य संचालक के रूप में सेवा क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करने के लिए उच्चाधिकार प्राप्त 'शिक्षा से रोजगार एवं उद्यम' स्थायी समिति के गठन का प्रस्ताव। यह फैसला भारत को वर्ष 2047 तक 10 प्रतिशत की वैश्विक हिस्सेदारी के साथ अग्रणी बनाएगा।

ऑरेंज इकोनॉमी

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी, मुंबई को 15 हजार माध्यमिक विद्यालयों और 500 महाविद्यालयों में एवीजीसी कंटेंट क्रिएटर लैब (सीसीएल) स्थापित करने में सहायता प्रदान करने का प्रस्ताव।

खेलकूद

खेलो इंडिया कार्यक्रम के माध्यम से चल रहे खेलकूद से जुड़ी प्रतिभाओं के विकास के प्रयासों को आगे बढ़ाते हुए अगले दशक में खेलकूद के क्षेत्र में बदलाव लाने के लिए खेलो इंडिया मिशन शुरू करने का प्रस्ताव।

कई सुविधाएं प्रदान करेगा खेलो इंडिया मिशन

- एक एकीकृत प्रतिभा विकास मार्ग, जो बुनियादी, इंटरमीडिएट और एलीट स्तर पर प्रशिक्षण केंद्रों द्वारा समर्थित होगा।
- प्रशिक्षकों और सहायक स्टाफ का व्यवस्थित विकास किया जाएगा।
- खेल विज्ञान और प्रौद्योगिकी का एकीकरण।
- खेलों की संस्कृति को बढ़ावा देने व इसके लिए मंच उपलब्ध कराने के लिए प्रतिस्पर्धाएं और लीग आयोजित कराना।
- प्रशिक्षण और प्रतियोगिताओं के लिए खेलों से संबंधित बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास करना।



कृषि क्षेत्र किसानों का सपना होगा पूरा

भारत की कृषि, डेयरी सेक्टर, फिशरीज को केंद्र सरकार ने हमेशा सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। इस साल के बजट में भी, नारियल, काजू, कोको और चंदन की पैदावार से जुड़े किसानों के लिए अनेक अहम कदम उठाए गए हैं। फिशरीज और पशुपालन में उद्यमिता को बढ़ावा देने से गांव में ही बनेंगे रोजगार और स्वरोजगार के और ज्यादा अवसर...



1,70,944
करोड़ रुपये

सब्सिडी का प्रावधान सस्ता खाद और उर्वरक उपलब्ध कराने के लिए है, ताकि उत्पादन की लागत कम हो और किसान को राहत मिले।

उच्च मूल्य कृषि

सरकार देगी उच्च मूल्य वाली फसलों की खेती को समर्थन...

- तटवर्ती इलाकों में नारियल, चंदन, कोको, काजू जैसे उच्च मूल्य वाली फसलों को सहायता प्रदान की जाएगी।
- नारियल संवर्धन योजना का प्रस्ताव।
- पूर्वोत्तर में अगर के पेड़ों और पर्वतीय क्षेत्रों में बादाम, अखरोट और खुबानी जैसे गिरीदार फलों को प्रोत्साहन दिया जाएगा।
- वर्ष 2030 तक भारतीय काजू और कोको को प्रीमियम वैश्विक ब्रांड के रूप में बदलने के लिए समर्पित कार्यक्रम का प्रस्ताव।

किसानों की आय बढ़ाना

- किसानों की आय बढ़ाने के लिए मत्स्य पालन, पांच सौ जलाशयों और अमृत सरोवरों के एकीकृत विकास, पशुपालन, उच्च मूल्य वाली कृषि को प्रोत्साहन दिया जाएगा।

भारत-विस्तार

- केंद्रीय बजट में भारत-विस्तार का प्रस्ताव। यह बहुभाषीय एआई टूल है। इसे एआई प्रणाली सहित कृषि संबंधी प्रणालियों के लिए आईसीएआर पैकेज सहित एग्री स्टैक पोर्टल के रूप में एकीकृत किया गया है।

ग्रामीण विकास विभाग के बजट में वृद्धि

- ग्रामीण विकास विभाग के बजट में 21% की वृद्धि। ग्रामीण विकास और कृषि विभाग मिलाकर ग्रामीण विकास और कृषि मंत्रालय का बजट अब 4 लाख 35 हजार 779 करोड़ रुपये से अधिक हो गया है।
- कृषि विभाग का बजट बढ़ाकर इस वर्ष 1,32,561 करोड़ रुपये कर दिया गया है। कृषि शिक्षा और अनुसंधान के लिए 9,967 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इससे शोध और नवाचार को बल मिलेगा।
- नेशनल फाइबर स्कीम के अंतर्गत सिल्क, वूल और जूट जैसे फाइबर पर फोकस किया गया है। इससे इनसे जुड़े किसानों को सीधा लाभ मिलेगा।

सहकारिता क्षेत्र के लिए कई प्रोत्साहनों का प्रस्ताव

- प्राथमिक सहकारी समिति द्वारा उत्पादित पशुचारा और कपास के बीज की आपूर्ति के लिए कटौती की अनुमति।
- नई कर व्यवस्था के तहत अंतर-सहकारी समिति लाभांश आय को कटौती के रूप में अनुमति।





दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग
का बजट वित्त वर्ष 2026-27 में

1669.72
करोड़ रुपये

दिव्यांगजन

गरिमा, अवसर और आत्मनिर्भरता

दिव्यांगजन सशक्तीकरण को सामाजिक दायित्व से आगे बढ़ाकर समावेशी विकास की मुख्यधारा से जोड़ने की दिशा में इस वर्ष का बजट एक ठोस रोडमैप प्रस्तुत करता है। शिक्षा, कौशल विकास, स्वास्थ्य, सहायक उपकरणों की उपलब्धता और रोजगार के अवसरों के विस्तार पर केंद्रित प्रावधानों के माध्यम से बजट का उद्देश्य दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर बनाना और गरिमापूर्ण जीवन के साथ समान अवसर करना है प्रदान...

ईज ऑफ लीविंग

दिव्यांगजन कौशल योजना

प्रत्येक दिव्यांग समूहों के लिए उद्योग-संगत और अनुकूल विशिष्ट प्रशिक्षण के माध्यम से सम्मानजनक आजीविका के अवसर सुनिश्चित किया जाएगा। उद्योग के माध्यम से सम्मानजनक आजीविका अवसर उपलब्ध कराना और दिव्यांग महिलाओं के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार किया जाएगा। योजना के तहत आईटी, एवीजीसी और हॉस्पिटैलिटी क्षेत्रों में दिव्यांगजनों को अनुकूलित प्रशिक्षण दिया जाएगा।

सशस्त्र बलों के लिए दिव्यांगता पेंशन

अर्धसैनिक कर्मियों सहित सशस्त्र बलों के कर्मियों को प्रदत्त दिव्यांगता पेंशन, सेवा शर्त और दिव्यांगता शर्त को शामिल किया गया है। जहां कार्मिक, सेना, नौसेना अथवा वायु सेना सेवा के कारण या उसके प्रकोप के कारण शारीरिक अशक्तता हुआ हो और सेवा से बाहर हो गया हो, उनके लिए विशेष छूट की व्यवस्था की गई है।

वृद्धों की चिकित्सा

निजी क्षेत्र की भागीदारी के साथ वृद्धजनों के लिए स्वास्थ्य सेवा इकोसिस्टम और संबद्ध देखभाल सेवा केंद्रों का निर्माण किया जाएगा। डेढ़ लाख देखभाल सेवा प्रदाताओं को अगले कुछ वर्ष में प्रशिक्षित किया जाएगा।

दिव्यांग संहारा योजना

सभी पात्र दिव्यांगजनों तक उच्च-गुणवत्ता वाले सहायक उपकरण समय पर पहुंचे।

- अनुसंधान और विकास तथा एआई एकीकरण में निवेश के लिए भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम (एएलआइएमसीओ) को सहायता उपलब्ध कराया जाएगा।
- पीएम दिव्यांग केंद्रों को मजबूत करने और आधुनिक रिटेल-स्टाइल केंद्रों के रूप में सहायक प्रौद्योगिकी मार्ट की स्थापना का प्रस्ताव किया गया है। यहां दिव्यांगजन और वरिष्ठ नागरिक सहायक उत्पादों को देख, परख और खरीद सकेंगे।
- दिव्यांग संहारा योजना के तहत सरकार आर्टिफिशियल लिम्ब्स मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (ALIMCO) को सहायक उपकरणों के उत्पादन को बढ़ाने, अनुसंधान और विकास में निवेश करने और उत्पाद डिजाइन में कृत्रिम बुद्धिमत्ता सहित उन्नत प्रौद्योगिकियों को एकीकृत करने के लिए सहायता प्रदान करेगी।

भविष्य का भारत इंफ्रा के दम पर बढ़ेगी ग्रोथ की गाड़ी

किसी भी देश या राज्य के विकास का सबसे बड़ा पैमाना उसका पूंजीगत बजट माना जाता है। सरकारी कैपेक्स जितना ज्यादा होगा, विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर पर उतना अधिक काम होगा। बीते 11 वर्ष में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए न सिर्फ पूंजीगत खर्च 2 लाख करोड़ रुपये से बढ़ाकर 12.2 लाख करोड़ रुपये किया गया बल्कि बड़े पैमाने पर किया गया है इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास...



6 गुना हुआ
इंफ्रा बजट

12.2
लाख करोड़ रुपये
2026-27

11.2
लाख करोड़ रुपये
2025-26

2
लाख करोड़ रुपये
2014-15

सात हाईस्पीड रेल कॉरिडोर होंगे विकसित, और करीब आएं शहर

केंद्रीय बजट 2026-27 में

भारतीय रेल को अब तक का सबसे अधिक

2,93,030 करोड़ रुपये के रिकॉर्ड पूंजीगत व्यय(कैपेक्स) का आवंटन।

- रेलवे अपना व्यय हाई-स्पीड कनेक्टिविटी, माल ढुलाई और सुरक्षा पर करने में ध्यान केंद्रित कर रहा है।

- चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद ये साउथ हाई स्पीड डायमंड बनेगा। 5 दक्षिण भारत राज्य- कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी के लिए एक बड़ा वरदान साबित होगा।

- दक्षिण हाई-स्पीड कॉरिडोर से कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी को लाभ।

लगभग **4,000** किलोमीटर में फैले हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर से करीब 16 लाख करोड़ रुपये के निवेश की उम्मीद।

- प्रस्तावित कॉरिडोर से शहरों के बीच यात्रा के समय में कमी आएगी। यात्रियों के लिए बिना किसी रुकावट के मल्टीमॉडल आवाजाही आसान होगी।

- मुंबई - पुणे
- पुणे - हैदराबाद
- हैदराबाद - बेंगलुरु
- हैदराबाद - चेन्नई

- चेन्नई - बेंगलुरु
- दिल्ली - वाराणसी
- वाराणसी - सिलीगुड़ी
- विकसित करेंगे।



पर्यावरण-अनुकूल कार्गो परिवहन



पूर्व डानकूनी से पश्चिम में सूरत तक नया समर्पित मालवाहक कॉरिडोर (2052 किमी लंबा) बनेगा।



तालचर और आंगुल जैसे खनिज समृद्ध क्षेत्रों तथा कलिंगा नगर जैसे औद्योगिक केंद्रों को पारादीप और धमरा पत्तनों से जोड़ने के लिए ओडिशा में एनडबल्यू-5 से शुरु करते हुए, अगले 5 वर्षों में 20 नए राष्ट्रीय जलमार्ग (एनडबल्यू) शुरु किए जाएंगे।



जलमार्गों को लेकर जनशक्ति तैयार करने के उद्देश्य से क्षेत्रीय उत्कृष्टता केंद्रों के रूप में प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किए जाएंगे जिसका लाभ युवाओं को होगा। अंतर्देशीय जलमार्गों की जरूरतों को पूरा करने के लिए बनारस-पटना में जहाज मरम्मत सुविधा स्थापित की जाएगी।



2047 तक जलमार्ग और तटीय परिवहन की हिस्सेदारी 6% से बढ़ाकर 12% की जाएगी, इसके लिए तटीय कार्गो प्रोत्साहन योजना शुरु की जाएगी।



अंतिम छोर व दूर दराज के क्षेत्रों को जोड़ने और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए समुद्री विमानों के स्वदेशी निर्माण को बढ़ावा दिया जाएगा। संचालन में मदद के लिए समुद्री विमान वीजीएफ योजना शुरु होगी।

कार्बन कैप्चर उपयोगिता और भंडारण (सीसीयूएस)

दिसंबर, 2025 में शुरु किए गए रोडमैप के अनुरूप, बड़े पैमाने पर सीसीयूएस प्रौद्योगिकियां विद्युत, इस्पात, सीमेंट और रसायनों सहित पांच औद्योगिक क्षेत्रों के लिए अगले पांच वर्षों में

20,000 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव।



इंफ्रास्ट्रक्चर गारंटी फंड होगा स्थापित

- सीपीएसईएस की महत्वपूर्ण रियल एस्टेट परिसंपत्तियों की रिसाइलिंग को तेज करने के लिए समर्पित आरईआईटीएस की स्थापना की जाएगी।
- सरकार का 5 लाख से अधिक आबादी वाले (टियर-II और टियर-III) शहरों में इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास पर फोकस जारी है।
- इंफ्रास्ट्रक्चर विकास और निर्माण में निजी डेवलपर्स के विश्वास को मजबूत करने और ऋणदाताओं को आंशिक ऋण गारंटी उपलब्ध कराने के लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर जोखिम गारंटी निधि स्थापित की जाएगी।
- सीपीएसई द्वारा डिजिटल रूप से समर्थित ऑटोमेटेड सर्विस ब्यूरो के रूप में 2 स्थानों पर हाई-टेक टूल रूम स्थापित किए जाएंगे।
- उच्च-मूल्य और तकनीकी रूप से उन्नत निर्माण एवं अवसंरचना उपकरण (सीआईई) के घरेलू उत्पादन को मजबूत करने के लिए एक योजना आरंभ की जाएगी।
- 5 वर्षों की अवधि के लिए

10,000 करोड़ रुपये के बजटीय आवंटन के साथ वैश्विक प्रतिस्पर्धी कंटेनर विनिर्माण परिवेश तैयार करने के एक कंटेनर विनिर्माण योजना का भी प्रस्ताव।



शहरी आर्थिक क्षेत्र

शहर भारत के विकास, नवाचार और अवसरों के इंजन हैं। हम अब टियर II और टियर III शहरों तथा तीर्थ कस्बों पर भी ध्यान केंद्रित करेंगे, जिन्हें आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर और बुनियादी सुविधाओं की आवश्यकता है। आर्थिक शक्ति का उपयोग करने और शहरों की क्षमता को और अधिक बढ़ाने के लिए चुनौती मोड के माध्यम से उनकी योजनाओं को लागू करने के लिए 5 वर्षों में प्रति शहरी आर्थिक क्षेत्र के लिए

5,000

करोड़ रुपये आवंटन प्रस्तावित।



विकास के इंजन

उभरती तकनीक और डिजिटलाइजेशन

21वीं सदी प्रौद्योगिकी से प्रेरित है। इसे अपनाना सभी लोगों के हित में है। सरकार ने एआई मिशन, राष्ट्रीय क्वांटम मिशन, अनुसंधान नेशनल रिसर्च फंड, और अनुसंधान, विकास एवं नवाचार निधि से नई प्रौद्योगिकियों को सहायता प्रदान करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। इसी कड़ी में 2026-27 के बजट में किए गए हैं कई प्रावधान...

40,000 करोड़ रुपये

किया गया इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग स्कीम का बजट।

15.5%

एक समान सेफ हार्बर मार्जिन लागू होगा, सूचना प्रौद्योगिकी की सभी सेवाओं की एकल श्रेणी होगी।

- सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, आईटी समर्पित सेवाओं, ज्ञान प्रक्रिया आउटसोर्सिंग सेवाओं और सॉफ्टवेयर विकास से संबंधित अनुसंधान और विकास सेवाओं के क्षेत्र में लीडर हैं। अब इन सभी सेवाओं को सूचना प्रौद्योगिकी सेवाओं की एकल श्रेणी में लाकर 15.5% एक समान सेफ हार्बर मार्जिन लागू होगा।
- आईटी सेवाओं के लिए सेफ हार्बर प्राप्त करने की सीमा को 300 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 2,000 करोड़ रुपये किया जा रहा है।
- आईटी सेवाओं के लिए सेफ हार्बर का अनुमोदन अब स्वचालित नियम से होगा। आवेदनों की जांच करने और स्वीकार करने के लिए किसी कर अधिकारी की आवश्यकता नहीं होगी।
- एक बार किसी आईटी सेवा कंपनी द्वारा इसके लिए आवेदन करने पर, कंपनी की इच्छानुसार इसी सेफ हार्बर को 5 वर्षों की अवधि के लिए जारी रखा जा सकता है।
- एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट (एपीए) करने की इच्छुक आईटी सेवा कंपनियों के एकपक्षीय एपीए प्रक्रिया को तेज करने का प्रस्ताव, जिसे 2 वर्षों की अवधि के भीतर पूरा करने का प्रयास किया जाएगा।



सेमीकंडक्टर मिशन में दो बड़ी घोषणाएं की गई हैं जो इंडिया स्टैक और आईपी से जुड़े मामलों को बेहतर बनाएंगी। 40,000 करोड़ रुपये की इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग स्कीम इलेक्ट्रॉनिक्स को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक बड़ा प्रोत्साहन है।

-निर्मला सीतारमण, केंद्रीय वित्त मंत्री



वैश्विक व्यापार और निवेश आकर्षित करना

- डाटा केंद्रों के इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश को बढ़ाने की दृष्टि से ऐसी विदेशी कंपनी जो डाटा केंद्र सेवाओं का उपयोग करके वैश्विक तौर पर क्लाउड सेवाएं प्रदान करती हैं, उन्हें वर्ष 2047 तक कर रियायत (टैक्स होलिडे) दी जाएगी।
- यदि डाटा सेंटर सेवाएं प्रदान करने वाली कंपनी एक संबंधित कंपनी है तो, उसे लागत पर 15% का सेफ हार्बर दिया जाएगा।
- इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण की खातिर जस्ट-इन-टाइम कार्य कुशलता का उपयोग करने के लिए, मूल्य के 2 प्रतिशत के लाभांतर पर कंपोनेंट वेयरहाउस के लिए अनिवारियों को सेफ हार्बर प्रदान किया जाएगा।
- भारत में टोल विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए अनिवारी को आयकर से 5 वर्षों के लिए छूट प्रदान की जाएगी।
- वैश्विक प्रतिभा के विशाल पूल को भारत में लंबी अवधि के लिए काम करने हेतु प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से अधिसूचित योजनाओं के अंतर्गत 5 वर्षों की प्रवास अवधि के लिए किसी अनिवारी विशेषज्ञ की वैश्विक (गैर-भारत स्रोत) आय के लिए छूट दी जाएगी।
- अनुमानित आधार पर कर भुगतान करने वाले अनिवारियों को न्यूनतम वैकल्पिक कर (एमएटी) से छूट दी जाएगी।

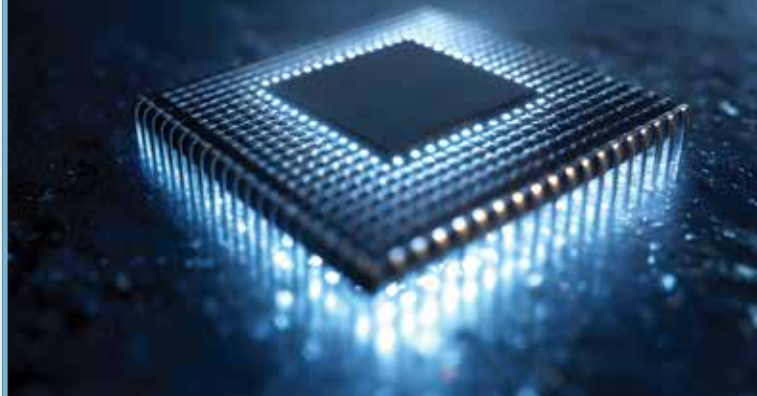


ई-कॉमर्स से कुरियर निर्यातों की मूल्य सीमा खत्म

ई-कॉमर्स के माध्यम से वैश्विक बाजारों में भारत की पहुंच बढ़ी है। भारत के छोटे व्यवसायों, कारीगरों और स्टार्टअप की आकांक्षाओं को सहायता प्रदान करने के लिए, कुरियर निर्यातों पर प्रति खेप 10 लाख रुपये की मूल्य सीमा को हटाई गई। ऐसी खेपों की पहचान के लिए प्रौद्योगिकी के प्रभावी उपयोग से अस्वीकृत और वापस लौटाई गई खेपों के प्रबंध में सुधार किया जाएगा।

भारत सेमीकंडक्टर मिशन

- उपकरण और सामग्रियों के उत्पादन, पूर्ण सुसज्जित भारतीय आईपी डिजाइन तथा आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत करने के लिए भारत सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 शुरू किया जाएगा। उद्योग आधारित अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्रों पर भी ध्यान केंद्रित किया जाएगा।
- अप्रैल, 2025 में 22,919 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ आरंभ की गई इलेक्ट्रॉनिक्स घटक विनिर्माण योजना में पहले ही लक्ष्य से दोगुनी निवेश प्रतिबद्धताएं प्राप्त हो चुकी हैं। इस तेजी का लाभ उठाने के लिए, परिव्यय बढ़ाकर 40,000 करोड़ रुपये किया जाएगा।



ये बजट एंबीशियस भी है। ये बजट देश की एस्पिरेशन को भी एड्रेस करता है। मैं एक बार फिर निर्मला जी और उनकी टीम को इस फ्यूचरिस्टिक एवं संवेदनशील, गांव गरीब किसान का कल्याण करने वाले बजट के लिए, बहुत-बहुत बधाई देता हूं।

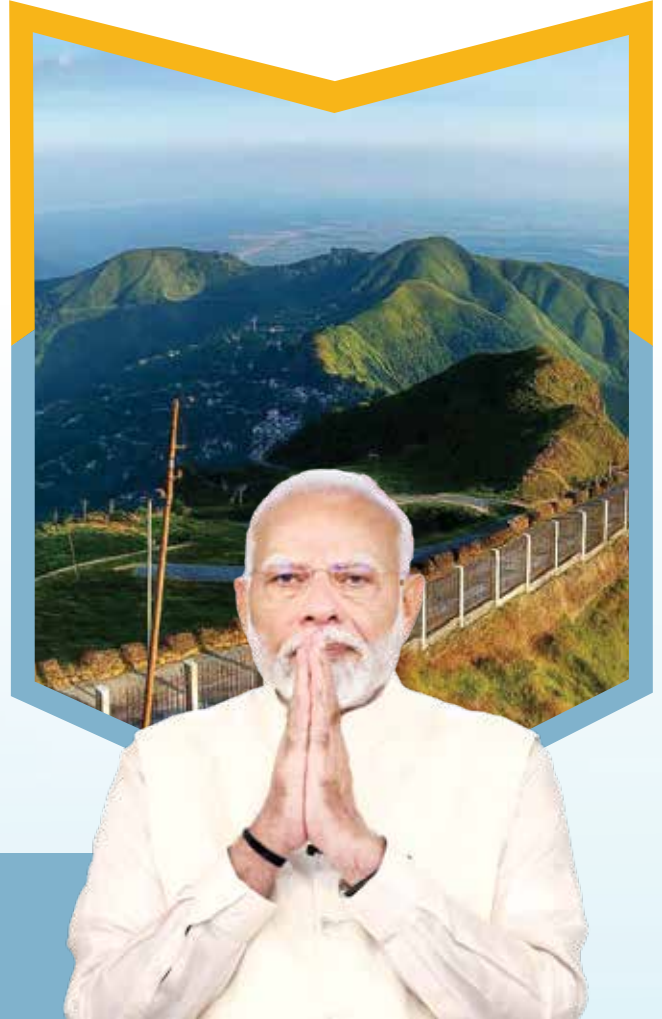
-नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री

पर्यटन को नई गति

भारत की संस्कृति और विरासत को नई ऊंचाइयां

भारत की सांस्कृतिक जड़ों की मजबूती के लिए पर्यटन आधारित विकास में नए अवसर खोले जा रहे हैं। बजट में आध्यात्मिक पर्यटन, गंतव्य विकास और भारत के विशाल सांस्कृतिक इको-सिस्टम को सशक्त बनाने पर विशेष जोर दिया गया है। इस साल का बजट पर्यटन को नई गति, भारत की संस्कृति और विरासत को ले जाने वाला है नई ऊंचाइयों तक...

हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर में, साथ ही पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट की अराकू घाटी में पारिस्थितिक रूप से टिकाऊ पर्वतीय मार्ग विकसित करने का प्रस्ताव।



राष्ट्रीय आतिथ्य संस्थान होगा स्थापित

- मौजूदा राष्ट्रीय होटल प्रबंधन और कैटरिंग प्रौद्योगिकी परिषद का उन्नयन करते हुए राष्ट्रीय आतिथ्य संस्थान की स्थापना का प्रस्ताव। इससे युवाओं को कौशल और रोजगार के अवसर मिलेंगे तथा पर्यटन क्षेत्र को भी नई मजबूती मिलेगी।
- भारतीय प्रबंधन संस्थान के सहयोग से हाइब्रिड मोड में मानकीकृत, उच्च गुणवत्ता वाले 12 सप्ताह के प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के जरिए 20 पर्यटन स्थलों में 10 हजार गाइडों के कौशल उन्नयन के लिए प्रायोगिक योजना शुरू की जाएगी।
- सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और विरासत महत्व वाले सभी स्थानों के डिजिटल दस्तावेज तैयार करने के लिए नेशनल डेस्टिनेशन डिजिटल नॉलेज ग्रिड की स्थापना होगी।
- यह पहल स्थानीय शोधार्थी, इतिहासविद, कंटेन्ट क्रिएटर व टेक्नोलॉजी में नए रोजगार का इकोसिस्टम तैयार करेगी।

15 पुरातात्विक स्थल होंगे सांस्कृतिक गंतव्य के रूप में विकसित

- लोथल, धौलावीरा, राखीगढ़ी, अद्विचनल्लूर, सारनाथ, हस्तिनापुर और लेह पैलेस जैसे 15 पुरातात्विक स्थलों को जीवंत और अनुभवजन्य सांस्कृतिक गंतव्य के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव। इससे वैश्विक मंच पर भारतीय संस्कृति स्थापित होगी।

5 पूर्वोत्तर राज्यों में 5 पर्यटन स्थलों के निर्माण

- दुर्गापुर में बेहतर संपर्क नोड के साथ एकीकृत पूर्वी तट औद्योगिक गलियारे के विकास, 5 पूर्वोत्तर राज्यों में 5 पर्यटन स्थलों के निर्माण होगा।
- पूर्वोत्तर में 4,000 ई-बसें चलेगी।
- अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, असम, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में बौद्ध सर्किट के विकास के लिए नई योजना।
- यह योजना मंदिरों-मठों के संरक्षण, तीर्थ स्थलों पर द्विभाषी केंद्र की स्थापना संपर्क तथा तीर्थ से जुड़ी मूलभूत सुविधाओं को उपलब्ध कराने में सहायक सिद्ध होगी।

पर्यटन आधारित विकास के नए अवसर

- ओडिशा, कर्नाटक और केरल में प्रमुख कछुआ प्रजनन स्थलों के साथ-साथ कछुआ मार्ग भी विकसित किए जाएंगे।
- पर्यटन और जैव विविधता को बढ़ावा देने के लिए आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में पुलिकट झील के किनारे बर्ड वॉचिंग ट्रेल्स विकसित किए जाएंगे।

पद्म सम्मान 2026

पद्म भूषण
उच्च कोटि की
विशिष्ट सेवा

पद्म विभूषण
असाधारण और विशिष्ट सेवा

पद्म श्री
विशिष्ट सेवा



पीपुल्स पद्म की वास्तविक भावना के अनुरूप नई परंपरा निष्काम कर्मयोगियों को पद्म सम्मान

देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में शामिल पद्म सम्मान अब सिर्फ प्रसिद्ध हस्तियों को नहीं बल्कि किसी भी सूरत में समाज, देश में सकारात्मक ऊर्जा का संचार और मानवता की सेवा करने वाले गुमनाम नायकों को भी मिल रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि वर्तमान सरकार ने इन पुरस्कारों के चयन की पूरी प्रक्रिया ही बदल दी... अब राष्ट्रपति भवन में सुखियों से दूर निःस्वार्थ रूप से परंपरा, संस्कृति, शिक्षा-साहित्य, स्वास्थ्य के लिए सेवा करने वाले गुमनाम नायक बढ़ा रहे हैं 'जनता के पद्म' का सम्मान... वर्ष 2026 में सार्वजनिक जीवन को समृद्ध करने वाले 131 विभूतियों को किया जाएगा सम्मानित...

पद्म विभूषण से सम्मानित होंगी यह 5 विभूतियां



धर्मेन्द्र सिंह देओल
(मरणोपरांत)(कला)
महाराष्ट्र



के टी थॉमस
(सार्वजनिक मामले)
केरल



एन राजम
(कला)
उत्तर प्रदेश



पी नारायणन
(साहित्य एवं शिक्षा)
केरल



वी एस अच्युतानंदन
(मरणोपरांत) (सार्वजनिक
मामले), केरल

दे श के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक पद्म सम्मान 2026 की घोषणा गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर की गई जिसमें दो युगल पुरस्कार सहित 131 महान विभूतियों के नाम शामिल हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जिन पद्म पुरस्कारों को प्रदान

करने की स्वीकृति दी है, उनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्म श्री पुरस्कार शामिल हैं। इनमें से 19 महिलाएं हैं जबकि विदेशी/एनआरआई/पीआईओ/ओसीआई श्रेणी के 6 व्यक्ति और 16 मरणोपरांत पुरस्कार हैं। इस वर्ष के नाम में शामिल 19 महिलाओं

पद्म पुरस्कारों की महत्ता कुछ यूं समझें

- भारत सरकार ने 1954 में दो नागरिक पुरस्कार-भारत रत्न और पद्म विभूषण की शुरुआत की थी। पद्म विभूषण पुरस्कार में तीन श्रेणियां थीं, पहला वर्ग, दूसरा वर्ग और तीसरा वर्ग। 8 जनवरी, 1955 को राष्ट्रपति की तरफ से जारी अधिसूचना से इनका नाम बदलकर पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री कर दिया गया।
- यह पुरस्कार प्रतिष्ठा और राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक है। इसमें नकद राशि नहीं दी जाती।
- पुरस्कार विजेताओं को राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित एक सनद (प्रमाण पत्र) और एक पदक प्रदान किया जाता है। पदक की एक छोटी प्रतिकृति भी दी जाती है, जिसे वे किसी भी समारोह के दौरान पहन सकते हैं।
- यह पुरस्कार किसी उपाधि के समान नहीं है। इसका उपयोग पुरस्कार विजेताओं के नाम के प्रत्यय या उपसर्ग के रूप में नहीं किया जा सकता है।

को जोड़ लें तो बीते 6 वर्ष में पद्म पुरस्कार पाने वाली महिलाओं की संख्या बढ़कर 154 पहुंच गई हैं। यह पुरस्कार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोहों में आमतौर पर प्रत्येक वर्ष मार्च या अप्रैल के आसपास प्रदान किए जाते हैं।

देश के लिए बेहतरीन योगदान और उनकी समर्पित सेवा के लिए जिन महान विभूतियों को सम्मानित किया जाएगा। अभिनेता धर्मेन्द्र सिंह देओल और केरल के पूर्व मुख्यमंत्री वी. एस. अच्युतानंदन को मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाएगा। वहीं पद्म भूषण पाने वालों में उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी, कल्लिपट्टी रामासामी पलनीसामी, गायिका अलका याज्ञनिक और मलयाली अभिनेता ममूटी के साथ ही एड गुरु पीयूष पांडेय, राजनेता शिबू सोरेन और विजय कुमार मल्होत्रा को मरणोपरांत पद्म भूषण से सम्मानित किया जाएगा। पद्म श्री सम्मान से सम्मानित किए जाने वालों में जो 113 लोग शामिल हैं, उनमें खेल जगत से क्रिकेट खिलाड़ी रोहित शर्मा, प्रवीण कुमार और महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमन प्रीत कौर, बलदेव सिंह, के. पजनीवेल और सविता पुनिया शामिल हैं।

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने गुजरात, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और असम से पद्म सम्मान के लिए नामित लोगों के योगदान को न सिर्फ सराहा बल्कि कहा है कि इनके उत्कृष्ट योगदान प्रेरणा पथ पर दूसरों के मार्ग प्रशस्त करेंगे।

13 नायकों को पद्म भूषण



अलका याज्ञनिक
(कला) - महाराष्ट्र



भगत सिंह कोश्यारी
(सार्वजनिक मामले)
उत्तराखंड



कल्लिपट्टी रामासामी
पलानीस्वामी (दवा)
तमिलनाडु



ममूटी (कला)
केरल



डॉ. नोरी दत्तात्रेयुडु
(दवा) - संयुक्त राज्य
अमेरिका



पीयूष पांडे
(मरणोपरांत) (कला)
महाराष्ट्र



पद्मश्री
113

किस क्षेत्र में मिले
कितने पद्म पुरस्कार

कला	44 (2 पद्म विभूषण, 4 पद्म भूषण, 38 पद्म श्री)
साहित्य एवं शिक्षा	18 (1 पद्म विभूषण, 17 पद्म श्री)
मेडिसिन	15 (2 पद्म भूषण, 13 पद्म श्री)
पब्लिक अफेयर्स	7 (2 पद्म विभूषण, 4 पद्म भूषण, 1 पद्म श्री)
समाज सेवा	13 (1 पद्म विभूषण, 12 पद्म श्री)
खेल	9 (1 पद्म भूषण, 8 पद्म श्री)
व्यापार एवं उद्योग	4 (1 पद्म भूषण, 3 पद्म श्री)
सिविल साइंस	2 पद्म श्री
साइंस एंड इंजीनियरिंग	11 पद्म श्री
अन्य	8 पद्म श्री
कुल	131

“

देश के प्रति उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए सभी पद्म पुरस्कार विजेताओं को बधाई। विभिन्न क्षेत्रों में उनकी उत्कृष्टता, समर्पण और सेवा हमारे समाज की संरचना को समृद्ध बनाती है। यह सम्मान उस वचनबद्धता और उत्कृष्टता की भावना को दर्शाता है जो आने वाली पीढ़ियों को निरंतर प्रेरित करती रहती है।

- नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री

समाजसेवा, शिक्षा, साहित्य एवं कला के क्षेत्र में पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित महानुभावों ने अनवरत योगदान देकर अनेक लोगों के जीवन में परिवर्तन लाया है। ये सम्मान भारत की सांस्कृतिक और बौद्धिक परिदृश्य को आकार देने में इनकी निरंतर भूमिका को दर्शाते हैं, जो पीपुल्स पद्म की वास्तविक भावना के अनुरूप हैं। पद्म सम्मान के लिए चयनित लोगों ने यह सिद्ध किया है कि सामाजिक दायित्वों का सजगता से निर्वहन करते हुए राष्ट्र निर्माण में प्रभावी सहयोग दिया जा सकता है। निश्चित रूप से अधिक लोगों को निःस्वार्थ भाव से समाज की सेवा करने के लिए प्रेरित करेंगे। ■



13 नायकों को पद्म भूषण



एस के एम मेइलानंदन
(सामाजिक कार्य)
तमिलनाडु



शतावधानी आर
गणेश (कला)
कर्नाटक



शिबू सोरेन
(मरणोपरांत)
(सार्वजनिक मामले)
झारखंड



उदय कोटक
(व्यापार और उद्योग)
महाराष्ट्र



वी. के. मल्होत्रा
(मरणोपरांत)
(सार्वजनिक मामले)
दिल्ली



वेल्लापल्ली नटेशन
(सार्वजनिक मामले)
केरल



विजय अमृतराज
(खेल) संयुक्त राज्य
अमेरिका

केरल से 'विकास की, रोजगार निर्माण की' नई पहल



केंद्र सरकार के प्रयासों से केरल के विकास को निरंतरता के साथ नई गति मिल रही है। बीते 23 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई विकास कार्यों को आगे बढ़ाया। यहीं से पूरे देश के लिए गरीब कल्याण से जुड़ी एक बड़ी शुरुआत करते हुए पीएम स्वनिधि क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया गया तो रेल कनेक्टिविटी को सशक्त बनाने, तिरुवनंतपुरम को देश का बड़ा स्टार्ट-अप हब बनाने जैसी पहल बढ़ी आगे...

कभी क्रेडिट कार्ड अमीरों तक ही सीमित होता था लेकिन अब देश भर के रेहड़ी-पटरी वाले लाखों लोगों को भी इसकी सुविधा मिलने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनवरी में केरल के तिरुवनंतपुरम से इसकी शुरुआत की। पिछले 11 वर्षों में करोड़ों देशवासियों को बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ने का बहुत बड़ा काम हुआ है। पहले सड़कों के किनारे, गलियों में सामान बेचने वाले स्ट्रीट वेंडर्स की स्थिति बहुत बुरी थी। उन्हें सामान खरीदने के लिए कुछ सौ रुपये भी महंगे ब्याज पर लेने पड़ते थे। केंद्र सरकार ने पहली बार इनके लिए पीएम स्वनिधि योजना बनाई। इस योजना के बाद देशभर में लाखों साथियों को बैंकों से बहुत मदद मिली है। लाखों स्ट्रीट वेंडर्स को जिंदगी में पहली बार बैंक से कोई लोन मिला है। अब भारत सरकार एक कदम आगे बढ़ते हुए, इन लोगों को क्रेडिट कार्ड दे रही है। इससे देशभर के रेहड़ी-ठेले, फुटपाथ पर काम करने वालों को लाभ होगा।

समान शहरी विकास हो रहा सुनिश्चित

भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए आज पूरा देश एकजुट होकर प्रयास कर रहा है। विकसित भारत के निर्माण में शहरों की बहुत बड़ी भूमिका है। बीते 11 वर्षों से केंद्र सरकार शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर विशेष रूप से निवेश कर रही है। केंद्र सरकार शहर के गरीब परिवारों के लिए भी काम कर रही है। पीएम आवास योजना के तहत देश में 4 करोड़ से अधिक घर बनाकर गरीबों को दिए गए हैं। इनमें शहरी गरीबों के लिए एक करोड़ से अधिक घर बनाए गए हैं। केरल में ही करीब सवा लाख शहरी गरीबों को भी पक्का घर मिला है। गरीब परिवारों का बिजली का बिल बचे, इसके लिए पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना शुरू की गई है। गरीबों को आयुष्मान भारत से 5 लाख रुपये का मुफ्त इलाज मिल रहा है। नारी-शक्ति की स्वास्थ्य सुरक्षा

विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला और उद्घाटन

रेल संपर्क, शहरी आजीविका, विज्ञान और इनोवेशन, जन-केंद्रित सेवाएं और उन्नत स्वास्थ्य सेवा सहित प्रमुख सेक्टर इसमें शामिल।

- पीएम स्वनिधि क्रेडिट कार्ड लॉन्च हुआ। यह यूपीआई से जुड़ी, ब्याज-मुक्त रिवॉल्विंग क्रेडिट सुविधा तत्काल नकदी उपलब्ध कराएगी, डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देगी और लाभार्थियों को औपचारिक क्रेडिट इतिहास बनाने में मदद करेगी।
- एक लाख लाभार्थियों को पीएम स्वनिधि ऋण वितरित किए गए। पीएम स्वनिधि स्कीम ने लाभार्थियों के एक बड़े हिस्से को पहली बार औपचारिक ऋण तक पहुंच प्रदान की है
- केरल में रेल संपर्क को बेहतर बनाने के लिए तीन अमृत भारत एक्सप्रेस और एक यात्री ट्रेन को हरी झंडी।
- इनमें नागरकोइल-मंगलुरु अमृत भारत एक्सप्रेस, तिरुवनंतपुरम-तंबूरम अमृत भारत एक्सप्रेस, तिरुवनंतपुरम-चारलापल्ली अमृत भारत एक्सप्रेस और त्रिशूर और गुरुवायूर के बीच चलने वाली एक नई यात्री ट्रेन शामिल हैं।
- इन सेवाओं के शुरू होने से केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बीच लंबी दूरी और क्षेत्रीय संपर्क में उल्लेखनीय सुधार होगा, इससे यात्रियों के लिए यात्रा अधिक किफायती, सुरक्षित और समयबद्ध हो जाएगी।
- तिरुवनंतपुरम में सीएसआईआर-एनआईआईएसटी इनोवेशन, टेक्नोलॉजी एंड एंटरप्रेन्योरशिप हब की आधारशिला रखी गई।
- तिरुवनंतपुरम के श्री चित्रा तिरुनल आयुर्वेद विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान में अत्याधुनिक रेडियो सर्जरी केंद्र की आधारशिला रखी गई।
- तिरुवनंतपुरम में पूजप्पुरा के नए डाकघर का भी उद्घाटन हुआ।



प्रधानमंत्री का पूरा कार्यक्रम देखने के लिए QR कोड स्कैन करें।

“बीते 11 वर्षों में करोड़ों देशवासियों को बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ने का बहुत बड़ा काम हुआ है। अब गरीब, एसी/एसटी/ओबीसी, महिला, फिशरमैन, इन सभी को भी आसानी से बैंक लोन मिलने लगे हैं। जिनके पास कोई गारंटी नहीं है, सरकार खुद उनकी गारंटर बन रही है।” — नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री

के लिए मातृ वंदना योजना जैसी योजना काम कर रही है। केंद्र सरकार ने 12 लाख रुपये तक की आय को टैक्स फ्री कर दिया है। इसका बहुत बड़ा फायदा केरल के लोगों को और विशेष रूप से मध्यम वर्ग को हुआ है।

केरल के विकास को नई गति

केंद्र सरकार कनेक्टिविटी, साइंस एंड इनोवेशन और हेल्थकेयर पर भी बहुत अधिक निवेश कर रही है। सीएसआईआर के इनोवेशन हब का लोकार्पण, मेडिकल कॉलेज में रेडियो सर्जरी सेंटर की

शुरुआत से केरल को साइंस, इनोवेशन और हेल्थकेयर का हब बनाने में मदद मिलेगी। इसी तरह केरल की रेल कनेक्टिविटी और सशक्त हुई है। तीन अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई गई। इससे टूरिज्म सेक्टर को लाभ होगा। गुरुवायूर से त्रिशूर के बीच नई पैसेंजर ट्रेन, तीर्थयात्रियों के लिए सफर को और आसान बनाएगी। इन सारी परियोजनाओं से केरल के विकास को भी गति मिलेगी। निश्चित रूप से विकसित केरल से ही विकसित भारत का सपना पूरा होगा। इसमें केंद्र सरकार पूरी शक्ति से केरल के लोगों के साथ खड़ी है। ■

...ताकि संत परंपरा और विरासत से जुड़ी रहे भावी पीढ़ी

अब श्री गुरु रविदास महाराज जी हवाई अड्डा, आदमपुर कहिए



भारत विकास के साथ विरासत को भी भावी पीढ़ी से जोड़ने और उसे संजोने का काम कर रही है। इसी कड़ी में भारत के लिए न्याय और करुणा भाव के साथ भविष्य की एक संकल्पना पेश करने वाले संत रविदास की 649वीं जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंजाब दौरे पर पहुंचे। यहां एक हवाई अड्डे के टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया तो वहीं संत परंपरा और विरासत को भावी पीढ़ी से जोड़ने के लिए आदमपुर हवाई अड्डे को दिया नया नाम 'श्री गुरु रविदास महाराज जी हवाई अड्डा, आदमपुर'...

समाज सुधारक और संत रविदास महाराज ने राष्ट्र को सेवा का मार्ग दिखाया। सामाजिक समरसता और सद्भावना का दीप प्रज्वलित कर समानता, करुणा और मानवीय गरिमा की शिक्षाएं दी जो भारत के सामाजिक मूल्यों को प्रेरित करती हैं। गुरु रविदास महाराज की जयंती पर पंजाब पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह निर्णय लिया गया है कि आदमपुर हवाई अड्डे को अब से श्री गुरु रविदास महाराज जी हवाई अड्डे के नाम से जाना जाएगा। यह श्री गुरु रविदास महाराज जी के चिरस्थायी आदर्शों को एक उपयुक्त श्रद्धांजलि है। समानता, करुणा और सेवा का उनका संदेश हम सभी को अत्यधिक प्रेरित करता है।

राज्य के विमानन इंफ्रास्ट्रक्चर को और आगे बढ़ाते हुए, हलवारा विमान पत्तन पर नए टर्मिनल भवन का प्रधानमंत्री मोदी ने उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने कहा कि हलवारा हवाई अड्डे पर टर्मिनल भवन का उद्घाटन होना पंजाब, विशेषकर लुधियाना और आसपास के लोगों के लिए अपार खुशी का क्षण है। लुधियाना



मानवता के अनन्य उपासक महान संत श्री गुरु रविदास महाराज जी को उनकी जयंती पर कोटि-कोटि नमन। उनके विचारों में न्याय और करुणा का भाव सर्वोपरि था जो जनकल्याण की हमारी योजनाओं के मूल में है। उन्होंने सामाजिक समरसता और सद्भावना के जिस दीप को प्रज्वलित किया, वह देशवासियों के पथ को सदैव आलोकित करता रहेगा।

- नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री

रविदास महाराज को श्रद्धांजलि

- आदमपुर हवाई अड्डे का नया नाम 'श्री गुरु रविदास महाराज जी हवाई अड्डा, आदमपुर' रखा गया।
- आदमपुर विमानपत्तन का नामकरण संत और समाज सुधारक गुरु रविदास महाराज का सम्मान है, जिनकी समानता, करुणा और मानवीय गरिमा की शिक्षाएं सामाजिक मूल्यों को प्रेरित करती हैं।



उत्तरी भारत का एक महत्वपूर्ण औद्योगिक और वाणिज्यिक केंद्र है। यह शहर अपने ऊर्जावान लोगों के लिए जाना जाता है। हमारी सरकार इस शहर के हवाई संपर्क को बेहतर बनाने के लिए अथक प्रयास कर रही है जो आधुनिक हवाई अड्डे के लिए चल रहे कार्यों में परिलक्षित होता है।

प्रधानमंत्री ने डेरा सचखंड बल्लां के दर्शन किए

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब में डेरा सचखंड बल्लां के दर्शन किए। पीएम मोदी ने कहा कि "श्री गुरु रविदास महाराज जी की जयंती पर डेरा सचखंड बल्लां में होना एक बहुत ही खास एहसास था।"

पीएम मोदी ने संत निरंजन दास जी से की मुलाकात

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डेरा सचखंड बल्लां में संत निरंजन दास जी से मुलाकात के बाद कहा कि संत निरंजन दास जी से मिलना बहुत खास था। समाज के प्रति उनकी प्रेरणादायक सेवा को मान्यता देते हुए उन्हें हाल ही में पद्म श्री से सम्मानित किया गया है। ■



प्रधानमंत्री का पूरा कार्यक्रम देखने के लिए QR कोड स्कैन करें।

लुधियाना में हलवारा विमान पत्तन के टर्मिनल भवन का उद्घाटन

- पंजाब में विमानन इंफ्रास्ट्रक्चर को और आगे बढ़ाते हुए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब के लुधियाना में हलवारा विमान पत्तन के टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया।
- यह टर्मिनल भवन राज्य के लिए एक नया प्रवेश द्वार स्थापित करेगा जो लुधियाना और उसके आसपास के औद्योगिक और कृषि क्षेत्रों की आवश्यकताओं को पूरा करेगा।
- लुधियाना जिले में स्थित हलवारा में भारतीय वायु सेना का एक रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण स्टेशन भी है।
- लुधियाना में पहले विमान पत्तन का रनवे अपेक्षाकृत छोटा था जो छोटे आकार के विमानों के लिए उपयुक्त था।
- संपर्क में सुधार और बड़े विमानों को समायोजित करने के लिए हलवारा में एक नया सिविल एन्वलेव विकसित किया गया है। इसका रनवे लंबा है और ए-320 जैसे विमानों की आवाजाही के लिए सक्षम है।
- प्रधानमंत्री के सतत और पर्यावरण के प्रति उत्तरदायी विकास के दृष्टिकोण के अनुरूप, टर्मिनल में कई हरित और ऊर्जा दक्ष सुविधाएं शामिल हैं।
- एलईडी प्रकाश व्यवस्था, इंसुलेटेड छत, वर्षा जल संचयन प्रणाली, सीवेज और जल शोधन संयंत्र तथा पुनर्चक्रित जल का उपयोग शामिल है।
- टर्मिनल का डिजाइन पंजाब की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को दर्शाता है। यह यात्रियों को एक विशिष्ट और क्षेत्रीय रूप से प्रेरित यात्रा का अनुभव प्रदान करती है।



भारत में हवाई यात्रा अब चुनिंदा नहीं, आमजन तक

भारत का नागर विमानन क्षेत्र आज देश के सबसे तेजी से विकसित होते क्षेत्रों में शामिल हो चुका है। एक समय था जब हवाई यात्रा कुछ चुनिंदा लोगों तक सीमित मानी जाती थी लेकिन आज भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार बन चुका है। यात्रियों की संख्या में निरंतर वृद्धि के साथ-साथ देश का विमान के बेड़े में भी तेजी से विस्तार कर रहा है। इसी पृष्ठभूमि में विमानन इंफ्रास्ट्रक्चर के आधुनिकीकरण को नई गति देने के उद्देश्य से हैदराबाद में 28 जनवरी को आयोजित 'विंग्स इंडिया 2026' कार्यक्रम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया संबोधित...

भारत अभी हवाई यात्रा को चुनिंदा लोगों के क्लब से बाहर निकालकर आमजन तक ले आया है। भारतीय विमानन क्षेत्र ने देश की आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा देने, मजबूती से राष्ट्र के एकीकरण और भारत को विकसित राष्ट्र बनने के अपने लक्ष्य-विकसित भारत @2047 की ओर आत्मविश्वास से बढ़ने के लिए सशक्त भी किया है। इसी कड़ी में एशिया के सबसे बड़े नागरिक विमानन कार्यक्रम विंग्स इंडिया 2026 में भारत ने न केवल देश की विमानन विकास गाथा को प्रदर्शित किया बल्कि वैश्विक स्तर पर नागरिक उड्डयन में देश में मौजूद अवसरों से भी निवेशकों को अवगत कराया। यह आयोजन 28-31 जनवरी तक तेलंगाना के हैदराबाद में चला।

'भारतीय विमानन: भविष्य का मार्ग प्रशस्त करना-डिजाइन से तैनाती तक, विनिर्माण से रखरखाव तक, समावेशिता से नवाचार तक और सुरक्षा से स्थिरता तक' विषय पर आधारित विंग्स इंडिया 2026 अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में 13 विषय पर सत्रों के अलावा

मंत्रिस्तरीय सत्र भी हुआ। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विमानन उद्योग का अगला दौर उम्मीदों से भरा हुआ है जिसमें भारत एक अहम प्लेयर के रूप में उभर रहा है। विमान निर्माण, पायलट प्रशिक्षण, एडवांस्ड एयर मोबिलिटी और विमान लीजिंग ऐसे क्षेत्र हैं, जिन्हें लेकर भारत में दुनिया की विमानन कंपनियों के लिए निवेश के बेहतरीन अवसर उपलब्ध हैं।

2047 में होंगे 400 से ज्यादा एयरपोर्ट

देश की एयर-एक्टिविटी का कई गुणा विस्तार हो रहा है। अनुमान है कि 2047 तक भारत में 400 से अधिक हवाई अड्डे होंगे। भारत सरकार उड़ान योजना के अगले चरण पर भी काम कर रही है। इस पॉलिसी से, क्षेत्रीय और किफायती कनेक्टिविटी और मजबूत होगी। सी-प्लेन परिचालन का भी विस्तार किया जा रहा है। पीएम मोदी ने कार्यक्रम में कहा, "हमारी कोशिश यही है कि भारत के कोने-कोने में एयर-कनेक्टिविटी और बेहतर हो। देशभर में टूरिस्ट

भारत की उड़ान के को-पायलट बनें

दुनिया के ऐसे कुछ ही देश हैं, जहां विमानन उद्योग के लिए ऐसा बड़ा स्केल, नीति स्थिरता और तकनीकी महत्वाकांक्षा है। भारत विमानन क्षेत्र में बहुत सारे रिफॉर्म कर रहा है। इन प्रयासों के कारण भारत ग्लोबल साउथ और दुनिया के बीच एक बड़ा एविएशन गेटवे बना रहा है। यह एविएशन सेक्टर से जुड़े निवेशक और निर्माताओं के लिए बहुत बड़ा अवसर है। प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया भर के निवेशकों से कहा कि वो इस स्वर्णिम अवसर का लाभ उठाएं। हमारी इस विकास यात्रा में एक दीर्घकालिक साझेदार बनकर विश्व के विमानन क्षेत्र की गोथ के लिए काम करें।



प्रधानमंत्री का पूरा कार्यक्रम देखने के लिए QR कोड स्कैन करें।

विमानन क्षेत्र में भारत के लॉन्ग टर्म विजन से बड़ी सुविधाएं

- टीयर-2 और टीयर-3 शहरों को एयरपोर्ट से जोड़ा गया है।
- साल 2014 में भारत में 70 एयरपोर्ट थे जो एक दशक में दोगुना से अधिक 160 हो गए हैं।
- भारत के हवाई यात्रियों की संख्या 2014 में 10.3 करोड़ से बढ़कर 2025 में 35 करोड़ को पार कर गई।
- देश में 100 से अधिक एयर डोम्स एक्टिवेट किए गए हैं।
- नागरिकों के लिए किफायती किराए वाली उड़ान स्कीम लॉन्च की है।
- उड़ान स्कीम के कारण, 1.5 करोड़ यात्रियों ने उन रूट पर यात्रा की है, जिनमें से कई पहले अस्तित्व में भी नहीं थे।



वह दिन दूर नहीं, जब भारत में डिजाइन और निर्मित किए गए इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक-ऑफ एंड लैंडिंग एयरक्राफ्ट पूरे एविएशन सेक्टर को नई दिशा देंगे। यह टेकरोलॉजी हमारे ट्रेवल टाइम को बहुत कम कर सकती है। हम टिकाऊ विमान ईंधन पर भी बड़ा काम कर रहे हैं। अगले कुछ वर्षों में भारत हरित विमान ईंधन का एक बड़ा निर्माता और निर्यातक बनने की ओर अग्रसर है।

-नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री

प्लेस विकसित हो रहे हैं, जहां पहुंचने में लोगों की पहली पसंद हवाई यात्रा ही है। आने वाले समय में, हवाई यात्रा की मांग में और भी वृद्धि होने वाली है। ऐसे में निवेश के और ज्यादा अवसर बनेंगे।

विमानन जरूरतों के लिए दूसरों पर न रहें निर्भर

पीएम मोदी ने विंग्स इंडिया 2026 में आग्रह किया कि आज जब भारत, एक बड़ा ग्लोबल एविएशन हब बन रहा है, तब यह भी जरूरी है कि हम एविएशन से जुड़ी जरूरतों के लिए दूसरों पर निर्भर न रहें। हमें आत्मनिर्भरता का रास्ता मजबूत करना ही होगा। यह भारत में इंवेस्ट करने आ रही कंपनियों के लिए भी मददगार होगा। इसी सोच के साथ भारत एयरक्राफ्ट डिजाइन, एयरक्राफ्ट मैनुफैक्चरिंग और एयरक्राफ्ट एमआरओ इकोसिस्टम पर जोर दे रहा है। आज भी भारत, एयरक्राफ्ट पार्ट का एक बड़ा निर्माता और आपूर्तिकर्ता है। भारत मिलिट्री और ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट देश में बनाना शुरू कर रहा है। सिविल एयरक्राफ्ट मैनुफैक्चरिंग की दिशा में भी आगे बढ़ रहा है। ■



भारतीय निर्वाचन आयोग

लोकतंत्र की वैश्विक आवाज

भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। करीब 97 करोड़ मतदाता पंजीकृत हैं तो 700 से अधिक राजनीतिक दल भी हैं। भारत ने अंतरराष्ट्रीय लोकतंत्र एवं निर्वाचन सहायता संस्थान के सदस्य राष्ट्रों की परिषद की अध्यक्षता भी ग्रहण की है। लोकतंत्र की इस समृद्ध परंपरा और निष्पक्ष, पारदर्शी एवं समावेशी चुनाव प्रक्रिया को वैश्विक मंच पर साझा करने के उद्देश्य से भारतीय निर्वाचन आयोग ने 21 से 23 जनवरी तक तीन दिवसीय भारत अंतरराष्ट्रीय लोकतंत्र एवं चुनाव प्रबंधन सम्मेलन 2026 का आयोजन किया। इस आयोजन ने चुनाव प्रबंधन में भारत की भूमिका की और सुदृढ़...

अं तरराष्ट्रीय सम्मेलन ने चुनाव प्रबंधन निकायों, नीति-निर्माताओं और विशेषज्ञों को एक साझा मंच प्रदान किया, जहां चुनावी प्रक्रियाओं में नवाचार, तकनीकी हस्तक्षेप और मतदाता सहभागिता जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विचार-विमर्श किया गया। अपनी तरह का यह पहला सम्मेलन था जिसमें 42 विदेशी दूतावास के अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधियों तथा 27 देशों के मिशन प्रमुखों सहित एक हजार से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने इस दौरान 32 देशों के चुनाव प्रबंधन निकायों के प्रमुख के साथ द्विपक्षीय बैठक की। बैठक में वैश्विक चुनावी अनुभवों और नवाचार पर विस्तृत चर्चा हुई। इसका उद्देश्य चुनाव प्रबंधन और लोकतांत्रिक सहयोग में भारत की दीर्घकालिक साझेदारी को

और अधिक मजबूत करना था। भारत ने आमंत्रित देशों के चुनाव प्रबंधन निकायों (ईएमबी) को उनके संबंधित देशों के कानूनों के अनुसार ईसीआईनेट जैसे तकनीकी प्लेटफॉर्म विकसित करने में सहयोग करने का प्रस्ताव दिया। इसमें कई चुनाव प्रबंधन निकायों ने अपने देशों में इसी तरह के तकनीकी समाधान अपनाने के लिए भारत के साथ सहयोग करने में रुचि दिखाई।

समापन सत्र के दौरान, मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने 'दिल्ली घोषणा पत्र 2026' प्रस्तुत किया, जिसे सभी निर्वाचन प्रबंधन निकायों द्वारा सर्वसम्मति से अपनाया गया। निर्वाचन प्रबंधन निकायों ने घोषणा के पांच प्रमुख स्तंभों - मतदाता सूचियों की शुद्धता, चुनाव प्रक्रिया संचालन, अनुसंधान एवं प्रकाशन, प्रौद्योगिकी के उपयोग और प्रशिक्षण

मतदाता ही लोकतंत्र की असली ताकत

लोकतंत्र में मतदाता सर्वोपरि है। उसकी भागीदारी बढ़ाने के लिए भारत निर्वाचन आयोग लगातार प्रयास करता है। इसी कड़ी में 25 जनवरी को 16वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2026 मनाया गया। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने पांच नव पंजीकृत युवा मतदाताओं को मतदाता फोटो पहचान पत्र सौंपे और कहा कि यह पहचान पत्र आपको विश्व के सबसे बड़े और जीवंत लोकतंत्र में सक्रिय भागीदारी का अमूल्य अधिकार प्रदान करता है। सभी युवा मतदाता बहुत जिम्मेदारी के साथ मताधिकार का प्रयोग कर राष्ट्र निर्माण में अपनी भागीदारी निभाएं। वहीं चुनावों में भारी संख्या में मतदान करने वाली माता-बहनों को बधाई देते हुए कहा कि ये गणतंत्र को अधिक शक्तिशाली बना रही हैं।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने कहा कि आधुनिक लोकतंत्र के संदर्भ में दो तिथियां बहुत महत्वपूर्ण हैं। 26 नवंबर 1949 को जिस दिन संविधान को अपनाया गया और 26 जनवरी, 1950 जिस दिन संविधान को पूरी तरह से लागू किया। संविधान के केवल 16 अनुच्छेद ऐसे थे जो 26 नवंबर, 1949 के दिन ही तत्काल प्रभाव से लागू कर दिए गए थे। उनमें से एक अनुच्छेद 324 भी था जिसके तहत 26 जनवरी, 1950 यानी गणतंत्र की स्थापना के एक दिन पहले ही, 25 जनवरी, 1950 को निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई। उसी उपलक्ष्य में लोकतंत्र का विशेष उत्सव मनाया जाता है। देश में मतदाताओं की संख्या 95 करोड़ से अधिक है लेकिन लोकतंत्र की शक्ति केवल संख्या की विशालता में नहीं है बल्कि लोकतांत्रिक भावना की गहराई में भी है।

16 वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस

भारत निर्वाचन आयोग ने 25 जनवरी को 16वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस (एनवीडी-2026) मनाया, जिसका विषय “मेरा भारत, मेरा मत-भारतीय लोकतंत्र के केंद्र में नागरिक” रहा। यह विषय हमारे लोकतंत्र की भावना को व्यक्त करती है।

विभिन्न श्रेणियों में मिले पुरस्कार

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने विभिन्न श्रेणियों में सर्वश्रेष्ठ चुनावी प्रक्रियाओं के पुरस्कार भी प्रदान किए। इनमें बिहार, केरल और तमिलनाडु को तकनीक के प्रभावी उपयोग के लिए, ओडिशा, मेघालय और बिहार को चुनाव प्रबंधन एवं लॉजिस्टिक्स की श्रेणी में, बिहार, गुजरात और केरल को रचनात्मक मतदाता जागरूकता के लिए, मिजोरम और बिहार को आदर्श आचार संहिता के कार्यान्वयन एवं प्रवर्तन के लिए, बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड को प्रशिक्षण एवं क्षमता के विकास के लिए पुरस्कार मिले।

दो प्रकाशन का विमोचन

कार्यक्रम में दो प्रकाशनों “2025: पहल और नवाचारों का वर्ष” और “चुनाव का पर्व, बिहार का गर्व”, जोकि बिहार में आम चुनावों के सफल संचालन पर आधारित प्रकाशन है, का विमोचन किया गया। इसमें 2025 के दौरान चुनावी प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए किए गए 30 से अधिक प्रयासों का दस्तावेजीकरण भी किया गया है।



“आज के मतदाता, भारत के भविष्य-निर्माता भी हैं। मतदान का अधिकार जितना महत्वपूर्ण है उतना ही महत्वपूर्ण यह भी है कि सभी वयस्क नागरिक अपने संवैधानिक कर्तव्यों को ध्यान में रखते हुए अपने मताधिकार का प्रयोग करें। मैं आशा करती हूं कि हमारे सभी मतदाता प्रलोभन, अनभिज्ञता, भ्रामक सूचना, दुष्प्रचार और पूर्वाग्रह से मुक्त रहते हुए, अपने विवेक के बल पर हमारी निर्वाचन व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखेंगे। - द्रौपदी मुर्मु, राष्ट्रपति

व क्षमता निर्माण पर सामूहिक रूप से कार्य करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। सभी प्रतिभागियों ने अपनी प्रगति की समय-समय पर समीक्षा करने का भी संकल्प लिया। सम्मेलन में 3, 4 तथा 5 दिसंबर

2026 को नई दिल्ली स्थित भारतीय अंतरराष्ट्रीय लोकतंत्र एवं चुनाव प्रबंधन संस्थान (आईआईआईडीईएम) में बैठक आयोजित करने का प्रस्ताव रखा गया। ■



राष्ट्रपति का पूरा कार्यक्रम देखने के लिए QR कोड स्कैन करें।



नियुक्त पत्र

राष्ट्र निर्माण का निमंत्रण पत्र

भारत आज दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक है। ऐसे में केंद्र सरकार का निरंतर प्रयास है कि भारत की युवाशक्ति के लिए देश-दुनिया में नए-नए अवसर बनें। इसी कड़ी में 24 जनवरी को 61 हजार से अधिक युवाओं को रोजगार मेले में सरकारी सेवा के लिए नियुक्ति पत्र सौंपे गए। नियुक्ति पत्र वितरण के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज आप सबको सरकारी सेवाओं के नियुक्ति पत्र मिल रहे हैं जो एक तरह से राष्ट्र निर्माण का निमंत्रण पत्र है। यह विकसित भारत के निर्माण को गति देने का भी है संकल्प पत्र...

युवाओं को कौशल से जोड़ना और उन्हें रोजगार-स्वरोजगार के अवसर देना, केंद्र सरकार की प्राथमिकता रही है। इसी कड़ी में सरकारी भर्तियों को मिशन मोड पर लाने के लिए रोजगार मेले की शुरुआत की गई। यही कारण है कि बीते वर्षों में रोजगार मेला एक इंस्टीट्यूशन बन गया है। इसके जरिए लाखों युवाओं को सरकार के अलग-अलग विभागों में नियुक्ति पत्र मिल चुके हैं। रोजगार मेले के तहत नियुक्ति पत्र वितरण के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आप में से बहुत सारे साथी देश की सुरक्षा को मजबूत करेंगे। एजुकेशन और हेल्थ केयर इकोसिस्टम को और सशक्त करेंगे। कई साथी वित्तीय सेवाओं और एनर्जी सिक्योरिटी को मजबूती देंगे तो कई

युवा सरकारी कंपनियों की ग्रोथ में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। मैं आप सभी युवाओं को बहुत-बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ।

रोजगार मेले में 8 हजार से ज्यादा लड़कियों को भी नियुक्ति पत्र मिले। बीते 11 वर्षों में, देश की वर्कफोर्स में महिला भागीदारी में करीब दोगुनी बढ़ोतरी हुई है। सरकार की मुद्रा और स्टार्टअप इंडिया जैसी योजनाओं का बहुत बड़ा फायदा महिलाओं को हुआ है। महिला स्व-रोजगार की दर में करीब 15% की बढ़ोतरी हुई है।

युवाओं को मिल रहे हैं नए-नए अवसर

बीते समय में भारत ने आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अभूतपूर्व निवेश किया है। इससे कंस्ट्रक्शन से जुड़े हर सेक्टर में रोजगार

रोजगार मेलों के माध्यम से 11 लाख से अधिक भर्ती पत्र जारी

- रोजगार मेला की शुरुआत के बाद से, देश भर में आयोजित रोजगार मेलों के माध्यम से 11 लाख से अधिक भर्ती पत्र जारी किए जा चुके हैं।
- देश भर में 45 स्थानों पर 18वां रोजगार मेला आयोजित किया गया।
- भारत के सभी हिस्सों से चयनित नवनियुक्त उम्मीदवार गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग, उच्च शिक्षा विभाग आदि सहित भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में कार्यभार ग्रहण करेंगे।



प्रधानमंत्री का पूरा कार्यक्रम देखने के लिए QR कोड स्कैन करें।



आज भारत पर जिस तरह दुनिया का भरोसा बढ़ रहा है, वो भी युवाओं के लिए अनेक नई संभावनाएं बना रहा है। भारत ने एक दशक में जीडीपी को डबल किया है। वर्ष 2014 से पहले के दस वर्षों की तुलना में भारत में ढाई गुना से अधिक एफडीआई आया है। ज्यादा विदेशी निवेश का अर्थ है, भारत के युवाओं के लिए रोजगार के अनगिनत अवसर।

- नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री

युवाओं को सरकारी नौकरी देने के लिए रोजगार मेला

कब हुआ	नियुक्ति पत्र दिए
22 अक्टूबर 2022	75 हजार से ज्यादा
22 नवंबर 2022	71 हजार से अधिक
20 जनवरी 2023	71 हजार से अधिक
13 अप्रैल 2023	71 हजार से अधिक
16 मई 2023	70 हजार से अधिक
13 जून 2023	70 हजार से अधिक
22 जुलाई 2023	70 हजार से अधिक
28 अगस्त 2023	51 हजार से अधिक
26 सितंबर 2023	51 हजार से अधिक
28 अक्टूबर 2023	51 हजार से अधिक
30 नवंबर 2023	51 हजार से अधिक
12 फरवरी 2024	1 लाख से अधिक
29 अक्टूबर 2024	51 हजार से अधिक
23 दिसंबर 2024	71 हजार से अधिक
26 अप्रैल 2025	51 हजार से अधिक
12 जुलाई 2025	51 हजार से अधिक
24 अक्टूबर 2025	51 हजार से अधिक
24 जनवरी 2026	61 हजार से अधिक

बहुत बढ़े हैं। भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम का दायरा भी तेज गति से आगे बढ़ रहा है।

आज देश में करीब दो लाख स्टार्टअप हैं। इनमें इक्कीस लाख से ज्यादा युवा काम कर रहे हैं। इसी प्रकार, डिजिटल इंडिया ने एक नई इकोनॉमी को विस्तार दिया है। एनिमेशन, डिजिटल मीडिया जैसे अनेक क्षेत्रों में भारत एक ग्लोबल हब बनता जा रहा है। भारत की क्रिएटर इकोनॉमी बहुत तेज गति से बढ़ रही है। इसमें भी युवाओं को नए-नए अवसर मिल रहे हैं।

बड़ी मैनुफैक्चरिंग पावर बनता जा रहा है भारत

आज भारत एक बड़ी मैनुफैक्चरिंग पावर बनता जा रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स, दवाएं-वैक्सीन, डिफेंस, ऑटो, ऐसे अनेक क्षेत्र में भारत के उत्पादन और निर्यात, दोनों में अभूतपूर्व वृद्धि हो रही है। 2014 के बाद से भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण में छह गुना वृद्धि हुई है। आज यह 11 लाख करोड़ रुपये से अधिक की इंडस्ट्री है। इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात भी चार लाख करोड़ रुपये को पार कर चुका है। भारत की ऑटो इंडस्ट्री भी सबसे तेजी से ग्रो करने वाले सेक्टर में से एक बन गई है। वर्ष 2025 में टू-व्हीलर की बिक्री दो करोड़ के पार पहुंच चुकी है। ■

राष्ट्रीय चेतना का उत्सव

नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नाम ऐसा है, जिनके स्मरण मात्र से मन में देश प्रेम का ज्वार उमड़ पड़ता है। उन्होंने युवाओं को संगठित कर आजाद हिंद फौज बनाकर प्रथम सैन्य अभियान चलाया। अंडमान-निकोबार में तिरंगा फहराकर वर्ष 1943 में ही आजाद भारत की घोषणा कर दी। उनकी जयंती 23 जनवरी को देश वर्ष 2021 से पराक्रम दिवस के रूप में मनाता है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पराक्रम दिवस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पराक्रम दिवस, देश की राष्ट्रीय भावना और राष्ट्रीय चेतना का बन गया है एक अभिन्न पर्व...

नेताजी सुभाष चंद्र बोस आजादी की लड़ाई के महानायक के साथ ही, स्वतंत्र भारत के महान स्वप्न-दृष्टा थे। उन्होंने एक ऐसे भारत की संकल्पना की थी, जिसका स्वरूप आधुनिक हो और उसकी आत्मा भारत की पुरातन चेतना से जुड़ी हो। नेताजी के इस विजन से आज की पीढ़ी को परिचित कराना, सभी का दायित्व है। केंद्र सरकार इस दायित्व को बखूबी निभा रही है। कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कहा कि उन पर किए गए विभिन्न कार्य केवल नेताजी सुभाष चंद्र बोस का सम्मान ही नहीं हैं। यह युवा पीढ़ी और भविष्य के भी अमर प्रेरणा के स्रोत हैं। अपने आदर्शों का यह सम्मान, उनसे प्रेरणा, यही विकसित भारत के हमारे संकल्प को ऊर्जा और आत्मविश्वास से भर रहा है।

एक कमजोर राष्ट्र का अपने लक्ष्यों तक पहुंचना मुश्किल होता है। इसलिए नेताजी सुभाष ने हमेशा सशक्त राष्ट्र का सपना देखा। पीएम मोदी ने कहा कि आज 21वीं सदी का भारत भी एक सशक्त और दृढ़ प्रतिज्ञा राष्ट्र के तौर पर अपनी पहचान बना रहा है। भारत आज शक्ति बढ़ाना, शक्ति संभालना और उसका इस्तेमाल करना भी जानता है। नेताजी सुभाष के समर्थ भारत के विजन पर चलते हुए, आज हम डिफेंस सेक्टर को आत्मनिर्भर बनाने में जुटे हैं। पहले भारत



प्रधानमंत्री का पूरा कार्यक्रम देखने के लिए QR कोड स्कैन करें।



नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर हम उनके अडिग साहस, संकल्प और राष्ट्र के प्रति उनके अद्वितीय योगदान को याद करते हैं। उन्होंने निडर नेतृत्व और अटल देशभक्ति का प्रतीक प्रस्तुत किया। उनके आदर्श पीढ़ियों को एक मजबूत भारत बनाने के लिए प्रेरित करते रहते हैं।

- नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री

पराक्रम दिवस

- उस विरासत को नमन, जिसने असंभव को चुनौती दी।
- उस साहस की याद, जिसने इतिहास की धारा बदली।
- उन मूल्यों की पुनः पुष्टि, जिन्होंने भारत की आजादी की लड़ाई को आकार दिया।

सिर्फ विदेशों से मंगाए हथियार पर आश्रित रहता था। जबकि आज रक्षा निर्यात 23 हजार करोड़ को पार कर चुका है। भारत में बनी ब्रह्मोस और दूसरी मिसाइलें, कितने ही देशों का ध्यान खींच रही हैं।

सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार - 2026

सिक्किम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को संस्थागत श्रेणी और लेफ्टिनेंट कर्नल सीता अशोक शेल्के को व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार - 2026 के लिए चुना गया। भारत सरकार ने आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में भारत में व्यक्ति और संगठनों द्वारा दिए गए अमूल्य योगदान और निस्वार्थ सेवा को पहचानने एवं सम्मानित करने के लिए सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार

नेताजी के जीवन और आदर्शों को लोकप्रिय बनाने के प्रयास

- पीएम मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए आईटी क्षेत्र को रूपांतरित करने वाली नेताजी से जुड़ी एक अग्रणी ई-ग्राम विश्वग्राम योजना 23 जनवरी 2009 को लॉन्च की।
- पीएम मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए 2012 में आजाद हिंद फौज दिवस पर अहमदाबाद में एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया था।
- नेताजी से संबंधित फाइलों और दस्तावेजों को सार्वजनिक किया गया।
- साल 2018 में आजाद हिंद सरकार की स्थापना की 75वीं वर्षगांठ लाल किले पर मनाई गई। वहां पीएम मोदी ने तिरंगा फहराया।
- अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के श्रीविजयपुरम (तत्कालीन पोर्ट ब्लेयर) में नेताजी नेताजी द्वारा वहां राष्ट्रीय ध्वज फहराने की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर तिरंगा फहराया गया।
- अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के तीन प्रमुख द्वीपों के नाम बदले गए। इसमें रॉस द्वीप को अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप के नाम से जाना जाता है।
- लाल किले में स्थित क्रांति मंदिर संग्रहालय में नेताजी और इंडियन नेशनल आर्मी से संबंधित महत्वपूर्ण ऐतिहासिक सामग्री रखी गई है। इसमें नेताजी द्वारा पहनी गई टोपी भी शामिल है।
- 2021 में भारत सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में घोषित किया।
- 13 सितंबर, 2024 में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर 'श्री विजयपुरम' करने का निर्णय लिया गया।
- औपनिवेशिक मानसिकता को छोड़ने और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के प्रति श्रद्धांजलि के तौर पर इंडिया गेट के पास उनकी प्रतिमा स्थापित की गई।

की स्थापना की है। साथ ही, देश में आपदा प्रबंधन की पद्धतियों, तैयारियों, आपदा न्यूनीकरण और आपदा से निपटने के तौर-तरीकों में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। इसके परिणामस्वरूप प्राकृतिक आपदाओं के दौरान मृत्यु दर में काफी कमी आई है।

13 स्थानों पर पराक्रम दिवस का आयोजन

अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में आयोजित मुख्य समारोह के साथ-साथ, पराक्रम दिवस देशभर के 13 प्रमुख स्थान कटक, कोडालिया, रामगढ़, हरिपुरा, जबलपुर, कोलकाता, मुर्शिदाबाद, डलहौजी, दिल्ली, मोइरांग, कोहिमा, गोमो और मेरठ में भी मनाया गया। यह स्थान नेताजी के जीवन और विरासत से करीब से जुड़े हैं। ■



राष्ट्रीय कैडेट कोर

आत्मविश्वासी-अनुशासित युवा शक्ति

नेशनल कैडेट कोर (एनसीसी) एक ऐसा संगठन, एक ऐसा आंदोलन है जो भारत की युवाशक्ति को आत्मविश्वासी, अनुशासित- संवेदनशील और राष्ट्र के लिए समर्पित नागरिक बनाता है। एनसीसी में शामिल होने वाले कैडेट की संख्या बीते वर्षों में 14 लाख से बढ़कर 20 लाख पहुंच गई है। एनसीसी गणतंत्र दिवस शिविर 2026 के समापन पर दिल्ली के करियाप्पा परेड ग्राउंड में आयोजित वार्षिक एनसीसी पीएम रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा- एनसीसी हर साल अपनी भूमिका को कर रहा है और सशक्त...

एनसीसी, युवाओं का मंच है। इस मंच पर अपनी विरासत को गौरव के साथ जीया जाता है। जैसे इस वर्ष वंदे मातरम् के 150 वर्ष होने का उत्सव एनसीसी ने पूरे जोश से मनाया। परमवीर सागर यात्रा भी इसी का एक बेहतरीन उदाहरण है। एनसीसी रैली में परमवीर सागर यात्रा को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आप सभी जानते हैं कि कुछ साल पहले सरकार ने अंडमान-निकोबार के 21 द्वीपों को परमवीर चक्र विजेताओं के नाम दिए थे। इसके पीछे राष्ट्र-नायकों को सम्मान देने का जो भाव था, उसको नौकायन अभियान से आगे बढ़ाया गया है। इसी तरह, लक्षद्वीप में द्वीप-उत्सव के माध्यम से आपने सागर, संस्कृति, प्रकृति सबको एक साथ सेलिब्रेट किया गया है।

पीएम मोदी ने एनसीसी कैडेट की सराहना करते हुए कहा

कि एनसीसी ने इतिहास को स्मारकों से निकालकर जन-जन के हृदय में जीवंत बनाया है। एनसीसी ने बाजीराव पेशवा की वीरता, महायोद्धा लसित बोरफुकन की कुशलता और भगवान बिरसा मुंडा के नेतृत्व को अपनी साइकिल रैली के माध्यम से जन चेतना जगाने का काम किया। आज पूरी दुनिया युवा भारत के युवाओं की तरफ बहुत भरोसे से देख रही है। इस भरोसे का कारण है, स्किल और संस्कार। भारत के युवाओं के पास लोकतंत्र के संस्कार हैं, हर प्रकार की विविधता को सम्मान देने के संस्कार हैं, साथ में पूरी दुनिया को एक परिवार मानने के संस्कार हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने रैली में कहा कि इसलिए, भारत के युवा कहीं भी जाते हैं तो उस देश के लोगों के साथ आसानी से घुल-मिल जाते हैं, उनके दिलों को जीत लेते हैं। हम अपने सामर्थ्य से उस देश के विकास में मदद करते हैं। यही

एनसीसी कैडेट्स की संख्या 20 लाख

बीते वर्षों में एनसीसी कैडेट्स की संख्या 14 लाख से बढ़कर 20 लाख हो चुकी है। खासकर सीमावर्ती इलाके और तटीय क्षेत्र में एनसीसी कैडेट्स की संख्या में काफी वृद्धि हुई है। एनसीसी ने 'एक पेड़ मां के नाम' के अभियान के तहत करीब 8 लाख पौधे भी लगाए हैं।

रैली की थीम

'राष्ट्र प्रथम - कर्तव्य निष्ठ युवा'

- वार्षिक एनसीसी पीएम रैली 2026 का विषय 'राष्ट्र प्रथम-कर्तव्य निष्ठ युवा' रहा, जो भारत के युवाओं में कर्तव्य, अनुशासन और राष्ट्रीय प्रतिबद्धता की भावना को दर्शाता है।
- एनसीसी पीएम रैली, महीने भर तक चलने वाले एनसीसी गणतंत्र दिवस शिविर 2026 के समापन का प्रतीक।
- इस वर्ष देश भर से 2,406 एनसीसी कैडेटों ने शिविर में भाग लिया। इनमें 898 छात्रा कैडेट भी शामिल थीं। रैली में 21 अन्य देशों के 207 युवा और अधिकारी भी शामिल हुए।
- रैली में एनसीसी कैडेट, राष्ट्रीय रंगशाला और राष्ट्रीय सेवा योजना के सदस्यों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ राष्ट्र निर्माण, सामाजिक सेवा और चरित्र विकास में युवाओं की भूमिका को प्रदर्शित किया।



हमारे देश में युवाओं के जो अचीवमेंट्स हैं, उन्हें पूरी दुनिया सराह रही है। इन युवाओं के कारण ही भारत दुनिया में इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बैकबोन बन गया है। अब इन्हीं नौजवानों की शक्ति से स्टार्टअप, स्पेस, डिजिटल टेक्नोलॉजी, हर डोमेन में एक नया रिवोल्यूशन शुरू हुआ है।

- नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री



प्रधानमंत्री का पूरा कार्यक्रम देखने के लिए QR कोड स्कैन करें।



हमारे संस्कार हैं, यही हमारा स्वभाव है। मातृभूमि के प्रति अपार श्रद्धा और कर्मभूमि के प्रति अप्रतिम समर्पण, ये हमारी विरासत है।

युवाओं को फिटनेस का मंत्र

युवाशक्ति का बहुत बड़ा टेस्ट यह है कि हम आने वाले समय में कितने अधिक फिट होंगे। फिटनेस केवल कुछ मिनट्स के व्यायाम तक सीमित नहीं है। यह हमारे स्वभाव में भी आनी चाहिए। खानपान से लेकर दिनचर्या तक एक अनुशासित जीवनशैली भी आवश्यक है। एनसीसी फिट इंडिया कैम्पेन को आगे बढ़ा रहा है। एनसीसी के कैडेट्स ने स्पोर्ट्स में भी अच्छा प्रदर्शन किया है। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं से अपील की... अपने खाने के तेल में कमी लाने का प्रयास करें। मैंने कुछ समय पहले खाने में तेल की मात्रा 10 प्रतिशत कम करने का आग्रह किया था। आज आप सभी युवाओं से मैं फिर वो आग्रह दोहराता हूँ।

पीएम मोदी का एनसीसी से मजबूत हुआ नेशन फर्स्ट का भाव

राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी ऑपरेशन सिंदूर के महत्वपूर्ण घड़ी में एनसीसी कैडेट्स ने अपनी जिम्मेदारियां बखूबी संभालीं। किसी ने सेनाओं की तैयारियों में सहयोग दिया, किसी ने रक्तदान शिविर लगाए। किसी ने प्राथमिक चिकित्सा शिविर के माध्यम से सेवा की। एनसीसी में परेड ग्राउंड की ट्रेनिंग के साथ ही नेशन फर्स्ट के विचार प्रवाह की भी ट्रेनिंग होती है। एनसीसी से मिली यही देशभक्ति और नेतृत्व मुश्किल समय में देश के प्रति पूरी शक्ति से काम करने की प्रेरणा देती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जब मैं एनसीसी में था, तब मेरा भी नेशन फर्स्ट का भाव ऐसे ही मजबूत हुआ था। आज मैं आपको भी एनसीसी में यही सीखते देख रहा हूँ, गर्व अनुभव कर रहा हूँ। ■



INDIA ENERGY WEEK
27 - 30 JANUARY 2026
ONGC ATI | GOA, INDIA



भारत का नया ऊर्जा विजन

सिर्फ ऊर्जा सुरक्षा नहीं... आत्मनिर्भरता का मिशन

भविष्य की जरूरतों और चुनौतियों को देखते हुए भारत अब सिर्फ ऊर्जा सुरक्षा नहीं बल्कि ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में काम कर रहा है। भारत में ऊर्जा क्षेत्र में अपार अवसर है, यही वजह है कि 27-30 जनवरी तक गोवा में आयोजित भारत ऊर्जा सप्ताह 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक प्रतिनिधियों से मेक इन इंडिया, इनोवेट इन इंडिया, स्केल विद इंडिया, इन्वेस्ट इन इंडिया का किया आह्वान...

भारत में ऊर्जा आत्मनिर्भरता अब कोई विकल्प नहीं बल्कि एक आर्थिक, रणनीतिक और भू-राजनीतिक आवश्यकता बन गई है। यही वजह है कि भारत हरित और स्वच्छ ऊर्जा को न सिर्फ तेजी से अपना रहा है बल्कि उत्पादन क्षमता के बड़े लक्ष्य रख, उसे समय से पहले हासिल भी कर रहा है। भारत ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के मिशन पर है और विदेशी ईंधन पर निर्भरता कम कर रहा है। ऊर्जा के क्षेत्र में साझेदारी और निवेश आकर्षित करने पर भी काम किया जा रहा है। भारत ऊर्जा क्षेत्र का एक ऐसा इकोसिस्टम विकसित कर रहा है

जो देश की स्थानीय मांग को पूरा कर सके और कम लागत वाली रिफाइनिंग एवं परिवहन संबंधी समस्याओं को दूर करके दुनिया के लिए निर्यात को और प्रतिस्पर्धी बना सके।

भारत आज हर सेक्टर में वैश्विक साझेदारी बढ़ाने की दिशा में लगातार काम कर रहा है। इसी साझेदारी को बढ़ाने की दिशा में आयोजित भारत ऊर्जा सप्ताह 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत में एनर्जी वैल्यू चैन से जुड़े हुए अलग-अलग क्षेत्रों में निवेश की बहुत संभावनाएं हैं। भारत ने अपने एक्सप्लोरेशन सेक्टर को काफी ओपन कर दिया है। डीप-सी एक्सप्लोरेशन से



भारत आज रिफॉर्म एक्सप्रेस पर सवार है। हर सेक्टर में तेजी से रिफॉर्म कर रहा है। डोमेस्टिक हाइड्रोकार्बन को सशक्त करने के लिए रिफॉर्म किए जा रहे हैं। ग्लोबल कोलैबोरेशन के लिए ट्रांसपेरेंट और इन्वेस्टर फ्रेंडली एनवायरमेंट तैयार किया जा रहा है। हमने एक्सप्लोरेशन सेक्टर में नो-गो एरिया बहुत कम कर दिया है।

**-नरेंद्र मोदी,
प्रधानमंत्री**



प्रधानमंत्री का पूरा कार्यक्रम देखने के लिए QR कोड स्कैन करें।



भारत के ऊर्जा क्षेत्र में निवेश फायदेमंद

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत ऊर्जा सप्ताह 2026 में शामिल हुए 125 देशों के प्रतिनिधियों से कहा है कि भारत ऊर्जा क्षेत्र में निवेश को बहुत फायदेमंद बनाता है। देश में बहुत बड़ी शोधन क्षमता मौजूद है, भारत इस मामले में विश्व में दूसरे स्थान पर है और जल्द ही पहले स्थान पर होगा। आज भारत की रिफाइनिंग क्षमता करीब 260 एमएमटीपीए है जिसे 300 एमएमटीपीए के ऊपर ले जाने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। भारत ने कुल ऊर्जा मांग का 15 फीसदी लिक्विफाइड नेचुरल गैस (एलएनजी) से पूरा करने का लक्ष्य रखा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि एलएनजी के पूरे वैल्यू चेन पर काम करने की आवश्यकता है। एलएनजी ट्रांसपोर्टेशन के लिए जिन वेसल्स की जरूरत है, उन्हें भारत में ही बनाने पर काम कर रहे हैं। हाल ही में भारत में शिप बिल्डिंग के लिए 70 हजार करोड़ रुपये का प्रोग्राम शुरू किया गया है। एलएनजी के ट्रांसपोर्टेशन के लिए भारत में बहुत बड़ी पाइपलाइन की भी अब जरूरत है।

दुनिया के 150 से ज्यादा देशों तक भारत का निर्यात कवरेज

भारत ऊर्जा क्षेत्र के लिए बहुत बड़े अवसरों की धरती है। भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई बड़ी अर्थव्यवस्था है जिससे ऊर्जा उत्पादों की डिमांड लगातार बढ़ रही है। इसके अलावा भारत दुनिया की मांग पूरी करने के लिए भी बेहतरीन अवसर उपलब्ध कराता है। आज भारत दुनिया में पेट्रोलियम उत्पाद के शीर्ष 5 निर्यातकों में से एक है। दुनिया के 150 से ज्यादा देशों तक निर्यात कवरेज है। प्रधानमंत्री मोदी ने निवेशकों से कहा कि भारत की यह क्षमता बहुत काम आने वाली है। भारत ऊर्जा सप्ताह 2026 का प्लेटफॉर्म साझेदारी को एक्सप्लोर करने का उत्तम स्थान है।

जुड़ा मिशन भी उन्हीं में है। भारत इस दशक के अंत तक अपने तेल और गैस के क्षेत्र में निवेश को 100 अरब डॉलर तक ले जाने का प्रयास कर रहा है जिसके दायरे को 10 लाख वर्ग किलोमीटर

तक विस्तार दिए जाने का लक्ष्य है। इसी सोच के साथ हमारे 170 से अधिक ब्लॉक अवार्ड किए जा चुके हैं। अंडमान निकोबार का बेसिन भी देश के लिए नेक्स्ट हाइड्रोकार्बन होप बन रहा है। ■



रणनीतिक साझेदारी से विकास को रफ्तार

पिछले कुछ वर्षों में संयुक्त अरब अमीरात और भारत के संबंधों ने नई ऊंचाइयों को छुआ है। इसी क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान 19 जनवरी को भारत की यात्रा पर आए। कुछ घंटों की इस यात्रा में दोनों देशों के बीच हुए कई महत्वपूर्ण समझौते...

भारत और संयुक्त अरब अमीरात, रणनीतिक साझेदारी, व्यापार, निवेश, ऊर्जा, रक्षा और नवाचार के क्षेत्रों में सहयोग को लगातार मजबूती दे रहे हैं। संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के राष्ट्रपति की यह यात्रा केवल औपचारिक शिष्टाचार नहीं, बल्कि साझा समृद्धि, तकनीकी सहयोग और नागरिक संबंधों को और सशक्त करने में निर्णायक कदम है। दोनों देशों के संबंधों की महत्ता इससे भी समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं दिल्ली के हवाई अड्डे पर यूएई के राष्ट्रपति का स्वागत करने पहुंचे। यह यात्रा दोनों देशों की मजबूत मित्रता के प्रति महत्व को दर्शाती है। दोनों देशों के संबंध की ऊंचाई को इससे भी समझ सकते हैं कि पिछले 10 वर्षों में शेख मोहम्मद बिन जायद

अल नाहयान की भारत की यह पांचवी यात्रा थी, जबकि राष्ट्रपति के रूप में तीसरी आधिकारिक यात्रा रही।

बैठक के बाद दोनों नेताओं ने संयुक्त वक्तव्य में वर्ष 2022 में व्यापक आर्थिक समझौते (सीडीपीए) पर हस्ताक्षर के बाद से व्यापार और आर्थिक सहयोग में हुई वृद्धि का स्वागत किया। द्विपक्षीय व्यापार में हुई प्रगति को रेखांकित भी किया। वित्त वर्ष 2024-25 में दोनों देशों के बीच 100 बिलियन डॉलर तक व्यापार हुआ है, जिसे वर्ष 2032 तक दोगुना कर 200 बिलियन डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। दोनों नेताओं ने भारत-यूएई मित्रता के स्थायी प्रतीक के रूप में अबू धाबी में एक हाउस ऑफ इंडिया स्थापित करने का निर्णय लिया है। सांस्कृतिक समझ को और गहरा



महत्वपूर्ण घोषणाएं

- भारत में सुपरकंप्यूटिंग क्लस्टर की स्थापना होगी।
- 2032 तक द्विपक्षीय व्यापार को 200 अरब अमेरिकी डॉलर तक करने का लक्ष्य।
- द्विपक्षीय असैन्य परमाणु सहयोग को बढ़ावा देना।
- गुजरात की गिफ्ट सिटी में यूएई कंपनियों-फर्स्ट अबू धाबी बैंक (एफएबी) और डीपी वर्ल्ड के कार्यालय एवं संचालन की स्थापना।
- डिजिटल/डेटा एंबेसी की स्थापना की संभावना का पता लगाना।
- अबू धाबी में 'हाउस ऑफ इंडिया' की स्थापना।
- युवा आदान-प्रदान को बढ़ावा देना।



प्रधानमंत्री का पूरा कार्यक्रम देखने के लिए QR कोड स्कैन करें।



संयुक्त अरब अमीरात ने 2026 में भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता की सफलता के लिए अपना पूर्ण समर्थन व्यक्त किया। वहीं भारतीय पक्ष ने 2026 संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन के लिए अपना समर्थन दिया, जिसकी सह-मेजबानी 2026 के अंत में यूएई द्वारा की जाएगी।

करने के उद्देश्य से जन केंद्रित संबंधों को जारी रखने पर सहमति बनी। भारत-यूएई साझेदारी की आधारशिला के रूप में शिक्षा की पहचान की गई है। संयुक्त अरब अमीरात में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली और भारतीय प्रबंधन संस्थान, अहमदाबाद के ऑफशोर कैम्पस के खुलने और शैक्षणिक संस्थानों के बीच संबंधों को बढ़ावा देने को प्रोत्साहित करने का निर्णय लिया गया है। इसमें स्कूल और कॉलेजों में नवाचार एवं टिंकरिंग लैब के विस्तार में सहयोग भी शामिल होगा।

दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय ऊर्जा साझेदारी की मजबूती पर संतोष व्यक्त किया। भारत की ऊर्जा सुरक्षा में संयुक्त अरब अमीरात के योगदान को भी रेखांकित किया गया। हिंदुस्तान पेट्रोलियम

कॉर्पोरेशन लिमिटेड और एडीएनओसी गैस के बीच 2028 से शुरू होने वाले 0.5 मिलियन टन प्रतिवर्ष लिक्विफाइड नेचुरल गैस की आपूर्ति के लिए 10 वर्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किया गया। दोनों देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति गहरे सम्मान तथा रणनीतिक स्वायत्तता के महत्व पर बल दिया गया। निरंतर एवं सुदृढ़ द्विपक्षीय रक्षा-सुरक्षा सहयोग को व्यापक रणनीतिक साझेदारी के एक मुख्य स्तंभ के रूप में स्वीकार किया गया। सीमा पार आतंकवाद सहित सभी रूपों और अभिव्यक्तियों में आतंकवाद की स्पष्ट रूप से निंदा की गई और कहा गया कि किसी भी देश को उन लोगों को सुरक्षित पनाहगाह प्रदान नहीं करनी चाहिए जो आतंकवादी कृत्यों का वित्तपोषण, योजना, समर्थन या उसे अंजाम देते हैं। ■



“मदर ऑफ ऑल डील्स”



प्रधानमंत्री का पूरा कार्यक्रम देखने के लिए QR कोड स्कैन करें।

भारत-यूरोपीय यूनियन रिश्तों में नए युग का शंखनाद

आज वैश्विक अर्थव्यवस्था में बड़े पैमाने पर उथल-पुथल हो रही है, ऐसे में भारत और यूरोपीय संघ के बीच हुआ इतिहास का सबसे बड़ा मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्थिरता लाने में अहम भूमिका निभाएगा। यूरोपीय संघ अभी भारत के सबसे बड़े व्यापारिक साझेदारों में से एक है। भारत और यूरोपीय संघ का द्विपक्षीय व्यापार निरंतर वृद्धि के साथ 2024-25 में 11.5 लाख करोड़ रुपये का रहा है। इस समझौते से न सिर्फ द्विपक्षीय व्यापार सुगम और प्रतिस्पर्धी होगा बल्कि निवेश, नवाचार, आपूर्ति शृंखला और रोजगार के भी खुलेंगे नए अवसर...

विश्व की दूसरी और चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के बीच हुआ ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते कई दृष्टि में महत्वपूर्ण है। इस समझौते से भारत और यूरोपीय संघ की दो अरब आबादी को तो लाभ मिलेगा ही लेकिन विश्व के दूसरे देशों पर भी इसका व्यापक असर होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपीय आयोग

की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन की मौजूदगी में यह ऐतिहासिक समझौता हुआ। इस समझौते से विश्व की दो सबसे बड़ी लोकतांत्रिक शक्तियों ने अपने संबंधों में एक निर्णायक अध्याय जोड़ा है।

भारत-यूरोपीय संघ एफटीए से आर्थिक और रणनीतिक संबंधों को मजबूती मिलेगी। देश के किसानों और लघु उद्योगों के लिए यूरोपीय बाजार तक पहुंच आसान होगी। विनिर्माण क्षेत्र में नए अवसरों का

सृजन होगा। सेवा क्षेत्र के बीच सहयोग को और मजबूती मिलेगी, रोजगार सृजित होंगे, पेशेवर प्रतिभाओं, छात्रों और शोधकर्ताओं के लिए गतिशीलता बढ़ेगी। इस समझौते से व्यापार, निवेश और नवाचार को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही भारत के स्टूडेंट्स, कामगार और पेशेवर के लिए यूरोपियन यूनियन में नए अवसर खुलेंगे।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में भारत और यूरोपीय संघ के बीच संबंधों में प्रगति हुई है। इसमें यूरोपीयन यूनियन में रह रहे 8 लाख से अधिक भारतीय सक्रिय योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में दोनों के बीच 180 बिलियन यूरो का व्यापार है। दोनों के बीच स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी, स्वच्छ ऊर्जा और डिजिटल गवर्नेंस से लेकर डेवलपमेंट पार्टनरशिप के क्षेत्र तक सहयोग के नए आयाम स्थापित हुए हैं। भारत ने अपने इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा मुक्त व्यापार समझौता किया है। 27 जनवरी की यह तारीख सुखद संयोग है कि भारत ने यूरोपीयन यूनियन के 27 देशों के साथ यह समझौता किया है। यह ऐतिहासिक समझौता किसानों, छोटे उद्योगों की यूरोपियन मार्केट तक पहुंच आसान बनाएगा। मैन्युफैक्चरिंग में नए अवसर और सर्विस सेक्टर के बीच सहयोग को मजबूत करेगा। यही नहीं एफटीए भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच इन्वेस्टमेंट को बूस्ट करेगा एवं इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप बनाएगा। वैश्विक स्तर पर स्प्लाइ चैन को मजबूत करने के साथ यह समझौता साझा समृद्धि का नया ब्लू प्रिंट भी होगा।

पीएम मोदी ने कहा कि रक्षा और सुरक्षा सहयोग किसी भी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की नींव होती है जिसे भारत और यूरोपीय संघ ने औपचारिक रूप दिया। इससे काउंटर टेरेरिज्म, मैरीटाइम और साइबर सिक्योरिटी में साझेदारी और गहरी होगी। इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में दोनों पक्षों के सहयोग का दायरा बढ़ेगा। पीएम मोदी ने कहा कि राष्ट्रों के संबंधों में कभी-कभी ऐसा क्षण आता है, जब इतिहास स्वयं कहता है, यहीं से दिशा बदली, यहीं से एक नए युग की शुरुआत हुई। भारत और यूरोपियन की यह ऐतिहासिक समिट वही क्षण है।

10 वर्षों में व्यापार हुआ दोगुना

यूरोपीय संघ भारत के सबसे बड़े व्यापारिक भागीदारों में से एक है। पिछले 10 वर्षों में भारत और यूरोपीय संघ का व्यापार दोगुना होकर 180 बिलियन यूरो तक पहुंच गया है। भारत में 6,000 से अधिक यूरोपीय कंपनियां काम कर रही हैं। यूरोपियन यूनियन से भारत में 120 बिलियन यूरो से अधिक का निवेश है। भारत की 1,500 कंपनियां यूरोपियन यूनियन में मौजूद हैं। वहां भारतीय निवेश लगभग 40 बिलियन यूरो तक पहुंच चुका है।



तीन प्राथमिकताओं पर पीएम मोदी का फोकस

पहला : आज विश्व में व्यापार, टेक्नोलॉजी और क्रिटिकल मिनरल्स को वेपनाइज्ड किया जा रहा है। ऐसे में साथ मिलकर अपनी निर्भरताओं को डी-रिस्क करने की आवश्यकता है।

दूसरा : भारत और यूरोपियन यूनियन दोनों का फोकस डिफेंस इंडस्ट्रीज और फ्रंटियर टेक्नोलॉजी पर रहा है। पीएम मोदी ने बिजनस फोरम में डिफेंस, स्पेस, टेलीकॉम और एआई जैसे क्षेत्रों में साझेदारी बढ़ाने का आग्रह किया है।

तीसरा : क्लीन एंड सस्टेनेबल प्लूचर दोनों की प्राथमिकता है। ग्रीन हाइड्रोजन से लेकर सौर एनर्जी और स्मार्ट ग्रिड, हर क्षेत्र में जॉइंट रिसर्च और इन्वेस्टमेंट बढ़ाना चाहिए।

22वां एफटीए भागीदार

यूरोपीय संघ भारत का 22वां एफटीए भागीदार बना है। केंद्र सरकार ने 2014 से मॉरीशस, संयुक्त अरब अमीरात, ब्रिटेन, ईएफटीए, ओमान और ऑस्ट्रेलिया के साथ व्यापार सौदों पर हस्ताक्षर किए हैं। 2025 में भारत ने ओमान और यूके के साथ व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए और न्यूजीलैंड के साथ व्यापार समझौते की घोषणा की।

बेहतर बाजार होगा उपलब्ध

भारत और यूरोपीय संघ के संयुक्त बाजार का अनुमानित मूल्य 2091.6 लाख करोड़ रुपये से अधिक है। व्यापार मूल्य के हिसाब से भारत के 99 प्रतिशत से अधिक निर्यात के लिए यह मुक्त व्यापार समझौता पहले से बेहतर बाजार पहुंच प्रदान करेगा।

भारत की यूरोपीय बाजारों तक पहुंच

- भारत ने विशेष रूप से 99.5% व्यापार मूल्य को कवर करते हुए 97% टैरिफ लाइनों पर यूरोपीय बाजारों में प्राथमिकता वाली पहुंच बनाई है।
- भारत के 90.7% निर्यात के अंतर्गत आने वाली 70.4% टैरिफ लाइनों से कपड़ा, चमड़ा और जूते, चाय, कॉफी, मसाले, खेल के सामान, खिलौने और रत्न जैसे महत्वपूर्ण श्रम-प्रधान क्षेत्रों के लिए तत्काल शुल्क हटा दिया जाएगा।
- भारत के निर्यात के 2.9% हिस्से के अंतर्गत आने वाली 20.3% टैरिफ लाइनों पर कुछ समुद्री उत्पादों, प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों, हथियारों और गोला-बारूद आदि के लिए 3 और 5 वर्षों में शून्य शुल्क की सुविधा होगी।
- भारत के निर्यात के 6% हिस्से के अंतर्गत आने वाली 6.1% टैरिफ लाइनों को कुछ पोल्ट्री उत्पादों, संरक्षित सब्जियों, बेकरी उत्पादों आदि के लिए टैरिफ में कमी के माध्यम से या कारों, स्टील आदि के लिए टीआरव्यू के माध्यम से प्राथमिक रूप से पहुंच प्राप्त होगी।

वस्तुओं और सेवाओं में द्विपक्षीय व्यापार पिछले कुछ वर्षों में लगातार बढ़ा है। 2024-25 में यूरोपीय संघ के साथ भारत का द्विपक्षीय व्यापार 11.5 लाख करोड़ रुपये था जिसमें 6.4 लाख करोड़ रुपये का निर्यात और 5.1 लाख करोड़ रुपये का आयात किया जा रहा था। यूरोपीय संघ से भारत को होने वाले निर्यात में मशीनरी, परिवहन उपकरण और रसायन शामिल हैं, वहीं भारत से होने वाले आयात में मशीनरी, रसायन, बेस मेटल, खनिज उत्पाद और कपड़ा शामिल हैं। सेवा क्षेत्र में भारत-यूरोपीय संघ का व्यापार 2024 में 7.2 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया।

गुणवत्ता से दिल जीतें, लंबे समय तक रहता है इसका प्रभाव

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी प्रकार के उत्पादकों से कहा है कि भारत-यूरोपियन यूनियन के बीच ऐतिहासिक समझौते से देश के उद्योग-धंधे में शामिल, मैन्युफैक्चरर के लिए बड़ा बाजार खुल गया है। अब सस्ते में माल पहुंच जाएगा। इस अवसर का सबसे पहला



भारत और European Union का सहयोग एक “पार्टनरशिप फॉर global good” है। इंडो-पैसिफिक से लेकर कैरेबियन तक, trilateral projects को विस्तार देंगे। इससे सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, स्वच्छ ऊर्जा और महिला सशक्तीकरण को ठोस समर्थन मिलेगा। साथ मिलकर IMEC कॉरिडोर, ग्लोबल ट्रेड और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की एक प्रमुख कड़ी के रूप में स्थापित करेंगे।

-नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री

मंत्र यही है कि क्वालिटी पर बल दें। उत्तम से उत्तम क्वालिटी लेकर बाजार में जाएं। उत्तम से उत्तम क्वालिटी लेकर जाने से यूरोपियन यूनियन के 27 देशों के खरीदारों से सिर्फ पैसे ही नहीं कमाते बल्कि क्वालिटी के कारण उनका दिल भी जीत लेते हैं। लंबे अरसे तक इसका प्रभाव रहता है।

होल ऑफ द सोसाइटी पार्टनरशिप

भारत और यूरोपीय संघ के बीच हुई साझेदारी को ‘होल ऑफ द सोसाइटी पार्टनरशिप’ बनाने की बात कही गई। इसी सोच के साथ मुक्त व्यापार समझौता किया गया। इससे भारत के लेबर इंटेसिव उत्पादों को यूरोपीय संघ के बाजार में आसानी से पहुंच मिलेगा। इसमें विशेष तौर पर टेक्सटाइल, जेम्स एंड ज्वेलरी, ऑटो पार्ट्स और इंजीनियरिंग गुड्स शामिल हैं। फ्रूट्स, वेजिटेबल, प्रोसेस्ड फूड और मरीन प्रोडक्ट्स से नए अवसर बनेंगे। इसका सीधा लाभ देश के किसानों, मछुआरों और सर्विस सेक्टर को होगा। आईटी, एजुकेशन, ट्रेडिशनल मेडिसिन और बिजनेस सर्विस भी लाभान्वित होंगे। ■



Narendra Modi @narendramodi

The Union Budget reflects the aspirations of 140 crore Indians. It strengthens the reform journey and charts a clear roadmap for Viksit Bharat.

#ViksitBharatBudget



Rajnath Singh @rajnathsingh

Under the visionary leadership of PM Shri @narendramodi, India's journey towards a Viksit Bharat continues to gather momentum. In this spirit, I congratulate Finance Minister Smt. @nsitharaman, for presenting a budget that seeks to "transform aspiration into achievement" and "potential into performance". This "Yuva Shakti-driven Budget" will further strengthen PM Modi's vision of an Aatmanirbhar and Viksit Bharat.



Amit Shah @AmitShah

बजट 2026-27 के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी जी ने सिद्ध किया है कि आत्मनिर्भर और विकसित भारत केवल एक नारा नहीं, बल्कि हमारी सरकार का संकल्प है। इस बजट में न सिर्फ हर क्षेत्र, हर वर्ग और हर नागरिक को सशक्त बनाने का एक स्पष्ट ब्लूप्रिंट है, बल्कि उसे प्रोत्साहन देने का एक जमीनी विजन भी है, जो उसे हर कदम पर मदद करेगा। #ViksitBharatBudget एक ऐसे भारत के निर्माण का विजन है, जो विश्व में हर क्षेत्र में अग्रणी हो।



Nitin Gadkari @nitin_gadkari

#UnionBudget2026 outlines a decisive roadmap centred on farmers, youth, and MSMEs, strengthening the foundations of inclusive growth, innovation, and capital investment as India progresses towards #ViksitBharat2047.



Shivraj Singh Chouhan @ChouhanShivraj

वित्त मंत्री श्रीमती @nsitharaman जी द्वारा प्रस्तुत बजट अमृत काल का वह अमृत-कलश है, जिससे समृद्धि की सरिता बहेगी और विकसित भारत के विराट संकल्प की सिद्धि होगी।

यह बजट अर्थ से सामर्थ्य तक, अंत्योदय से अभ्युदय तक और साधन से समाधान तक की एक स्वर्णिम यात्रा है। इससे खेतों में हरियाली, खलिहानों में खुशहाली और हर चेहरे पर लाली आएगी।



Manohar Lal @mlkhattar

यह विकसित भारत के संकल्प का विजयिनी बजट है...

देश के संसाधनों, सामर्थ्य और समृद्धि को ध्यान में रखते हुए Ease of Doing Business और Ease of Living की दिशा में चलकर लोगों के जीवन को सरल, सहज और समृद्ध करने वाला बजट है।

भारत-ईयू ने महाशक्तियों को दिया उनके विकल्प का संदेश

यूनायटेड किंगडम और यूरोपीय संघ ने भारत को एक विकल्प प्रस्तुत किया है जो उनके विकास और प्रगति के लिए है। भारत-ईयू ने महाशक्तियों को दिया उनके विकल्प का संदेश।

भारत एक सशक्त राष्ट्र के रूप में अपनी पहचान बना रहा है: मोदी

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत एक सशक्त राष्ट्र के रूप में अपनी पहचान बना रहा है।

ईएम मोदी ने सुविधायन को ही संकेत

ईएम मोदी ने सुविधायन को ही संकेत दिया कि भारत एक सशक्त राष्ट्र के रूप में अपनी पहचान बना रहा है।

स्वदेशी कवच

भारत-ईयू ने महाशक्तियों को दिया उनके विकल्प का संदेश। भारत-ईयू ने महाशक्तियों को दिया उनके विकल्प का संदेश।

आत्मनिर्भर भारत को मिलेगी गति, 140 करोड़ भारतीयों की उम्मीदों पर खरा: मोदी

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत को मिलेगी गति, 140 करोड़ भारतीयों की उम्मीदों पर खरा: मोदी

एटा का 'पटना पक्षी अभयारण्य' अब रामसर साइट

एटा का 'पटना पक्षी अभयारण्य' अब रामसर साइट है।

भारत 2026-27 की योजना

- 53.47 लाख करोड़ का बजट
- 2300 करोड़ का पूंजीगत व्यय
- 1.5 लाख करोड़ का पूंजीगत व्यय

मुख्य बिंदु

- कृषि और किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए
- युवा शक्ति को बढ़ावा देने के लिए
- महामोटावा को नियंत्रित करने के लिए

मुख्य बिंदु

- कृषि और किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए
- युवा शक्ति को बढ़ावा देने के लिए
- महामोटावा को नियंत्रित करने के लिए

बीटिंग रिट्रीट समारोह

विजय चौक पर

परंपरा, पराक्रम और प्रौद्योगिकी का संगम



नई दिल्ली के विजय चौक पर 29 जनवरी 2026 की शाम 'बीटिंग रिट्रीट' समारोह में मधुर भारतीय धुन और सैनिकों के लयबद्ध कदमताल के उत्कृष्ट प्रदर्शन ने गर्व की अनुभूति कराई। इस मौके पर ऑपरेशन सिंदूर, 'वंदे मातरम्' के 150 वर्ष, भारत की नारी शक्ति की क्रिकेट उपलब्धि, अश्वि ड्रोन, भैरव बटालियन और प्राचीन 'गरुड़ व्यूह' युद्ध संरचना को सशक्त रूप से दर्शाया गया। बीटिंग रिट्रीट की यह परेड, 77वें गणतंत्र दिवस समारोह के समापन का प्रतीक और समृद्ध सैन्य विरासत का रहा विशिष्ट प्रदर्शन...



'बीटिंग रिट्रीट' समारोह
पूरा देखने के लिए QR
कोड स्कैन करें।

“
ऐसे समय में जब हम वंदे
मातरम् की 150वीं वर्षगांठ
मना रहे हैं, तब हमारी
सेनाओं द्वारा बीटिंग रिट्रीट
2026 में इसकी प्रस्तुति
खासतौर पर विशेष है।

-नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री



न्यू इंडिया
समाचार
पाक्षिक

आर.एन.आई, DELHIN/2020/78812, 16-28 फरवरी, 2026
आरएनआई DELHIN/2020/78812 (प्रकाशन तिथि- 5 फरवरी 2026, कुल पृष्ठ-64)

प्रधान संपादक
धीरेन्द्र ओझा, प्रधान महानिदेशक
पत्र सूचना कार्यालय, नई दिल्ली

प्रकाशक
कंचन प्रसाद
महानिदेशक, केंद्रीय संचार ब्यूरो

कमरा संख्या-278, केंद्रीय संचार ब्यूरो
सूचना भवन, द्वितीय तल
नई दिल्ली- 110003 से प्रकाशित